द हिंदू रिव्यू

बैंकिंग, SSC, रेलवे, राज्य, रक्षा, पुलिस और शिक्षण परीक्षाओं के लिए उपयोगी

अप्रैल 2025

मुख्य समाचार

- पहलगाम आतंकी हमला
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
- नया पंबन पुल
- RBI मौद्रिक नीति 2025
- मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना
- यशराज भारती सम्मान पुरस्कार 2025
- लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025
- टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025

Contents

राष्ट्रीय समाचार 3
सरकारी योजनाएँ 23
अंतरराष्ट्रीय समाचार 24
बैंकिंग और फाइनेंस 26
अर्थव्यवस्था और व्यापार 27
समझौता ज्ञापन एवं समझौते 29
नियुक्तियाँ और इस्तीफे 30
पुरस्कार 32
शिखर सम्मेलन, कार्यक्रम और सम्मेलन 33
इंडेक्स 34
रक्षा 35
विज्ञान प्रौद्योगिकी 37
खेल 38
पुस्तक एवं लेखक 41
निधन 41
महत्वपूर्ण दिवस 42
विविध 44
स्थैतिक टेकअवे 44

राष्ट्रीय समाचार

माह की महत्वपूर्ण खबरें

संसद ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया

संसद ने 26 मार्च 2025 को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिससे भारत के बैंकिंग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। यह विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और अब इसे राज्यसभा में ध्वनि मत से मंजूरी मिली। इस संशोधन के तहत, बैंक खाता धारक अब चार नामांकित व्यक्ति (नोमिनी) जोड़ सकते हैं, जिससे वित्तीय योजना में अधिक लचीलापन आएगा। इसके अलावा, 'महत्वपूर्ण हित' (Substantial Interest) की परिभाषा को संशोधित कर इसकी सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई, जो लगभग छह दशकों के बाद हुआ बड़ा बदलाव है। विधेयक में सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल, वैधानिक लेखा परीक्षक (Auditor) के पारिश्रमिक, तथा नियामक अनुपालन रिपोर्टिंग तिथियों को भी संशोधित किया गया है।

मुख्य प्रावधान

1. चार नामांकित व्यक्ति (Nominee) जोड़ने की सुविधा

- अब बैंक खाता धारक चार नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं, जबकि पहले केवल एक ही नोमिनी की अनुमति थी।
- यह नियम कैश और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों पर लागू होगा।
- लॉकर खातों के लिए सिर्फ संयुक्त नामांकन (Simultaneous Nomination) की अनुमति दी गई है।

2. 'महत्वपूर्ण हित' की नई परिभाषा

- बैंक में 'Substantial Interest' की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई है।
- यह बदलाव 60 वर्षों के बाद किया गया, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में बड़े निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

3. सहकारी बैंकों में सुधार

- निदेशकों का कार्यकाल (चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर) 8 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया।
- अब राज्य सहकारी बैंकों के बोर्ड में केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशक भी शामिल हो सकते हैं।

4. बैंकिंग क्षेत्र में निगरानी और अनुपालन सुधार

- बैंकों को लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक (Auditor Remuneration) तय करने में अधिक लचीलापन दिया गया।
- नियामक रिपोर्टिंग की तिथियां अब हर महीने की 15वीं और अंतिम तिथि होंगी, पहले यह दूसरे और चौथे शुक्रवार को होती थी।

5. जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों (Wilful Defaulters) पर कड़ी कार्रवाई

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीए (Non-Performing Assets) को कम करने और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
- पिछले 5 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 112 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की गई।

6. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष में ₹1.41 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा अर्जित किया।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में और अधिक लाभ वृद्धि की उम्मीद है।

7. व्यापक बैंकिंग सुधार

- यह संशोधन पांच अलग-अलग बैंकिंग कानूनों को प्रभावित करता है, जिससे यह बैंकिंग इतिहास में एक ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है।

यह विधेयक भारत के बैंकिंग क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, लचीला और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तराखंड में सरकार ने बदले 15 स्थानों के नाम

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। यह निर्णय जनभावनाओं और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप लिया गया है। सरकार का उद्देश्य महान ऐतिहासिक व्यक्तियों को सम्मान देना और राज्य के लोगों में प्रेरणा जगाना है।

संस्कृति और जनभावना से जुड़ा निर्णय

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन स्थानों के नए नाम उन महापुरुषों के सम्मान में रखे गए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राज्य सरकार के अनुसार, यह बदलाव जनसामान्य की मांग और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर किया गया है।

उत्तराखंड में बदले गए स्थानों की सूची

चार जिलों—हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में स्थानों के नाम बदले गए हैं।

हरिद्वार जिले में बदले गए नाम:

- औरंगजेबपुर → शिवाजी नगर
- गाजीवाली → आर्य नगर
- चांदपुर → ज्योतिबा फुले नगर
- मोहम्मदपुर जाट → मोहनपुर जाट
- खानपुर कुर्सली → अंबेडकर नगर
- इंद्रिशपुर → नंदपुर
- खानपुर → श्रीकृष्णपुर
- अकबरपुर फजलपुर → विजय नगर

देहरादून जिले में बदले गए नाम:

- मियांवाला → रामजी वाला
- पीरवाला → केशरी नगर
- चांदपुर खुर्द → पृथ्वीराज नगर
- अब्दुल्ला नगर → दक्ष नगर

नैनीताल जिले में बदले गए नाम:

- नवाबी रोड → अटल मार्ग
- पंचक्की से आईटीआई रोड → गुरु गोलवलकर मार्ग

ऊधम सिंह नगर जिले में बदला गया नाम:

- सुल्तानपुर पट्टी नगर पालिका → कौशल्या पुरी

नाम परिवर्तन के पीछे के प्रमुख कारण:

1. ऐतिहासिक व्यक्तियों को सम्मान – शिवाजी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों के नाम से स्थानों का नामकरण, उनके योगदान का सम्मान करने के लिए किया गया।
2. सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना – मुगलकालीन और औपनिवेशिक युग के नामों को हटाकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप नाम दिए गए।
3. जनभावनाओं का सम्मान – लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा नाम परिवर्तन की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने पूरा किया।
4. राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव – इस कदम को संस्कृति संरक्षण का प्रयास माना जा रहा है, हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि केवल नाम बदलने से बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे हल नहीं होंगे।

नाम परिवर्तन का प्रभाव:

- संस्कृति का पुनरुत्थान – लोगों को अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ने में मदद मिलेगी।
- शैक्षिक महत्व – नई पीढ़ी को ऐतिहासिक महापुरुषों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।
- राजनीतिक प्रभाव – सरकार को संस्कृति संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होगा।
- स्थानीय भावना का उत्थान – क्षेत्रीय गौरव और ऐतिहासिक चेतना को बल मिलेगा।

संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया

राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को 12 घंटे की विस्तृत चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। यह मंजूरी लोकसभा द्वारा 288-232 मतों से विधेयक पारित किए जाने के एक दिन बाद मिली।

भारतीय संसद ने हाल ही में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और उनकी निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विधायी उपाय पारित किए हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पर संसद के दोनों सदनों में बहस हुई और उन्हें मंजूरी दी गई। 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद शुक्रवार तड़के इसे राज्यसभा ने पारित कर दिया। पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोटों के साथ , विधेयक को उच्च सदन से मंजूरी मिली, गुरुवार को लोकसभा में 288-232 वोटों से इसे मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, राज्यसभा ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को भी 17 घंटे की बैठक के बाद पारित कर दिया, जिसे सुबह 4 बजे स्थगित कर दिया गया

प्रमुख बिंदु

विधेयक का उद्देश्य

- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है।
- इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वाले प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना तथा उनके कानूनी ढांचे को बढ़ाना है।

लोकसभा/राज्यसभा में पारित

- वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (यूएमईईडी) विधेयक रखा गया।
- मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करेगा।

संसदीय प्रक्रिया

- यह विधेयक 12 घंटे की बहस के बाद राज्यसभा में 128-95 मतों से पारित हुआ, जबकि लोकसभा में इसे 288-232 मतों से मंजूरी मिली थी।
- इस बहस में सांसदों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग तथा विवादों के समाधान में न्यायाधिकरणों की भूमिका पर चर्चा हुई।

मंत्रिस्तरीय वक्तव्य

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संसदीय बहस के दौरान विधेयक और इसके प्रावधानों का बचाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024

पृष्ठभूमि

दो विधेयक प्रस्तुत किये गये,

1. वक्फ (संशोधन) विधेयक
2. मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक

उद्देश्य

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025

- वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में चुनौतियों के समाधान के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन किया जाएगा।
- वक्फ बोर्डों के प्रशासन और दक्षता में सुधार करना।

मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024

- मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त किया जाए, जो एक पुराना औपनिवेशिक युग का कानून है।
- वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत वक्फ संपत्ति प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- पुराने कानून द्वारा उत्पन्न विसंगतियों और अस्पष्टताओं को दूर करना।

'वक्फ' का अर्थ

- इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां।
- संपत्ति की बिक्री या अन्य उपयोग निषिद्ध है।
- स्वामित्व अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है।
- वाकिफ (निर्माता) की ओर से मुतवल्ली द्वारा प्रबंधित।

'वक्फ' की अवधारणा की उत्पत्ति

- इसका इतिहास दिल्ली सल्तनत काल से जुड़ा है, जब सुल्तान मुइज़ुद्दीन सैम ग़ौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को कई गांव समर्पित किए थे।
- भारत में इस्लामी राजवंशों के उदय के साथ वक्फ संपत्तियों में भी वृद्धि हुई।
- मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913 ने भारत में वक्फ को संरक्षण प्रदान किया।

संवैधानिक ढांचा और शासन

- धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाएं संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं।
- संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस पर कानून बना सकते हैं।
- वक्फ शासन: वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित, जो 1913, 1923 और 1954 के पूर्ववर्ती कानूनों का स्थान लेता है।

वक्फ का निर्माण

द्वारा निर्मित,

- घोषणा (मौखिक या लिखित विलेख)।
- धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए भूमि का दीर्घकालिक उपयोग।
- उत्तराधिकार की एक पंक्ति के अंत के बाद दान।

सर्वाधिक वक्फ संपत्ति वाले राज्य

- उत्तर प्रदेश (27%)
- पश्चिम बंगाल (9%)
- पंजाब (9%)

वक्फ कानूनों का विकास

- 1913 अधिनियम: वक्फ विलेखों को वैध बनाया गया।
- 1923 अधिनियम: वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया।
- 1954 अधिनियम: केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई।
- 1995 अधिनियम: निर्वाचित सदस्यों और इस्लामी विद्वानों के साथ विवाद समाधान के लिए न्यायाधिकरण की शुरुआत की गई।

नये विधेयक में प्रमुख संशोधन

केंद्रीय वक्फ परिषद संरचना

- वक्फ के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।

सदस्यों में शामिल हैं

- संसद सदस्य (एमपी)
- राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति
- सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
- मुस्लिम कानून के प्रख्यात विद्वान
- नया प्रावधान: गैर-मुस्लिम सदस्य आवश्यक (दो)

वक्फ बोर्डों की संरचना

- राज्य सरकारों को प्रत्येक समूह से एक व्यक्ति को नामित करने का अधिकार देना।
- गैर-मुस्लिम सदस्य आवश्यक (दो)।
- इसमें शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्ग से एक-एक सदस्य शामिल हैं।
- दो मुस्लिम महिला सदस्यों की आवश्यकता है।

न्यायाधिकरणों की संरचना

- मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को हटा दिया गया।
- जिला न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया गया।
- संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी।

न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील

- पूर्ववर्ती अधिनियम : कोई अपील की अनुमति नहीं थी।
- नया विधेयक: न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देता है।

संपत्तियों का सर्वेक्षण

- वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की देखरेख के लिए सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर जिला कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

वक्फ के रूप में सरकारी संपत्ति

- वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी।
- कलेक्टर द्वारा राजस्व अभिलेख अद्यतन किये गये।

ऑडिट

- एक लाख रुपये से अधिक आय वाली वक्फ संस्थाओं का राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा।

केंद्रीकृत पोर्टल

- बेहतर कार्यकुशलता और पारदर्शिता के लिए केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से स्वचालित वक्फ संपत्ति प्रबंधन।

संपत्ति समर्पण

- धार्मिक आस्था रखने वाले मुसलमान (कम से कम पांच वर्ष) अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित कर सकते हैं, जिससे 2013 से पहले के नियम बहाल हो जाएंगे।

महिलाओं की विरासत

- महिलाओं को वक्फ घोषणा से पहले उत्तराधिकार प्राप्त करना होगा।
- विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान।

विधेयक की आवश्यकता

- मुकदमेबाजी को कम करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों की एकीकृत डिजिटल सूची।
- वक्फ बोर्डों में महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करके लैंगिक न्याय सुनिश्चित किया गया है।

चिंताएं

वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य

- राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया।
- चिंता यह है कि इन निकायों में मुख्य रूप से गैर-मुस्लिम लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि हिंदू और सिख बंदोबस्ती बोर्डों में ऐसे ही बोर्ड हैं।

वक्फ न्यायाधिकरणों पर प्रभाव

- वक्फ न्यायाधिकरणों से मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों को हटाने से विवाद समाधान प्रभावित हो सकता है।

वक्फ का निर्माण

- वक्फ निर्माण को कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन करने वाले मुसलमानों तक सीमित करना।
- इस पांच-वर्षीय मानदंड के पीछे तर्क के बारे में अस्पष्टता।

निष्कर्ष

- यह विधेयक भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- प्रस्तावित सुधार बेहतर प्रशासन, जवाबदेही और अधिक समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करेंगे, जिससे सभी संबंधित समुदायों को लाभ होगा।

बिम्सटेक: पूर्ण स्वरूप, सदस्य देश, उद्देश्य और क्षेत्रीय सहयोग का महत्व

छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल, 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, बिम्सटेक सदस्य देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय विकास और एकीकरण के उद्देश्य से छह प्रमुख परिणामों को मंजूरी दी, साथ ही 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण भी अपनाया।

बिम्सटेक (BIMSTEC) क्या है?

बिम्सटेक का पूर्ण रूप है बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को एक साथ लाकर आर्थिक विकास, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्थापना की तिथि: 6 जून 1997
मूल नाम: BIST-EC (Bangladesh, India, Sri Lanka, and Thailand Economic Cooperation)
वर्तमान नाम: BIMSTEC (जुलाई 2004 में पहले शिखर सम्मेलन के दौरान बदला गया)

संस्थापक सदस्य देश (1997)

1. बांग्लादेश
2. भारत
3. श्रीलंका
4. थाईलैंड

बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख प्रतिनिधि:

- अबुल हसन चौधरी (बांग्लादेश)
- सलीम इकबाल शेर्वानी (भारत)
- डी. पी. विक्रमसिंघे (श्रीलंका)
- पिटक इन्ट्रावित्यानुन्त (थाईलैंड)

सदस्यता का विस्तार

म्यांमार:

- 22 दिसंबर 1997 को शामिल हुआ
- इसके बाद नाम बदला गया – BIMST-EC

नेपाल और भूटान:

- दोनों फरवरी 2004 में शामिल हुए
- जुलाई 2004 में पहले शिखर सम्मेलन में नाम BIMSTEC रख दिया गया

वर्तमान सदस्य देश (7 देश)

1. बांग्लादेश
2. भूटान
3. भारत
4. म्यांमार
5. नेपाल
6. श्रीलंका
7. थाईलैंड

ये सभी देश बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित हैं और सामरिक व आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बिम्सटेक के मुख्य उद्देश्य

बिम्सटेक का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना और सदस्य देशों के बीच आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

विस्तृत उद्देश्य:

- आर्थिक विकास: व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, परिवहन, पर्यटन, ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर तेज़ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- सामाजिक प्रगति: सतत और समावेशी विकास के माध्यम से क्षेत्रीय जनता के जीवन स्तर को सुधारना।
- तकनीकी सहयोग: विज्ञान और तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देना और डिजिटल विकास के लिए सहयोग करना।
- कनेक्टिविटी: भौतिक, डिजिटल और जनसंपर्क आधारित कनेक्टिविटी को मजबूत करना ताकि क्षेत्रीय एकीकरण को गति मिले।
- ऊर्जा सहयोग: ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक ऊर्जा खोज, व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास में सहयोग।
- आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन: प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु संकटों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना।
- सुरक्षा व आतंकवाद विरोध: क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से मिलकर मुकाबला करना।

बिम्सटेक का महत्व

- रणनीतिक स्थान: बंगाल की खाड़ी दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ती है, जिससे बिम्सटेक इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक सेतु की भूमिका निभाता है।
- SAARC का विकल्प: SAARC में लंबे समय से गतिरोध के चलते बिम्सटेक एक अधिक सक्रिय और प्रभावी मंच बनकर उभरा है।
- विकास पर केंद्रित: यह संगठन न केवल आर्थिक विकास पर बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय सततता पर भी समान रूप से ध्यान देता है, जो इसे अन्य क्षेत्रीय संगठनों से अलग बनाता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान - मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया।

5 अप्रैल, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान , मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया । कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में आयोजित एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। यह प्रतिष्ठित सम्मान दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और सहयोग का प्रतिबिंब है।

प्रमुख बिंदु

पुरस्कार विवरण

- मिश्रा विभूषण श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था।
- इससे पहले यह सम्मान मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात को दिया जा चुका है।
- पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और नौ प्रकार के श्रीलंकाई रत्नों से सुसज्जित एक रजत पदक शामिल है।
- पदक के डिजाइन में कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा और चावल के ढेर जैसे प्रतीक अंकित हैं, जो भारत और श्रीलंका की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।

ऐतिहासिक महत्व

- पदक पर अंकित धर्म चक्र साझी बौद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है जिसने दोनों देशों की सांस्कृतिक परंपराओं को आकार दिया है।
- चावल के ढेरों से युक्त पुन कलश या औपचारिक बर्तन समृद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक है।
- नवरत्न (नौ बहुमूल्य रत्न) को कमल की पंखुड़ियों से घिरे एक ग्लोब के अंदर दर्शाया गया है।

मोदी की टिप्पणी

- मोदी ने कहा कि यह पुरस्कार भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का प्रतिबिंब है।
- उन्होंने कहा कि मिश्रा विभूषण प्राप्त करना न केवल उनके लिए बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के लिए भी सम्मान की बात है।

मोदी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान

मोदी को 15 से अधिक देशों द्वारा राजकीय सम्मान प्रदान किया गया है, जिनमें शामिल हैं,

- सऊदी अरब के राजा अब्दुल अजीज का आदेश
- फिलिस्तीन राज्य का आदेश
- संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ जायद
- ऑर्डर ऑफ फिजी
- मिस्र का नील नदी का आदेश

मार्च 2025 में, मॉरीशस ने देश की यात्रा के दौरान मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया।

समारोह विवरण

- यह समारोह कोलंबो स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में हुआ।
- राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया।

भारत-श्रीलंका ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत और श्रीलंका ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच इस तरह का पहला समझौता है। यह पहल लगभग **40** वर्षों बाद आई है, जब भारतीय शांति सेना (IPKF) को श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान तैनात किया गया था। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलंबो यात्रा और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुर कुमारा डिसानायके के साथ हुई चर्चाओं के दौरान संपन्न हुआ। यह दोनों देशों के बीच साझा रणनीतिक दृष्टिकोण और सुरक्षा व विकास के मामलों में बढ़ती परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। यह समझौता रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल सहयोग और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में केंद्रित दस प्रमुख समझौतों के व्यापक ढांचे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच साझेदारी को और गहरा करना है।

भारत-श्रीलंका रक्षा समझौता और अन्य समझौतों के प्रमुख बिंदु:

रक्षा सहयोग

- यह रक्षा सहयोग पर पहला फ्रेमवर्क समझौता ज्ञापन (MoU) है।
- इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और उच्च स्तरीय वार्तालाप शामिल हैं।
- यह इस विचार को सुदृढ़ करता है कि दोनों देशों की सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका द्वारा भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित किया।
- राष्ट्रपति अनुर कुमारा डिसानायके ने आश्वासन दिया कि श्रीलंकाई भूमि का उपयोग भारत के विरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा।

ऊर्जा और अवसंरचना

संपूर पावर प्रोजेक्ट

- इस परियोजना की शिलान्यास समारोह वर्चुअली आयोजित की गई।
- यह परियोजना श्रीलंका की ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त बनाएगी।

मल्टी-प्रोडक्ट ऊर्जा पाइपलाइन परियोजना

- भारत, श्रीलंका और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर।
- त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने की योजना।

ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौता

- भारत और श्रीलंका की बिजली ग्रिड को जोड़ने का प्रस्ताव।
- इससे बिजली व्यापार और विद्युत निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी।

डिजिटल परिवर्तन

- भारत और श्रीलंका के बीच डिजिटल गवर्नेंस समाधानों को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर।
- श्रीलंका के डिजिटल परिवर्तन को तेज करने का उद्देश्य।

नवीकरणीय ऊर्जा पहल

सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट

- 5,000 धार्मिक स्थलों पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना की जाएगी।
- भारत द्वारा 17 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता से वित्तपोषित।
- 25 मेगावॉट हरित ऊर्जा उत्पन्न होगी।
- इसमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य और औषधि

MoU के तहत साझेदारी

- भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और
- श्रीलंका के स्वास्थ्य और मास मीडिया मंत्रालय के बीच।
- उद्देश्य: स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग।

अलग समझौता ज्ञापन

- इंडियन फार्माकोपिया कमीशन और
- श्रीलंका की नेशनल मेडिसिन्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच।
- औषधीय मानकों और प्रथाओं में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए।

क्षेत्रीय समर्थन और विकास

- भारत ने 2.4 अरब श्रीलंकाई रुपये की सहायता योजना की घोषणा की।
- श्रीलंका के पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर केंद्रित।

प्रधानमंत्री मोदी ने नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया, जो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। यह देश का पहला वर्टिकल-लिफ्ट समुद्री पुल है, जो सौ साल पुराने पंबन ब्रिज का स्थान लेता है और आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। यह पुल रामेश्वरम द्वीप को मांडपम (मुख्य भूमि) से जोड़ता है और इसे टिकाऊपन व तकनीकी उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसका उद्घाटन राम नवमी के पावन दिन और श्रीलंका से प्रधानमंत्री मोदी की वापसी के साथ हुआ, जहां उन्होंने राम सेतु का हवाई दर्शन भी किया। यह दिन आध्यात्मिक और संरचनात्मक दोनों दृष्टियों से भारत के लिए विशेष बन गया।

नए पंबन ब्रिज की प्रमुख विशेषताएं :

नया पंबन ब्रिज

- उद्घाटन तिथि: 6 अप्रैल 2025 (राम नवमी)
- उद्घाटनकर्ता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- स्थान: रामनाथपुरम ज़िला, तमिलनाडु
- उद्देश्य: रामेश्वरम द्वीप को मांडपम (मुख्य भूमि) से जोड़ना

ब्रिज की तकनीकी विशेषताएं

- कुल लंबाई: 2.07 किमी
- निर्माण लागत: ₹700 करोड़ से अधिक
- कार्यकारी एजेंसी: रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL), एक नवरत्न PSU
- डिज़ाइन प्रकार: वर्टिकल-लिफ्ट ब्रिज
- लिफ्ट स्पैन: 72.5 मीटर (17 मीटर तक ऊँचा किया जा सकता है, ताकि जहाज़ निकल सकें)
- ट्रैक क्षमता: दो रेलवे ट्रैकों के लिए डिज़ाइन, फिलहाल एक चालू
- ट्रेन गति क्षमता: 80 किमी/घंटा तक
- आयु: 100 वर्षों तक टिकाऊ

उन्नत निर्माण तकनीक

- स्टेनलेस स्टील रिइंफोर्समेंट
- पूरी तरह वेल्डेड जोड़
- समुद्री जंग से सुरक्षा के लिए हाई-ग्रेड पेंट व पॉलिसिलॉक्सेन कोटिंग
- न्यूनतम रख-रखाव वाला डिज़ाइन

वैश्विक तुलना व महत्व

- गोल्डन गेट ब्रिज (USA),
- टॉवर ब्रिज (UK),
- ओरेसुंड ब्रिज (डेनमार्क-स्वीडन) जैसी प्रतिष्ठित संरचनाओं से तुलना
- आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक

प्रधानमंत्री मोदी के अन्य कार्यक्रम

- एक नए तटरक्षक जहाज़ को रवाना किया (जो ब्रिज के नीचे से गुज़रा)
- रामेश्वरम–तांबरम (चेन्नई) ट्रेन को हरी झंडी
- ₹8,300 करोड़ के रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला
- रामेश्वरम के रामनाथस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना

आध्यात्मिक पहलू: राम सेतु दर्शन

- श्रीलंका से लौटते समय प्रधानमंत्री मोदी ने राम सेतु (एडम्स ब्रिज) का हवाई दर्शन किया
- यह दृश्य उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर साझा किया
- यह घटना अयोध्या के सूर्य तिलक समारोह के साथ हुई — "दैवीय संयोग" बताया गया
- राम सेतु को धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रमुखता दी गई

राम सेतु (एडम्स ब्रिज) के बारे में

- स्थान: रामेश्वरम (भारत) से मन्नार द्वीप (श्रीलंका) तक का समुद्री प्राकृतिक श्रृंखला
- लंबाई: लगभग 48 किमी
- उत्तर में: पाल्क जलडमरूमध्य (बंगाल की खाड़ी से जुड़ाव)
- दक्षिण में: मन्नार की खाड़ी (हिंद महासागर से जुड़ाव)

यह पुल न केवल भारत की इंजीनियरिंग उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

RBI Monetary Policy 2025: Bi-Monthly Highlights द्विमासिक आरबीआई मौद्रिक नीति 2025: RBI ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नए वित्तीय वर्ष की पहली नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों में कटौती की घोषणा की है। 7 से 9 अप्रैल 2025 के बीच हुई 54वीं बैठक में समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6% करने का निर्णय लिया, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी (SDF) दर को 5.75% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) व बैंक दर को 6.25% कर दिया गया है।

बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की, और इसमें डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगता भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. राजीव रंजन और श्री एम. राजेश्वर राव शामिल हुए। वर्ष 2025 के लिए अगली MPC बैठकें जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी में निर्धारित हैं।

वर्तमान नीतिगत दरें:

नीति	दर
रेपो दर	6.00%
SDF दर	5.75%
MSF दर	6.25%
बैंक दर	6.25%
फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर	3.35%

RBI द्वारा घोषित 6 अतिरिक्त उपाय:

1. संकटग्रस्त परिसंपत्तियों (stressed assets) की सेक्यूरिटाइजेशन की सुविधा प्रस्तावित।
2. सह-उधारी (co-lending) दिशानिर्देश सभी नियामक संस्थाओं व सभी प्रकार के ऋणों पर लागू होंगे।
3. सोने के विरुद्ध ऋण (loan against gold) के लिए नए नियामक प्रावधान।
4. आंशिक क्रेडिट एन्हांसमेंट (Partial Credit Enhancement) पर व्यापक दिशा-निर्देश।
5. NPCI को बैंकों और हितधारकों की सलाह से **UPI** के व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन की सीमा **₹2** लाख से अधिक बढ़ाने की स्वतंत्रता।
6. रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को विषय-तटस्थ (theme-neutral) और ऑन-टैप रूप में लागू किया जाएगा।

GDP वृद्धि अनुमान (RBI द्वारा):

अवधि	पूर्व अनुमान	नया अनुमान
FY26	6.7%	6.5%
Q1 FY26	6.7%	6.5%
Q2 FY26	7.0%	6.7%
Q3 FY26	6.5%	6.6%
Q4 FY26	6.5%	6.3%

CPI मुद्रास्फीति अनुमान (RBI द्वारा):

अवधि	पूर्व अनुमान	नया अनुमान
FY26	4.2%	4.0%
Q1 FY26	4.5%	3.6%
Q2 FY26	4.0%	3.9%
Q3 FY26	3.8%	3.8%
Q4 FY26	4.2%	4.4%

यह मौद्रिक नीति समीक्षा RBI के विकास व स्थिरता के संतुलन की ओर बढ़ते दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां ब्याज दरों में कटौती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, जबकि मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण में रखा गया है।

भारत-यूएई रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए सहमत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम ने 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता की, जिसका उद्देश्य भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना था। उनकी बातचीत रक्षा, तटरक्षक बल संचालन, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और जनसंपर्क संबंधों में सहयोग को सशक्त बनाने पर केंद्रित रही। भारत में क्राउन प्रिंस के रूप में शेख हमदान की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। यह यात्रा दोनों देशों की साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं और पारस्परिक आर्थिक हितों को रेखांकित करती है।

प्रमुख बिंदु

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- भारत और यूएई ने रक्षा एवं तटरक्षक बल सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई।
- तटरक्षक बल सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- शेख हमदान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई बातचीत में व्यापारिक संबंधों की तरह रक्षा संबंधों को भी ऊंचे स्तर तक ले जाने पर बल दिया गया।

प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान:

- संयुक्त प्रशिक्षण और आदान-प्रदान कार्यक्रम
- सह-उत्पादन और सह-विकास परियोजनाएं
- रक्षा निर्माण में सहयोग
- दोनों पक्षों ने इंडिया-यूएई डिफेंस पार्टनरशिप फोरम का स्वागत किया।
- मेक-इन-इंडिया और मेक-इन-एमिरेट्स पहलों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

उच्च स्तरीय राजनयिक संवाद

- प्रधानमंत्री मोदी ने शेख हमदान की यात्रा को "गहरी मित्रता की पुष्टि" बताया।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी शेख हमदान से मुलाकात की और मजबूत संबंधों के लिए आभार जताया।
- शेख हमदान ने भारत-यूएई संबंधों को "विश्वास पर आधारित, इतिहास द्वारा आकारित" बताया।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

- दुबई चैंबर ने मुंबई में दुबई-इंडिया बिज़नेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें 200 भारतीय व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण व्यापारिक आँकड़े:

- भारत-यूएई गैर-तेल व्यापार (2023): $54.2 बिलियन
- दुबई-भारत द्विपक्षीय व्यापार: $45.4 बिलियन
- भारत में दुबई का निवेश: $4.68 बिलियन

2024 में:

- 16,623 भारतीय कंपनियाँ दुबई चैंबर ऑफ कॉमर्स में शामिल हुईं।
- अब दुबई में 70,000 से अधिक भारतीय कंपनियाँ कार्यरत हैं।

संपर्क और जन-सामान्य संबंध

- 2024 में दुबई ने 3.14 मिलियन दक्षिण एशियाई पर्यटकों का स्वागत किया, जिनमें सबसे अधिक संख्या भारत से थी।
- नेताओं ने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और संपर्क के माध्यमों की भूमिका को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण बताया

तेलंगाना अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना

तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के उप-श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद, 14 अप्रैल 2025 को—जो कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है—राज्य सरकार ने तेलंगाना अनुसूचित जातियाँ *(आरक्षण का युक्तिकरण)* अधिनियम, *2025* को लागू करते हुए एक सरकारी आदेश (GO) जारी किया। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा 15% SC आरक्षण को 59 उप-जातियों के बीच तीन समूहों में बाँटकर उनकी आपसी सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अधिक न्यायसंगत तरीके से लाभ वितरित करना है। यह निर्णय ऐतिहासिक प्रयासों जैसे कि लोकुर समिति (1965) और हाल की जस्टिस रामचंद्र राजू व उषा मेहरा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है, जो लक्षित सकारात्मक कार्रवाई की दिशा में एक ठोस बदलाव को दर्शाता है।

तेलंगाना में अनुसूचित जाति **(SC)** उप-श्रेणीकरण के मुख्य बिंदु **(**मुख्य विशेषताएँ**)**

विधायी और कानूनी ढांचा

- तेलंगाना विधानसभा ने यह अधिनियम 18 मार्च 2025 को पारित किया।
- राज्यपाल की स्वीकृति 8 अप्रैल 2025 को प्राप्त हुई।
- 14 अप्रैल (अंबेडकर जयंती) को सरकारी आदेश (GO) जारी किया गया।
- यह सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले पर आधारित है, जिसमें SC उप-श्रेणीकरण की अनुमति दी गई थी।
- न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता में अक्टूबर 2024 में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया था।

SC उप-श्रेणीकरण की संरचना

- कुल SC आरक्षण: 15% (2011 की जनगणना के आधार पर)
- SC उप-श्रेणियाँ: सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर तीन समूहों में विभाजन।

समूह	समुदायों की संख्या	जनसंख्या भागीदारी	आरक्षण आवंटन
समूह **1**	15 (सबसे पिछड़े)	3.288% (~1.71 लाख)	1%
समूह **2**	18 (मध्यम रूप से पिछड़े)	62.74% (~34 लाख)	9%
समूह **3**	26 (तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति वाले)	33.963% (~17 लाख)	5%

वर्गीकरण का आधार

- जनसंख्या का आकार, साक्षरता दर, रोजगार, शिक्षा की उपलब्धता, वित्तीय सहायता, राजनीतिक भागीदारी।
- शमीम अख्तर आयोग को 8,600 से अधिक प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुईं।
- विस्तृत परामर्श के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

प्रमुख वक्तव्य और औचित्य

- स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिंह
  - कहा, यह अंतिम समाधान नहीं, बल्कि उत्थान का एक साधन है।
  - शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, औद्योगिक सहायता और वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
  - बुडिगा जांगा जाति को असमान रूप से वंचित जाति का उदाहरण बताया।
- नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी
  - 13 अप्रैल 2025 को अंतिम बैठक की अध्यक्षता की।
  - SC समुदायों में क्रीमी लेयर की अवधारणा को खारिज किया।
  - स्पष्ट किया कि मौजूदा लाभों में कोई कटौती नहीं होगी।
  - बताया कि तेलंगाना की SC जनसंख्या अब 17.5% है, 2026 की जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ सकता है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ

- CPI विधायक कुनमनेनी संबाशिवा रेड्डी
  - रेल्ला समुदाय को समूह 3 में डाले जाने पर सवाल उठाया।
- AIMIM विधायक माजिद हुसैन
  - SC आरक्षण को 18% तक बढ़ाने और 3 के बजाय 4 उप-श्रेणियाँ बनाने का सुझाव दिया।
- सरकार का पक्ष
  - 3 समूहों को संतुलित और व्यावहारिक बताया—2 से असंतुलन होता, 4 अत्यधिक होते।

यह पहल सामाजिक न्याय की दिशा में एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है, जिससे सबसे कमजोर वर्गों तक वास्तविक लाभ पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति को 3 महीने की समय सीमा दी

तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2023) के एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधायी प्रक्रिया में मौजूद एक महत्वपूर्ण शून्य को संबोधित किया—राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजे गए राज्य विधेयकों पर निर्णय में देरी। पहली बार, न्यायालय ने राष्ट्रपति के निर्णय के लिए **3** महीने की समयसीमा तय की, जिससे उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो और संघवाद तथा लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों की रक्षा हो सके। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह सलाह भी दी कि यदि कोई विधेयक संभावित असंवैधानिकता के आधार पर राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा गया हो, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद **143** के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहिए। यह निर्णय सहकारी संघवाद की भावना की रक्षा करने और कार्यपालिका के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य विशेषताएँ

मामला: तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल, *2023*

संविधानिक अनुच्छेद संबंधित

- अनुच्छेद 201 – राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ।
- अनुच्छेद 143 – राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति।

अनुच्छेद 201 की न्यायालयीय व्याख्या

- यदि राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति को भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा।
- पहले इस प्रक्रिया में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं थी, जिससे विधायी ठहराव और अनिश्चितता पैदा होती थी।
- कोर्ट ने कहा कि अनिश्चितकालीन देरी असंवैधानिक है और यह "गैर-मनमानेपन" के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

समयबद्ध निर्णय

- अब राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर सहमति या अस्वीकृति देने के लिए 3 महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- यह निर्णय कारण सहित राज्य सरकार को सूचित किया जाना आवश्यक है।

कोई "पूर्ण वीटो" नहीं

- राष्ट्रपति अनिश्चितकाल तक विधेयक को रोके नहीं रख सकते—यह असंवैधानिक "एब्सोल्यूट वीटो" के समान होगा।
- यदि राष्ट्रपति सहमति नहीं देते हैं, तो कानूनी आधार पर स्पष्ट और तर्कसंगत कारण प्रस्तुत करना अनिवार्य है—राजनीतिक कारण मान्य नहीं होंगे।

न्यायिक उपाय

- यदि राष्ट्रपति द्वारा कोई निर्णय लंबे समय तक नहीं लिया जाता है, तो संबंधित राज्य न्यायालय का सहारा ले सकते हैं।
- राज्य सरकारें "मैंडमस" याचिका दायर कर राष्ट्रपति को निर्णय लेने हेतु बाध्य कर सकती हैं।

अनुच्छेद 143: सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श

- यदि राज्यपाल विधेयक को असंवैधानिक मानते हुए राष्ट्रपति को भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए।
- यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती, परंतु इसकी प्रभावशीलता और मान्यता उच्च होती है।
- इससे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक कानूनों के निर्माण को रोका जा सकता है, जिससे जन संसाधनों की बचत होती है।

राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच अंतर

- यदि राज्यपाल कोई विधेयक वापस भेजते हैं और वह दोबारा पारित होता है, तो उन्हें अनिवार्य रूप से उस पर सहमति देनी होती है।
- राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 201 के अंतर्गत ऐसा कोई बंधन नहीं होता।

नीति बनाम संविधान

- सुप्रीम कोर्ट केवल तभी परामर्श देगा जब मामला शुद्ध रूप से विधिक या संवैधानिक प्रश्न से जुड़ा हो।
- यदि मामला नीति, सामाजिक-आर्थिक या राजनीतिक प्रकृति का है, तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

सहायक सिफारिशें

- सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2010) की सिफारिशें:
  - राष्ट्रपति को समय-सीमित निर्णय लेना चाहिए।
  - असंवैधानिकता की आशंका होने पर अनुच्छेद **143** के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना चाहिए।
- गृह मंत्रालय की कार्यालय ज्ञापन (2016) ने भी 3 महीने की समय-सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की थी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे

भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने 16 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। यह घोषणा केंद्रीय विधि मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से की गई। सरकार की औपचारिक मंजूरी के बाद न्यायमूर्ति गवई भारत के **52**वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। न्यायमूर्ति गवई को वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। वे वर्तमान CJI संजीव खन्ना के 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार संभालेंगे। न्यायमूर्ति गवई का कानूनी सफर दशकों तक फैला हुआ है, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से संविधानिक और प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका नियुक्त होना न्यायपालिका में विविधता और अनुभव की निरंतरता को दर्शाता है।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई का करियर विवरण **(हिंदी में)**

प्रारंभिक पृष्ठभूमि और प्रारंभिक करियर

- जन्म: अमरावती, महाराष्ट्र।
- कानूनी करियर की शुरुआत: 1985 में वकालत शुरू की।
- प्रारंभिक प्रशिक्षण: बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और न्यायाधीश राजा एस. भोंसले के अधीन 1987 तक कार्य किया।
- प्रमुख अभ्यास क्षेत्र: नागपुर खंडपीठ, विशेष रूप से संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में विशेषज्ञता।

सरकारी भूमिकाएँ

- 1992-93: नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त।
- 2000 से आगे: सरकारी वकील और लोक अभियोजक के पद पर पदोन्नति।

न्यायिक करियर

- नवंबर 2003: बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त।
- नवंबर 2005: स्थायी न्यायाधीश बने।
- मई 2019: भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त।

न्यायमूर्ति गवई के प्रमुख न्यायिक योगदान

1 नोटबंदी पर फैसला (जनवरी 2023)

- 2016 में ₹500 और ₹1,000 के नोटों को अमान्य घोषित करने के केंद्र सरकार के फैसले को बहुमत के साथ सही ठहराया।
- न्यायमूर्ति गवई इस बहुमत निर्णय का हिस्सा थे।

2 अनुसूचित जातियों/जनजातियों का उप-वर्गीकरण (अगस्त 2024)

- ऐतिहासिक फैसले में SC/ST वर्गों में 'क्रीमी लेयर' लागू करने की वकालत की।
- इससे यह सुनिश्चित किया गया कि वास्तविक रूप से वंचित लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले।

3 अनुच्छेद 370 की समाप्ति (2019)

- पाँच-न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा रहे, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया।

4 बुलडोज़र से तोड़फोड़ पर आलोचना (नवंबर 2024)

- दो-न्यायाधीशों की पीठ में रहते हुए अपराध के आरोपियों की संपत्तियों को बिना विधिक प्रक्रिया के ध्वस्त करने की कार्रवाई की आलोचना की।
- इसे कानून के शासन का उल्लंघन बताया।

भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया

भारत ने अपनी प्राचीन सभ्यता की विरासत में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ते हुए भगवद गीता की पांडुलिपियों और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल करवा लिया है। यह निर्णय वैश्विक स्तर पर भारत की समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने इस उपलब्धि को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और गर्व का क्षण बताया है। इन दो नई प्रविष्टियों के साथ अब भारत की कुल 14 दस्तावेज़ी धरोहरें इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो चुकी हैं, जो हमारी संस्कृति की गहराई और विश्व योगदान का प्रतीक हैं।

मुख्य विशेषताएँ

- मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या है?
  - वर्ष 1992 में स्थापित, यूनेस्को का "मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (MoW) प्रोग्राम" वैश्विक महत्व की दस्तावेज़ी धरोहरों को संरक्षित करने और उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  - यह पांडुलिपियों, अभिलेखों, मौखिक परंपराओं, ऑडियो-विज़ुअल सामग्री और पुस्तकालय संग्रहों की सुरक्षा करता है।
- भारत की **2025** में शामिलियाँ
  - 17 अप्रैल 2025 को भगवद गीता की पांडुलिपियाँ और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र इस रजिस्टर में शामिल किए गए।
  - अब भारत की कुल 14 दस्तावेज़ी धरोहरें इस सूची में दर्ज हैं।
- भगवद गीता का महत्व
  - हिंदू धर्म का एक प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथ, जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है।
  - इसे दर्शन, धर्म (कर्तव्य) और आध्यात्मिकता का सार्वभौमिक मार्गदर्शक माना जाता है।
  - यह लगभग 80 भाषाओं में अनूदित हो चुकी है।
- नाट्यशास्त्र का महत्व
  - भरत मुनि द्वारा रचित यह प्राचीन ग्रंथ नाट्य, रंगमंच और प्रदर्शन कलाओं पर आधारित है।
  - इसमें अभिनय, मंच सज्जा, संगीत, नृत्य और सौंदर्यशास्त्र (रस सिद्धांत) सहित कई विषयों का वर्णन है।
  - यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नाट्य परंपराओं की आधारशिला माना जाता है।
- आधिकारिक प्रतिक्रियाएँ
  - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा को "हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण" बताया और गीता व नाट्यशास्त्र को भारतीय सभ्यता और चेतना को पोषित करने वाले ग्रंथ कहा।
  - संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सभ्यतागत विरासत के लिए "ऐतिहासिक क्षण" बताया।
- वैश्विक परिप्रेक्ष्य
  - वर्ष 2025 में कुल 74 नई कलेक्शन इस सूची में जोड़ी गईं, जिससे कुल वैश्विक संख्या 570 हो गई।
  - इनमें से 14 वैज्ञानिक दस्तावेज़ी धरोहरों से संबंधित हैं, जिनमें महिलाओं और बहुपक्षीय संस्थाओं का योगदान भी शामिल है।
- यूनेस्को का वक्तव्य
  - यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अज़ूले ने कहा कि दस्तावेज़ी धरोहरें नाजुक होती हैं, लेकिन वे मानव स्मृति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
  - यह रजिस्टर संरक्षण प्रयासों, ज्ञान साझा करने और वैश्विक अभिलेख के रूप में कार्य करता है।
- यूनेस्को का व्यापक कार्यक्रम
  - यूनेस्को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने को भी समर्थन देता है।
  - अब 100 से अधिक देशों में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड समितियाँ कार्यरत हैं।
  - यह कार्यक्रम धरोहर दस्तावेज़ों तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देता है

महाराष्ट्र के राज्यपाल ने यशराज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किए

महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने स्वास्थ्य, सतत विकास हेतु शिक्षा और सुशासन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले तीन प्रमुख जमीनी स्तर के संगठनों को 'यशराज भारती सम्मान' के तीसरे संस्करण से सम्मानित किया। मुंबई में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में जन स्वास्थ्य सहयोग (छत्तीसगढ़), प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म के प्रभाव को मान्यता दी गई। इस अवसर पर महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल और भारत के G-20 शेरपा अमिताभ कांत जैसी विशिष्ट हस्तियों की उपस्थिति रही। राज्यपाल राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और नैतिक शासन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सके।

यशराज भारती सम्मान **2025** के मुख्य बिंदु

सम्मान का अवलोकन

- यशराज भारती सम्मान उन व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय योगदान देते हैं।
- यह पुरस्कार का तीसरा संस्करण है।

पुरस्कार विजेता और उनके योगदान

जन स्वास्थ्य सहयोग (छत्तीसगढ़)

- दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ-निर्देशित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मानित।
- स्वास्थ्य सेवाओं में समानता और सस्ती चिकित्सा तक पहुंच पर केंद्रित।

प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन

- शिक्षा के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित।
- पूरे भारत में सीखने के परिणामों की निगरानी और सुधार के लिए ASER (Annual Status of Education Report) जैसे नवाचारों के लिए प्रसिद्ध।

सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र - NIC)

- नागरिक-केंद्रित ई-सेवाएं कुशलतापूर्वक और पारदर्शी ढंग से प्रदान कर अच्छी शासन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म।

कार्यक्रम की झलकियां

- यह आयोजन मुंबई में राज भवन द्वारा आयोजित किया गया।

मुख्य अतिथियों की उपस्थिति

- दिलीप वलसे पाटिल, पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष।
- अमिताभ कांत, भारत के G-20 शेरपा।

राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन का संबोधन

शिक्षा:

- महाराष्ट्र में स्कूलों की संख्या अधिक होने के बावजूद गिरते शिक्षा स्तर पर चिंता जताई।

स्वास्थ्य सेवा:

- जनजातीय क्षेत्रों में जीवन गुणवत्ता सुधारने हेतु विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया।

शासन व्यवस्था:

- भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-जागरूकता की आवश्यकता और नैतिक शासन को सामाजिक परिवर्तन की नींव बताया।

लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025: विजेताओं की पूरी सूची देखें

2025 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स ने मैड्रिड में एक भव्य समारोह के साथ अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया गया। "खेलों के ऑस्कर" कहे जाने वाले इन अवॉर्ड्स में व्यक्तिगत प्रतिभा के साथ-साथ सामूहिक उपलब्धियों को भी सराहा गया। इस आयोजन में दुनिया भर के खेलों से जुड़े दिग्गज, उभरते सितारे और बदलाव लाने वाले खिलाड़ी एकत्रित हुए। मैड्रिड की जीवंतता के बीच आयोजित यह समारोह विश्व खेल जगत की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों का उत्सव बन गया।

विजेताओं की शानदार सूची

मोंडो डुप्लांटिस: द वॉल्टिंग लीजेंड

25 वर्षीय स्वीडिश-अमेरिकन पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस को **Laureus** वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। लगातार तीन वर्षों तक नामांकित होने के बाद उन्होंने पहली बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया।

डुप्लांटिस को अब तक का सबसे महान पोल वॉल्टर माना जाता है। उन्होंने इन दिग्गजों को पीछे छोड़ा:

- कार्लोस अल्कराज (टेनिस – स्पेन)
- लियोन मार्चां (स्विमिंग – फ्रांस)
- तदेइ पोगाचार (साइक्लिंग – स्लोवेनिया)
- मैक्स वेरस्टैपेन (फॉर्मूला 1 – नीदरलैंड)

2024 में डुप्लांटिस ने:

- दूसरा वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप गोल्ड जीता
- नौवीं बार अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा
- पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता

इस पुरस्कार को और खास बना दिया यूसेन बोल्ट की विशेष श्रद्धांजलि ने, जो ट्रैक एंड फील्ड के एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान मिल चुका है।

सिमोन बाइल्स: द क्वीन रिटर्न्स

प्रतिस्पर्धा से कुछ समय दूर रहने के बाद सिमोन बाइल्स ने पेरिस ओलंपिक में शानदार वापसी की और जीते:

- तीन स्वर्ण पदक
- एक रजत पदक

उन्हें चौथी बार Laureus वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, जिससे उन्होंने सेरेना विलियम्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

यह जीत उन्हें इतिहास की सबसे सज्जित (decorated) जिमनास्टों में से एक के रूप में स्थापित करती है।

गौरतलब है कि बाइल्स और डुप्लांटिस दोनों ही पहले Comeback of the Year अवॉर्ड भी जीत चुके हैं — जो उनके जज़्बे और हौसले का प्रमाण है।

विजेताओं की पूरी सूची

श्रेणी	विजेता
वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर	मोंडो डुप्लांटिस
वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर	सिमोन बाइल्स
वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर	रियल मैड्रिड
ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर	लामिन यमाल
कमबैक ऑफ द ईयर	रेबेका आंद्राडे
स्पोर्ट्सपर्सन विद अ डिसएबिलिटी	जियांग यूयान
एक्शन स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर	टॉम पिडकॉक
स्पोर्ट फॉर गुड अवॉर्ड	किक4लाइफ
स्पोर्टिंग आइकन अवॉर्ड	राफेल नडाल
लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड	केली स्लेटर

IISc टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर

टाइम्स हायर एजुकेशन **(THE)** एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग **2025** की घोषणा 23 अप्रैल को की गई, जिसमें एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष की रैंकिंग में 35 देशों और क्षेत्रों के कुल 853 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, जो शोध, शिक्षण और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत की ओर से इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस **(IISc),** बेंगलुरु ने एक बार फिर श्रेष्ठता कायम रखते हुए देश की सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है, जिसे एशिया में कुल मिलाकर **38**वां स्थान मिला है। हालांकि, कई भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई, जो एशियाई उच्च शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता मानकों में बदलाव को दर्शाता है।

एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग **2025** की प्रमुख झलकियां

भारतीय संस्थानों की रैंकिंग

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) को 38वां स्थान मिला है, हालांकि यह 2024 की 32वीं रैंक से थोड़ा नीचे खिसका है।
- अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और आईआईटी इंदौर को 131वां स्थान मिला है।
- महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने 140वीं रैंक हासिल की है, जो पिछले वर्ष की 134वीं रैंक से थोड़ी कम है।
- अन्य प्रमुख भारतीय संस्थान जैसे शूलिनी यूनिवर्सिटी, सवीथा इंस्टीट्यूट, और जामिया मिलिया इस्लामिया भी सूची में शामिल हैं।

भारतीय विश्वविद्यालयों की विस्तृत रैंकिंग

- 38वां – इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc)
- 111वां – अन्ना विश्वविद्यालय
- 131वां – इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) इंदौर
- 140वां – महात्मा गांधी विश्वविद्यालय
- 146वां – शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज
- 149वां – सवीथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज
- 161वां – जामिया मिलिया इस्लामिया
- 184वां – IIT गुवाहाटी
- 184वां – KIIT यूनिवर्सिटी
- 188वां – अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
- 188वां – UPES
- 191वां – IIT पटना
- 191वां – NIT राउरकेला
- 200वां – इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुझान

- चीन ने एक बार फिर वर्चस्व कायम रखा है: त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले और दूसरे स्थान पर हैं।
- सिंगापुर की स्थिति मजबूत हुई है: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है।
- जापान और हॉन्गकॉन्ग की प्रमुख यूनिवर्सिटियाँ भी शीर्ष 10 में बनी हुई हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्गकॉन्ग।
- इस वर्ष पहली बार उज़्बेकिस्तान, बहरीन, मंगोलिया और सीरिया की यूनिवर्सिटियाँ भी रैंकिंग में शामिल हुई हैं।

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

भारतीय विधिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिनेश माहेश्वरी को भारत के **23**वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अप्रैल **2025** में नियुक्त किया गया है। यह घोषणा सरकार की उस निरंतर पहल का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत भारतीय कानून व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जा रही है और सुधारों की सिफारिशें की जा रही हैं। इस नियुक्ति को विशेष रूप से समान नागरिक संहिता **(Uniform Civil Code - UCC)** जैसे लंबे समय से चर्चा में रहे संवेदनशील विषयों की पृष्ठभूमि में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायमूर्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में विधि आयोग से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और संवैधानिक पहलुओं पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यापक कानूनी सुधारों की सिफारिश करेगा।

भारत के **23**वें विधि आयोग का कार्यकाल और संरचना

23वां विधि आयोग **1** सितंबर **2024** को औपचारिक रूप से गठित किया गया था, जिसका कार्यकाल **31** अगस्त **2027** तक रहेगा। यह आयोग कुल **7** सदस्यों से मिलकर बना है, जिनमें शामिल हैं:

- एक अध्यक्ष: न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिनेश माहेश्वरी
- चार पूर्णकालिक सदस्य: जिनमें वकील हितेश जैन और शैक्षणिक विशेषज्ञ पी. वर्मा (जो 22वें आयोग का भी हिस्सा थे) शामिल हैं

- दो पदेन सदस्य: जो विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग से नामित किए गए हैं

इसके अतिरिक्त, सरकार **5** अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकती है। यदि वर्तमान में सेवारत न्यायाधीशों को आयोग में शामिल किया जाता है, तो वे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सेवानिवृत्ति या आयोग के कार्यकाल के अंत तक कार्य करेंगे।

समान नागरिक संहिता **(UCC)** पर विशेष ध्यान

इस आयोग का मुख्य कार्य समान नागरिक संहिता **(Uniform Civil Code - UCC)** की व्यवहार्यता की जांच करना है—जो भारत में एक अत्यधिक राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील विषय रहा है। UCC का उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक साझा नागरिक कानून लागू करना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो।

UCC पर पूर्व परामर्श की पृष्ठभूमि:

- 22वें विधि आयोग ने 2023 में UCC पर देशव्यापी परामर्श शुरू किए थे, जिनमें 70 से अधिक परामर्श सत्रों में जनता की राय ली गई थी।
- इसने एक 749-पृष्ठों का प्रारंभिक मसौदा रिपोर्ट तैयार किया था, लेकिन इसकी प्रक्रिया पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी के लोकपाल नियुक्त हो जाने के बाद अधूरी रह गई।
- 21वें आयोग ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि "वर्तमान समय में UCC न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय", जिससे नीति निर्माण में मतभेद उत्पन्न हुआ।
- अब 23वें आयोग से उम्मीद की जा रही है कि वह इस मुद्दे पर अंतिम सिफारिशें देगा, जो भारत के बदलते सामाजिक और कानूनी परिवेश को ध्यान में रखेंगी।

UCC का राजनीतिक महत्व

UCC लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी **(BJP)** के वैचारिक एजेंडे का हिस्सा रहा है, जिसमें शामिल हैं:

- अनुच्छेद 370 की समाप्ति (जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला प्रावधान)
- अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण
- इन दोनों वादों को BJP ने अपने दूसरे कार्यकाल (2019–2024) में पूरा कर दिया है। अब UCC को पार्टी के आखिरी वैचारिक स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है।

राज्यों में हो रहे विकास**:**

- उत्तराखंड UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- गुजरात ने भी यूसीसी ड्राफ्टिंग समिति का गठन किया है।
- 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व "राष्ट्र की एकता के लिए अपमानजनक" है, जिससे UCC पर सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

वित्तीय और संचालन संरचना

23वें विधि आयोग के कार्य संचालन हेतु एक सुव्यवस्थित वित्तीय एवं प्रशासनिक ढांचा निर्धारित किया गया है:

- अध्यक्ष (सेवानिवृत्त) को ₹2.5 लाख मासिक मानधन मिलेगा, जिसमें पेंशन शामिल है।
- पूर्णकालिक सेवानिवृत्त सदस्यों को ₹2.25 लाख प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।

यह आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, लेकिन साथ ही विधि एवं न्याय मंत्रालय, अन्य विधिक निकायों और नागरिक समाज संगठनों के साथ समन्वय में कार्य कर समावेशी और व्यावहारिक विधि सुधारों की सिफारिश करेगा।

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025: पांच साल बाद फिर से शुरू

कैलाश मानसरोवर यात्रा (केएमवाई) एक महत्वपूर्ण वार्षिक तीर्थयात्रा है, जो भारत और चीन के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक मानी जाती है। यह यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। माना जाता है कि माउंट कैलाश की परिक्रमा करने से आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है, जबकि मानसरोवर झील में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह तीर्थयात्रा 2020 में COVID-19 महामारी और सीमा तनावों के कारण स्थगित कर दी गई थी। पांच वर्षों के बाद इसका पुनः आरंभ होना धार्मिक पर्यटन और द्विपक्षीय सहयोग में एक सकारात्मक विकास का संकेत है।

समाचार में क्यों?

26 अप्रैल 2025 को विदेश मंत्रालय (MEA) ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पुनः आरंभ की घोषणा की। यह यात्रा जून से अगस्त 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। कुल 750 तीर्थयात्रियों को अनुमति दी जाएगी, जो लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम) मार्गों से जत्थों में जाएंगे।

कैलाश मानसरोवर यात्रा क्या है?

कैलाश मानसरोवर यात्रा भारतीय नागरिकों के लिए आयोजित एक वार्षिक सरकारी तीर्थयात्रा है, जिसमें वे तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (चीन) स्थित माउंट कैलाश और मानसरोवर झील के दर्शन करते हैं। इसका गहरा धार्मिक महत्व है:

- हिंदू माउंट कैलाश को भगवान शिव का निवास मानते हैं।
- बौद्ध इसे बुद्ध देमचोक का निवास मानते हैं।
- जैन मानते हैं कि उनके प्रथम तीर्थंकर ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था।
- बोन धर्म के अनुयायी भी इसे पवित्र पर्वत मानते हैं।

यात्रा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक तीर्थाटन और भारत-चीन सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

मुख्य विवरण / विशेषताएँ

यात्रा के दो आधिकारिक मार्ग हैं:

- लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड): पारंपरिक मार्ग, 1981 से चालू।
- नाथू ला दर्रा (सिक्किम): मोटरेबल मार्ग, 2015 से चालू।

तीर्थयात्रियों का विवरण:

- लिपुलेख मार्ग से 5 जत्थे, प्रत्येक में 50 तीर्थयात्री।
- नाथू ला मार्ग से 10 जत्थे, प्रत्येक में 50 तीर्थयात्री।

पंजीकरण पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है (https://kmy.gov.in) के माध्यम से, जिसमें निष्पक्ष, यादृच्छिक और लैंगिक संतुलन सुनिश्चित किया गया है। यात्रा का समन्वय MEA, गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), उत्तराखंड, सिक्किम और दिल्ली की राज्य सरकारों और कुमाऊँ मंडल विकास निगम (KMVN) द्वारा किया जाता है।

प्रभाव / महत्त्व

यात्रा के पुनः आरंभ होने के कई प्रमुख निहितार्थ हैं:

- धार्मिक और सांस्कृतिक: आस्था और परंपराओं को सुदृढ़ करता है।
- कूटनीतिक संबंध: भारत-चीन संबंधों में जन संपर्क के माध्यम से सुधार का प्रतीक है।
- आर्थिक लाभ: उत्तराखंड और सिक्किम में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार सृजन।
- रणनीतिक मूल्य: सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना और संपर्क में सुधार कर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है।

चुनौतियाँ / चिंताएँ

हालांकि यात्रा का आरंभ सकारात्मक है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

- सुरक्षा: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव।
- लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा: कठिन भूभाग, ऊँचाई और मौसम संबंधी जोखिम।
- कूटनीतिक संवेदनशीलता: चीन के साथ नाजुक संबंध।
- पर्यावरणीय चिंता: हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर तीर्थयात्रियों के बढ़ते दबाव से खतरा।

आगे का रास्ता / समाधान

यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है:

- सुरक्षा उपाय बढ़ाना: चिकित्सीय जाँच, आपातकालीन सुविधाओं और बचाव प्रबंधों को मजबूत करना।
- कूटनीतिक संवाद बनाए रखना: चीन के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना।
- सतत आधारभूत संरचना विकास: न्यूनतम पारिस्थितिक क्षति के साथ सड़कों, संचार और आश्रय सुविधाओं में सुधार।
- पर्यावरण संरक्षण: कचरा प्रबंधन लागू करना और हरित पर्यटन को बढ़ावा देना।
- तीर्थयात्रियों का प्रशिक्षण: उच्च ऊँचाई के अनुरूप बनाने और पर्यावरणीय जागरूकता के लिए प्रशिक्षण देना।

कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए "जीवंत गांव कार्यक्रम-II (वीवीपी-II)" को मंजूरी दी

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम -II (VVP-II) को केंद्रीय क्षेत्र योजना (100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित) के रूप में मंजूरी दी, जो 'सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत भूमि सीमाओं' के लिए विकसित भारत@2047 की परिकल्पना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
- यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं (ILBs) से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के समग्र विकास में सहायता करेगा, उत्तर सीमा को छोड़कर, जिसे पहले ही VVP-I के तहत शामिल किया जा चुका है।
- इस योजना के तहत कुल ₹6,839 करोड़ की लागत से इसे वित्त वर्ष 2028-29 तक अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश), लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनिंदा रणनीतिक गांवों में लागू किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर जीवन स्थितियां और पर्याप्त आजीविका के अवसर प्रदान करना है ताकि सीमाएं समृद्ध और सुरक्षित बनें, सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण हो सके, और सीमावर्ती आबादी को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके तथा उन्हें सीमा सुरक्षा बलों की आंख और कान के रूप में तैयार किया जा सके, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- यह कार्यक्रम गांव या गांवों के समूह के भीतर बुनियादी ढांचा विकास, मूल्य श्रृंखला विकास (सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों आदि के माध्यम से), सीमा-विशिष्ट जनसंपर्क गतिविधियाँ, शैक्षणिक अवसंरचना जैसे स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना, पर्यटन सर्किटों का विकास, और सीमा क्षेत्रों में विविध और सतत आजीविका के अवसरों के लिए परियोजनाएं प्रदान करने हेतु धन उपलब्ध कराएगा।
- हस्तक्षेप सीमा-विशिष्ट, राज्य एवं गांव-विशिष्ट होंगे और इन्हें सहभागी दृष्टिकोण के तहत तैयार की गई ग्राम कार्य योजनाओं के आधार पर लागू किया जाएगा। इन गांवों के लिए हर मौसम में सड़क संपर्क की व्यवस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पहले से स्वीकृत पीएमजीएसवाई-IV के तहत की जाएगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति सीमा क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योजनागत दिशानिर्देशों में उचित ढील देने पर विचार करेगी।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य, पहचाने गए गांवों में व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर की मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को योजना मानदंडों के अनुसार पूर्ण रूप से लागू (सैचुरेशन) करना है। साथ ही, इन ब्लॉकों के सभी गांवों में चार प्रमुख विषयों — हर मौसम में सड़क संपर्क, दूरसंचार संपर्क, टेलीविजन संपर्क, और विद्युतीकरण — में योजनाओं के समेकन के माध्यम से सैचुरेशन प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- कार्यक्रम का जोर इन गांवों में जीवंतता को बढ़ाने पर है, जिसके तहत मेलों और उत्सवों का आयोजन, जागरूकता शिविर, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, केंद्रीय एवं राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के नियमित दौरे एवं रात्रि प्रवास शामिल हैं। इससे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी और इन गांवों की स्थानीय संस्कृति एवं विरासत को बढ़ावा मिलेगा।
- तकनीक का लाभ उठाया जाएगा और PM गति शक्ति जैसे सूचना डेटाबेस का उपयोग इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा।
- VVP-II, VVP-I के साथ मिलकर, सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर और जीवंत बनाने की एक परिवर्तनकारी पहल है।

कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की, ने रेलवे मंत्रालय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत लगभग **₹18,658** करोड़ है। ये चारों परियोजनाएं तीन राज्यों — महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ — के **15** जिलों में फैली हुई हैं और इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग **1247** किलोमीटर की वृद्धि होगी।

इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

- संबलपुर – जरापड़ा तीसरी और चौथी लाइन
- झारसुगुड़ा – सासोन तीसरी और चौथी लाइन
- खरसिया – नया रायपुर – परमलकसा पांचवीं और छठी लाइन
- गोंदिया – बल्हारशाह दोहरीकरण

लाइन क्षमता में वृद्धि से गतिशीलता में सुधार होगा, जिससे सेवा की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। ये मल्टी-ट्रैकिंग योजनाएं रेलवे की सबसे व्यस्त मार्गों पर संचालन को सुगम बनाएंगी और भीड़भाड़ को कम करेंगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "नए भारत" के विजन के अनुरूप हैं, जो क्षेत्रीय विकास के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगी और रोजगार / स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगी।

ये परियोजनाएं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए तैयार की गई हैं, जो समन्वित योजना के जरिए संभव हुई हैं और लोगों, सामान और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करेंगी।

इन परियोजनाओं के तहत **19** नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे दो आकांक्षी जिलों (गडचिरोली और राजनांदगांव) को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं लगभग **3350** गांवों और **47.25** लाख की जनसंख्या को जोड़ेंगी।

खरसिया – नया रायपुर – परमलकसा परियोजना से बलौदा बाजार जैसे नए क्षेत्रों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे नए औद्योगिक इकाइयों, जैसे कि सीमेंट कारखानों की स्थापना की संभावनाएं बनेंगी।

ये मार्ग कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन परियोजनाओं से रेलवे की मालवाहन क्षमता में **88.77** मिलियन टन प्रतिवर्ष **(MTPA)** की वृद्धि होगी। रेलवे एक पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के कारण देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, साथ ही लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, **95** करोड़ लीटर तेल आयात में बचत, और **477** करोड़ किलोग्राम CO_2 उत्सर्जन में कमी लाएगा, जो **19** करोड़ पेड़ों के वृक्षारोपण के बराबर है।

संसद समाचार

अप्रैल महीने की राज्यवार महत्वपूर्ण घटनाएँ

आंध्र प्रदेश

- समान आरक्षण लाभों के न्यायसंगत वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों (SCs) की उप-श्रेणीकरण (sub-categorisation) को लागू करने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय "आरक्षण के भीतर आरक्षण" की अवधारणा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों की विभिन्न उप-जातियों के बीच उनकी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति के आधार पर कोटा लाभों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है।
- आंध्र प्रदेश की नियोजित राजधानी अमरावती, सौर, पवन और जल विद्युत पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला शहर बनने जा रही है। कृष्णा नदी के किनारे 217 वर्ग किलोमीटर में फैली इस परियोजना की लागत ₹65,000 करोड़ है, जिसका लक्ष्य 2050 तक 2,700 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है, जिसमें कम से कम 30% सौर और पवन ऊर्जा से होगी।

अरुणाचल प्रदेश

- पूर्वोत्तर भारत में जलविद्युत क्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई एसजेवीएन लिमिटेड (SJVN Ltd) ने अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में 3,097 मेगावाट की एतालिन जलविद्युत परियोजना के लिए ₹269.97 करोड़ की भूमि मुआवजा राशि जारी की है। यह भुगतान 26 मार्च 2025 को दिबांग घाटी के उपायुक्त (DC) और ज़िला भूमि राजस्व एवं निपटान अधिकारी (DLRSO) के संयुक्त खाते में किया गया। यह पहल न केवल नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की योजना को गति प्रदान करती है, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधोसंरचनात्मक विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।

असम

- महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है, जो इसकी सबसे व्यापक उद्यमिता सहायता योजना है। बिश्वनाथ जिले में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य 30 लाख महिलाओं को सशक्त बनाना है।

बिहार

- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने "महिला संवाद" अभियान की शुरुआत की, जो ग्रामीण महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर और नीतिगत चर्चाओं में उनकी आवाज़ को बुलंद करके उन्हें सशक्त बनाने पर केंद्रित एक राज्यव्यापी पहल है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित करना, सार्वजनिक संसाधनों (स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका) के उनके सक्रिय उपयोग को प्रोत्साहित करना और सरकारी अधिकारियों के साथ दो-तरफ़ा संचार चैनल स्थापित करना है।

गुजरात

- गुजरात पुलिस द्वारा शुरू किया गया GP-DRASTI (ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इंटरवेंशन्स) कार्यक्रम राज्य में कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत क्वाडकॉप्टर ड्रोन का उपयोग अपराध की निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और अपराध स्थलों के दस्तावेजीकरण को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा जैसे शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही गैंग गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए तैयार किया गया है।

हरियाणा

- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे राज्य ऐसा प्रावधान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह निर्णय सेवा के बाद अग्निवीरों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक व्यापक योजना के हिस्से के रूप में लिया गया है।.
- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की, जिसमें हरियाणा पुलिस की नौकरियों में 20% आरक्षण शामिल है, जिससे यह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ऐसी गारंटी दी है। इसके अतिरिक्त, स्व-रोजगार के लिए किफायती ऋण और निजी सुरक्षा भूमिकाओं के लिए बंदूक लाइसेंस में प्राथमिकता के प्रावधान पेश किए गए, जिसका उद्देश्य सेवा के बाद अग्निवीरों के भविष्य के कल्याण को सुनिश्चित करना है। ये कदम अग्निवीरों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित दो हड़प्पा सभ्यता स्थलों - मिताथल और तिघराना - को आधिकारिक तौर पर संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। 4,400 साल से भी पुराने ये स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान हैं, जो हड़प्पा और हड़प्पा के बाद के काल में प्रारंभिक कृषि समाजों, नगर नियोजन, शिल्प उद्योगों और व्यापार के विकास पर प्रकाश डालते हैं। हरियाणा प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1964 के तहत हरियाणा विरासत और पर्यटन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से अब इन स्थलों को कानूनी संरक्षण में लाया गया है। इस कदम का उद्देश्य इन प्राचीन बस्तियों को अतिक्रमण और क्षति से बचाना है, साथ ही बाड़ लगाने और सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी।

महाराष्ट्र

- मुगल काल से पहले की विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 8 अप्रैल, 2025 को खुल्ताबाद का नाम बदलकर उसके मूल नाम रत्नापुर करने की घोषणा की है। यह घोषणा सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने की। छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित खुल्ताबाद में औरंगजेब का मकबरा है, साथ ही आजम शाह और आसफ जाह प्रथम की कब्रें भी हैं। मुगल काल के दौरान इसका नाम बदल दिया गया था।
- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई की उपनगरीय रेल सेवाओं को 30% तक बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली कवच 5.0 की घोषणा की। दिसंबर 2025 तक विकसित होने वाला कवच 5.0 सुरक्षा को बढ़ाता है, ऑटो-ब्रेकिंग के साथ लोको पायलटों का समर्थन करता है और प्रतिकूल मौसम में भी सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है।

मध्य प्रदेश

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के तहत चीता परियोजना संचालन समिति ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान से चीतों को लगभग 300 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है, जो एक जुड़े हुए परिदृश्य में 60-70 चीतों की मेटा-आबादी स्थापित करने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। प्रोजेक्ट चीता (2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीतों के साथ लॉन्च) के तहत यह कदम, जगह, शिकार की उपलब्धता पर चिंताओं को संबोधित करता है।

ओडिशा

- सिमिलीपाल, ओडिशा का एक अनोखा और पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र, अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। ओडिशा सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के साथ यह फैसला लिया गया, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ सिमिलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और ओडिशा में भितरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। यह निर्णय राज्य के संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है और "विकसित ओडिशा" की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

पंजाब

- पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, राज्य में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। नंगल को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए प्रारंभिक बजट ₹10 करोड़ निर्धारित किया गया है। वहीं, श्री आनंदपुर साहिब स्थित झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को पंजाब के पहले तेंदुआ सफारी गंतव्य के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ये योजनाएँ 'बदलदा पंजाब' बजट 2025-26 का हिस्सा हैं, जिसे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रस्तुत किया। इस बजट में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के लिए भी विशेष आवंटन किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, जैव विविधता का संरक्षण करना, रोजगार सृजन करना और पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त बनाना है।

तेलंगाना

- तेलंगाना सरकार ने भूमि शासन में ऐतिहासिक सुधार की शुरुआत की है – इसके तहत तेलंगाना भू भारती (अधिकार अभिलेख) अधिनियम, 2025 को लागू किया गया है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती धरनी पोर्टल प्रणाली में आई खामियों और नागरिकों की व्यापक शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। भू भारती अधिनियम का मूल उद्देश्य भूमि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और समावेशी बनाना है। यह अधिनियम विकेंद्रीकरण और नागरिक भागीदारी को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जिससे भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को जनोन्मुखी और भरोसेमंद बनाया जा सके।

तमिलनाडु

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र-राज्य संबंधों, संवैधानिक प्रावधानों और नीतियों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए सुझाव देना है। यह कदम भारतीय संविधान की संघीय भावना के अनुरूप उठाया गया है, खासकर उस पृष्ठभूमि में जब राज्यों की शक्तियों में कटौती को लेकर चिंता बढ़ रही है। तीन सदस्यीय यह समिति जनवरी 2026 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट और दो वर्षों के भीतर अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
- तमिलनाडु ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। राज्य ने 9.69% की दर से विकास किया, जो देश में सबसे अच्छा है और पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु के लिए भी सबसे अधिक है। यह वृद्धि दर्शाती है कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था साल दर साल मजबूत होती जा रही है।

त्रिपुरा

- त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 21 अप्रैल, 2025 को स्वामी विवेकानंद मैदान, अगरतला में 'गरिया और बोरशो बोरोन उत्सव 2025' का उद्घाटन किया। दो दिवसीय उत्सव में गरिया पूजा मनाई जाती है, जो त्रिपुरी और रियांग समुदायों के लिए एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जो शांति और समृद्धि के लिए भगवान शिव को समर्पित है। इस उत्सव में पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, रवींद्र संगीत और जादू के शो के साथ-साथ क्षेत्रीय व्यंजनों को प्रदर्शित करने वाले स्थानीय खाद्य स्टॉल भी शामिल हैं।

उत्तराखंड

- नैनीताल के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत, नैनी झील, जल स्तर में गंभीर गिरावट का सामना कर रही है, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे कम 4.7 फीट पर पहुंच गई है, जिससे संभावित पेयजल की कमी की चिंता बढ़ गई है। झील शहर की 76% पानी की मांग को पूरा करती है, लेकिन कम बारिश, कम बर्फबारी, अनियोजित विकास और प्रदूषण जैसे कारकों ने स्थिति को और खराब कर दिया है। विशेषज्ञ चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्राकृतिक कायाकल्प और सतत विकास प्रथाओं सहित समग्र संरक्षण दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 (जल संरक्षण अभियान) के तहत भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप नागरिकों को नौलों, धाराओं और वर्षा आधारित नदियों जैसे खतरे में पड़े जल स्रोतों की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है, जिससे उनके संरक्षण के लिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलती है। अभियान की थीम, "धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा" जल संसाधनों के संरक्षण के लिए सामूहिक कार्रवाई पर जोर देती है।

पश्चिम बंगाल

- पश्चिम बंगाल में 30 अप्रैल, 2025 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दीघा में जगन्नाथ धाम मंदिर के उद्घाटन के साथ एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की मेजबानी करने की तैयारी है। इस हाई-प्रोफाइल समारोह में लगभग 12,000-14,000 लोग शामिल होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री, राजनीतिक नेता, मशहूर हस्तियां और उद्योगपति जैसे वीआईपी अतिथि शामिल होंगे।

केंद्र शासित प्रदेश

- जम्मू-कश्मीर सरकार ने महिलाओं के लिए एक निःशुल्क बस सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य लैंगिक-समावेशी गतिशीलता को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू की गई इस सेवा के तहत महिलाएं पूरे केंद्र शासित प्रदेश में स्मार्ट सिटी ई-बसों और जेकेआरटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। इस पहल में शहरी क्षेत्रों में 200 ई-बसें और कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों में 235 जेकेआरटीसी बसें शामिल हैं।

शुभारंभ और उद्घाटन:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च, 2025 को MY-Bharat पहल के तहत ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया, जिसमें बच्चों को नए शौक और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अपने मन की बात संबोधन में उन्होंने तकनीकी शिविर, पर्यावरण पाठ्यक्रम और नेतृत्व कार्यक्रम जैसे अवसरों पर प्रकाश डाला। कैलेंडर में जन औषधि केंद्रों के अध्ययन दौरे, सीमावर्ती गांवों का दौरा (वाइब्रेंट विलेज कैंपेन) और सांस्कृतिक और खेल गतिविधियाँ शामिल हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार में 800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर शहरी विकास, सहकारी क्षेत्र, कानून व्यवस्था के बुनियादी ढांचे और परिवहन परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणा की गई।
- नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को "नीति एनसीएईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम" पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पोर्टल राज्यों की वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से संबंधित व्यापक डेटा प्रदान करता है, जिससे राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन और नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

महत्वपूर्ण त्यौहार

- छोटानागपुर क्षेत्र, खास तौर पर झारखंड में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला सरहुल उत्सव, वसंत ऋतु के आगमन और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। 1 अप्रैल, 2025 को आयोजित होने वाला यह उत्सव साल के पेड़ का सम्मान करता है, जिसे गांव की देवी सरना मां का निवास माना जाता है। यह त्यौहार सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, और विशेष रूप से आदिवासी पहचान और अधिकारों को मुखर करने के लिए गहरा सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और राजनीतिक महत्व रखता है।
- पांडिचेरी हेरिटेज फेस्टिवल के 11वें संस्करण की शुरुआत पुडुचेरी के तमिल क्वार्टर में जीवंत 'वीधी विलायट्टू' (स्ट्रीट गेम्स) के साथ हुई, जिसमें 250 से ज़्यादा बच्चे और कई निवासी शामिल हुए। ईश्वरन कोइल और अन्ना सलाई के बीच आयोजित इस फेस्टिवल में शहर की संस्कृति और इतिहास का जश्न मनाया गया, जिसमें पल्लंगुझी, पम्बरम, धयम और पाचा कुथिराई जैसे पारंपरिक खेल शामिल थे। पीपल फॉर पांडिचेरी हेरिटेज और पॉंडीकैन द्वारा सह-आयोजित इस कार्यक्रम ने समुदाय को सफलतापूर्वक जोड़ा, जिसमें पारंपरिक गतिविधियों, भोजन और मौज-मस्ती के साथ सड़कें जीवंत हो उठीं।

- माधवपुर मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने 6 अप्रैल, 2025 को रामनवमी के दौरान भगवान कृष्ण और रुक्मणीजी के दिव्य मिलन के उपलक्ष्य में किया था। पोरबंदर के माधवपुर में आयोजित यह सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एकता और सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक है। 2018 में इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम का दर्जा दिए जाने के बाद से, इस मेले का महत्व बढ़ गया है और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया जैसे गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पटेल ने धार्मिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करते हुए रुक्मणी मंदिर में नई तीर्थ सुविधाओं का भी शुभारंभ किया।

विविध राष्ट्रीय समाचार

- व्यापक वित्तीय समावेशन को समर्थन देने के लिए, इंडिया पोस्ट ने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी की है, ताकि घर-घर जाकर केवाईसी सत्यापन सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिससे सभी के लिए, विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए निवेश प्रक्रिया सरल हो सके।
- ब्रासीलिया में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच एकजुट जलवायु नेतृत्व की जोरदार वकालत की। सतत विकास और 2030 जलवायु एजेंडा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर हासिल करने की रणनीति के रूप में "बाकू से बेलेम रोडमैप" का प्रस्ताव रखा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल, 2025 को छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है, जिसमें व्यापार, संपर्क और आर्थिक सहयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- कारगिल विजय दिवस 2025 समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय सेना द्वारा जुबर स्टेडियम में बटालिक क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना, खेलों को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को जोड़ना था। यह स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देने का भी एक प्रयास था।
- केंद्र सरकार ने देश भर में 440 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) स्थापित करने की एक बड़ी पहल की है। इन विद्यालयों का उद्देश्य आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, खासकर उन ब्लॉकों में जहाँ 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी है।
- राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को 12 घंटे की विस्तृत चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। यह मंजूरी लोकसभा द्वारा 288-232 मतों से विधेयक पारित किए जाने के एक दिन बाद मिली।
- नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय रेलवे ने फरवरी 2025 तक 2,249 स्टेशनों और सेवा भवनों में 209 मेगावाट सौर ऊर्जा सफलतापूर्वक स्थापित की है। यह एक असाधारण वृद्धि दर को दर्शाता है, पिछले 5 वर्षों में 1,489 नए सौर प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं।
- 27 मार्च, 2025 तक केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत केंद्र के हिस्से से कोई धनराशि नहीं मिली है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटन स्वीकृत हो चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में CPI(M) MP जॉन ब्रिटास द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में यह खुलासा किया।
- भारत सरकार ने बिहार में दो परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचे की पहलों को हरी झंडी दे दी है – पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर और कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना। इन परियोजनाओं को पीएम के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने मंजूरी दे दी है।
- नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को "नीति एनसीएईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम" पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पोर्टल राज्यों की वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से संबंधित व्यापक डेटा प्रदान करता है, जिससे राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन और नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
- मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली को एक बड़ी तकनीकी मजबूती देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 'कवच 5.0' नामक अगली पीढ़ी की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की है। यह उन्नत प्रणाली ट्रेन की आवृत्ति में 30% तक की वृद्धि करने में सहायक होगी, जिससे लगभग 80 लाख दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। 'कवच' न केवल खराब मौसम के दौरान ट्रेन की सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि यदि लोको पायलट समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता है तो यह अपने आप ब्रेक लगाकर संभावित दुर्घटना को रोकने में सक्षम है। यह कदम रेलवे संचालन को और अधिक सुरक्षित, सुगम और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) ने अपने 75वें वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया, जिसे ढाका में भारत के हाई कमीशन के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। इस समारोह में 1950 में स्थापना के बाद से ICCR की विरासत, सांस्कृतिक कूटनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, और भारत-बांग्लादेश सांस्कृतिक संबंधों में इसके गहरे योगदान को उजागर किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक प्रस्तुतियाँ शामिल थीं और इसमें दोनों देशों के बीच कलात्मक एवं शैक्षिक पहलों के जीवंत आदान-प्रदान को भी प्रदर्शित किया गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ₹3,880 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा, कानून व्यवस्था, जनकल्याण और सांस्कृतिक विरासत जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इनका उद्देश्य वाराणसी को एक आधुनिक शहर में परिवर्तित करना है, साथ ही इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना भी है। इसके अंतर्गत कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, और कारीगरों, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों तथा छोटे व्यवसायों के कल्याण को सुनिश्चित करना शामिल है।
- भारत की हरित ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं काफी हद तक उन महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं, जो सौर पैनल, पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी भंडारण जैसी तकनीकों के लिए अनिवार्य हैं। इन आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission – NCMM) की शुरुआत की है।

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया और पुर्तगाल की चार दिवसीय राजकीय यात्रा के अंतिम दिन स्लोवाकिया के नित्रा शहर स्थित कॉन्स्टैंटाइन द फिलॉसॉफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें उनके उल्लेखनीय सार्वजनिक सेवा कार्य, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, तथा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के समर्थन के लिए प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत की वैश्विक नेतृत्व में बढ़ती प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं समावेशी शासन के प्रतिनिधित्व में राष्ट्रपति मुर्मू की अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा ने हाल ही में भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को रूपांतरित करने के सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत इंटर-एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली द्वारा देश में ही विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य मरीजों के रेफरल सिस्टम को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करना है।
- भारत की हरित ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं काफी हद तक उन महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं, जो सौर पैनल, पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी भंडारण जैसी तकनीकों के लिए अनिवार्य हैं। इन आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission – NCMM) की शुरुआत की है। यह मिशन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के नेतृत्व में और खनन मंत्रालय के समन्वय में संचालित किया जा रहा है।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया और पुर्तगाल की चार दिवसीय राजकीय यात्रा के अंतिम दिन स्लोवाकिया के नित्रा शहर स्थित कॉन्स्टैंटाइन द फिलॉसॉफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें उनके उल्लेखनीय सार्वजनिक सेवा कार्य, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, तथा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के समर्थन के लिए प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत की वैश्विक नेतृत्व में बढ़ती प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं समावेशी शासन के प्रतिनिधित्व में राष्ट्रपति मुर्मू की अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा ने हाल ही में भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को रूपांतरित करने के सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत इंटर-एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली द्वारा देश में ही विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य मरीजों के रेफरल सिस्टम को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करना है।
- वैश्विक विस्तार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद दुबई में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने जा रहा है। यह निर्णय IIM-अहमदाबाद और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सरकार के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के बाद लिया गया है। यह पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की उच्च शिक्षा की पहुंच को मजबूत बनाएगी। दुबई कैंपस में शुरुआत में वैश्विक पेशेवरों और उद्यमियों के लिए एक वर्षीय पूर्णकालिक MBA प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
- भारत द्वारा अफ्रीकी चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क (KNP) में फिर से जंगल में बसाए जाने के दो साल बाद, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 20 अप्रैल 2025 को हासिल होगी, जब दो वयस्क चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (GSWS) में स्थानांतरित किया जाएगा। यह कदम चीता पुनर्वास परियोजना के विस्तार का प्रतीक है और मंदसौर जिले में स्थित GSWS को चीतों के लिए दूसरा घर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। यह निर्णय चीता परियोजना की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया और यह केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच संरक्षण, अनुसंधान और ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो रहे साझा प्रयास को दर्शाता है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। यह भारत के समुद्री अवसंरचना क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, क्योंकि यह देश का पहला सेमी-ऑटोमेटेड और वास्तविक डीप-वॉटर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। यह परियोजना केरल सरकार, केंद्र सरकार और अडानी पोर्ट्स के बीच एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के तहत विकसित की गई है। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के निकट स्थित इस बंदरगाह से भारत की व्यापारिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है और यह केरल को एक प्रमुख समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
- कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि 1 मई 2025 से मौजूदा फास्टैग आधारित टोल संग्रह प्रणाली को हटाकर उपग्रह आधारित टोल प्रणाली शुरू की जाएगी। इन दावों को खारिज करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने इसके विपरीत, कुछ चयनित टोल प्लाज़ाओं पर एक उन्नत एएनपीआर-फास्टैग आधारित बिना बाधा वाली टोलिंग प्रणाली (Barrier-Less Tolling System) के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है।
- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से आग्रह किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की अब तक की पहली थर्ड-पार्टी मूल्यांकन प्रक्रिया वर्ष 2025 के अंत तक पूरी कर ली जाए। समिति ने यह भी जोर दिया कि नवंबर 1995 में शुरू हुई इस योजना के तहत दी जा रही न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,000 को अब महंगाई में आई तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए।
- केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली स्थित नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी (NDTL) में एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट (APMU) का उद्घाटन किया। यह पहल भारत के एंटी-डोपिंग प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देती है, जिससे देश अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होता है और निष्पक्ष, स्वच्छ और नैतिक खेलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
- भारतीय विमानन क्षेत्र 2026 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बड़ा विमानन बाजार बनने की ओर अग्रसर है, ऐसा एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) का कहना है। हालांकि कुल विमानन बाजार के आकार में चीन अभी भी काफी आगे है, लेकिन भारत की तेज़ी से होती वृद्धि का कारण है देश की विशाल आबादी में बढ़ती हवाई यात्रा की मांग, जहाँ प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा अभी भी बहुत कम है। बढ़ते बुनियादी ढांचे का विकास, नीतिगत सुधार और मध्यम वर्ग की बढ़ती आकांक्षाएं इस वृद्धि को और गति दे रही हैं। अगले तीन दशकों

में, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में बना रहेगा, लेकिन विकास दर के मामले में यह शीर्ष पर रहेगा।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2025 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में माता-पिता को सख्त चेतावनी दी है, जिससे बच्चों की तस्करी के बढ़ते खतरे के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि तस्करी के गिरोह बच्चों को यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी, बाल विवाह और अवैध गोद लेने जैसे अपराधों के लिए शिकार बना रहे हैं। अदालत ने विशेष रूप से यह चिंता व्यक्त की कि अब ये आपराधिक नेटवर्क तकनीक का दुरुपयोग करके अपने जाल फैला रहे हैं, जबकि सरकारी और संस्थागत उपाय अभी भी इन चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को सरल बनाने और पर्यावरणीय सेवाओं में अहम भूमिका निभाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने उद्योगों के लिए एक नया वर्गीकरण लागू किया है। इस संशोधित श्रेणीकरण में "आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं" (Essential Environmental Services – EES) के लिए एक नई 'ब्लू श्रेणी' बनाई गई है। इस ब्लू श्रेणी में वे उद्योग शामिल हैं जो पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सीधे योगदान करते हैं, जैसे वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र, बायोमाइनिंग इकाइयाँ, और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र। इन उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण की मंज़ूरी (consent) की अवधि लंबी दी जाएगी, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।
- भारत अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विदेशी कंपनियों को 49% तक हिस्सेदारी लेने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है, जो कि देश के सबसे संरक्षित क्षेत्रों में से एक के लिए एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन है। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने, कोयले पर निर्भरता को कम करने और महत्वाकांक्षी कार्बन उत्सर्जन कमी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
- कैलाश मानसरोवर यात्रा (केएमवाई) एक महत्वपूर्ण वार्षिक तीर्थयात्रा है, जो भारत और चीन के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक मानी जाती है। यह यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। माना जाता है कि माउंट कैलाश की परिक्रमा करने से आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है, जबकि मानसरोवर झील में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह तीर्थयात्रा 2020 में COVID-19 महामारी और सीमा तनावों के कारण स्थगित कर दी गई थी। पांच वर्षों के बाद इसका पुनः आरंभ होना धार्मिक पर्यटन और द्विपक्षीय सहयोग में एक सकारात्मक विकास का संकेत है।
- भारतीय उच्च शिक्षा और कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत, पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से "डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी" का दर्जा प्रदान किया गया है। यह कदम संस्थान की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होता है और सिनेमा व टेलीविज़न अध्ययन के क्षेत्र में शैक्षणिक स्वायत्तता, पाठ्यक्रम में लचीलापन और शोध नवाचार के लिए नए द्वार खोलता है।
- राजनयिक और सैन्य तनावों के बीच एक बड़े घटनाक्रम में, पाकिस्तान ने 1972 की शिमला समझौता को निलंबित कर दिया है। साथ ही, वाघा बॉर्डर को बंद, भारत के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियाँ रोक दी गई हैं, और भारतीय एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने और राजनयिक संबंधों को घटाने के जवाब में लिया गया है। इन कदमों की पृष्ठभूमि में पहलगाम आतंकी हमले की त्रासदी है, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। जैसे-जैसे दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, सभी मौजूदा द्विपक्षीय समझौते और संवाद तंत्र ठप हो चुके हैं।
- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें एक विदेशी नागरिक सहित 26 लोगों की जान गई, के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए हैं। भारत ने इस हमले में सीमा पार आतंकवाद की स्पष्ट संलिप्तता के प्रमाणों का हवाला देते हुए त्वरित कार्रवाई की है। यह निर्णय भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा इकाई—कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS)—की आपात बैठक में लिए गए। इस बैठक में एक पाँच-सूत्रीय रणनीतिक कार्ययोजना को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करना और भारत में उसकी किसी भी प्रकार की गतिविधि और प्रभाव को सीमित करना है।
- भारत और पाकिस्तान, जो कि पड़ोसी होने के बावजूद अक्सर कूटनीतिक रूप से तनावपूर्ण संबंधों में रहते हैं, के बीच व्यापार हमेशा सीमित रहा है, फिर भी यह महत्वपूर्ण रहा है। ऐतिहासिक रूप से, राजनीतिक तनावों के कारण दोनों देशों के वैश्विक व्यापार में एक-दूसरे के साथ व्यापार की हिस्सेदारी बेहद कम रही है, लेकिन कुछ खास वस्तुएं ऐसी रही हैं जो पाकिस्तान से भारत को लगातार निर्यात होती रही हैं।
- एक नाटकीय बदलाव के तहत, भारत ने 1960 में लागू हुई सिंधु जल संधि (इंडस वॉटर ट्रीटी) को पहली बार निलंबित कर दिया है, जिसके दूरगामी भू-राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। यह कदम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद उठाया गया, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली। यह हमला मुंबई 26/11 के बाद सबसे भीषण नागरिक हमला माना जा रहा है।

सरकारी योजनाएँ

केंद्र सरकार की योजना

पहल का नाम	उद्देश्य
मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम (SMILE)	• भारत के लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, लागत को कम करना और दक्षता में वृद्धि करना। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) और पीएम गतिशक्ति का समर्थन करता है तथा मल्टीमॉडल परिवहन, वेयरहाउसिंग मानकीकरण और डिजिटल व्यापार लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देता है।
"एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)" नीति	• 43 मौजूदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 28 में समेकित कर परिचालन दक्षता बढ़ाना और आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करना। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह और सेवा वितरण को बेहतर बनाना है। इस नीति से लागत में कटौती और बैंकिंग ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)	• 5 अप्रैल 2025 को दिल्ली ने इस योजना को लागू किया, जिससे यह 35वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बना। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)	• 8 अप्रैल 2025 को इस योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह योजना बिना गारंटी के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान कर 'वित्त पोषण का लोकतंत्रीकरण' करती है और ग्रामीण भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देती है। अब तक 52 करोड़ ऋण ₹32.61 लाख करोड़ की राशि में स्वीकृत हुए हैं।
सागरमाला कार्यक्रम	• मार्च 2015 में शुरू की गई यह योजना भारत के समुद्री क्षेत्र को परिवर्तित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यह बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, संपर्क बढ़ाना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, और तटीय तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को कम कर व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करना चाहती है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS)	• वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत मजदूरी दरों में 2.33% से 7.48% तक की वृद्धि की गई है। यह पहली बार है जब किसी राज्य में मजदूरी ₹400 प्रति दिन तक पहुँची है, जिसमें हरियाणा को सबसे अधिक बढ़ोतरी मिली है।

राज्य सरकार की योजना

पहल का नाम	उद्देश्य
स्वर्ण आंध्र - 2047 विजन	• "शून्य गरीबी – P4 नीति" की शुरुआत उगादी (30 मार्च 2025) को की जाएगी, जिसका उद्देश्य 2047 तक गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना है। यह सार्वजनिक-निजी-जन सहभागिता (P4 मॉडल) पर आधारित है और आवास, स्वच्छता, जलापूर्ति, एलपीजी, विश्वसनीय बिजली, हाई-स्पीड इंटरनेट और उद्यमिता पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (असम)	• 1 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा शुरू की गई यह योजना महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करती है। पहले वर्ष ₹10,000 की सहायता, दूसरे वर्ष ₹25,000, और तीसरे वर्ष ₹50,000 दी जाएगी। इसका लक्ष्य 30 लाख महिलाओं को सशक्त बनाना है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना	• 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई इस योजना ने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को नए व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब तक ₹61,000 करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे आर्थिक समावेशन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है।
उत्तर प्रदेश: 'शून्य गरीबी मिशन'	• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अप्रैल 2025 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर इस मिशन की घोषणा की। इसका उद्देश्य वंचित वर्गों (जैसे मुसहर, थारू, कोल आदि) को सभी सरकारी लाभ प्रदान कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है।
पिंक ई-रिक्शा पहल (महाराष्ट्र)	• डिप्टी सीएम अजित पवार द्वारा शुरू की गई यह योजना 20–50 वर्ष की महिलाओं (विशेष रूप से विधवा, तलाकशुदा, निम्न-आय वर्ग) को 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शा वितरित करती है। इसमें ₹1 लाख की सब्सिडी और कम ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध है।
यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना (कर्नाटक)	• ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने हेतु इस योजना में जटिल उपचारों के लिए 50% और सामान्य प्रक्रियाओं के लिए 15%–25% दर वृद्धि प्रस्तावित है। 69 नई प्रक्रियाएं जोड़ी जाएंगी और 6 पुरानी हटेंगी। कुल अनुमानित लागत ₹127.5 करोड़ है, जिसमें ₹40 करोड़ अतिरिक्त बजट प्रस्तावित है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

- 4 अप्रैल, 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले दो वर्षों के लिए BIMSTEC का नया अध्यक्ष बन गया। इसे पिछले अध्यक्ष थाईलैंड से नेतृत्व प्राप्त हुआ। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने अध्यक्षता स्वीकार की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश BIMSTEC को अधिक समावेशी (सभी को शामिल करना) और कार्रवाई-उन्मुख (वास्तविक परिणामों पर केंद्रित) बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जैसा कि UNCTAD के वैश्विक 'अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए तत्परता' सूचकांक में 36वें स्थान पर पहुंचने से पता चलता है। यह 2022 में 48वें स्थान से एक बड़ी छलांग है, जो अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में प्रगति से प्रेरित है।
- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित "रेसीप्रोकल टैरिफ" नीति एक बार फिर सुर्खियों में है। इस प्रस्तावित टैरिफ ढांचे के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय निर्यात पर 27% समायोजित पारस्परिक टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे अमेरिकी मार्क में भारतीय वस्तुओं की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित "रेसीप्रोकल टैरिफ" नीति एक बार फिर सुर्खियों में है।
- ब्राजील ने वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद बनाने का प्रस्ताव यूएनएफसीसीसी ढांचे के भीतर पेश किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु पहलों को गति देना है। यह प्रस्ताव नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित होने वाले COP30 से पहले आया है। परिषद को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- तेल-समृद्ध मध्य अफ्रीकी देश गैबॉन 12 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार है, जिसमें तख्तापलट के प्रमुख ब्राइस ओलिगुई नगुएमा को प्रमुख उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। यह चुनाव अगस्त 2023 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद देश के सैन्य शासन से नागरिक शासन की ओर परिवर्तन की दिशा में एक निर्णायक क्षण है, जिसने बॉन्गो परिवार के पाँच दशकों से अधिक समय के शासन का अंत किया था।
- वैश्विक व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकांश देशों के लिए हाल ही में लगाए गए उच्च टैरिफ़ पर 90 दिनों की रोक लगाने की घोषणा की है। इस फैसले से अमेरिका के कई व्यापारिक साझेदारों को कुछ राहत मिली है। हालांकि, यह रोक चीन पर लागू नहीं होती।
- अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ने गंभीर रूप धारण कर लिया है, क्योंकि चीन ने जवाबी टैरिफ में भारी वृद्धि की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी आयात पर 104% शुल्क लगाए जाने के जवाब में, चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 84% तक कर दिए हैं। यह निर्णय दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को एक नए स्तर पर ले गया है। इस बढ़ती टकराव की स्थिति में, चीन ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें निर्यात नियंत्रण लागू करना, अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में शामिल करना, और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराना शामिल है। यह व्यापार युद्ध न केवल द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वैश्विक व्यापार प्रणाली पर भी गहरा असर डाल सकता है।
- एक उल्लेखनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि के तहत, वेस्ट जापान रेलवे कंपनी (JR वेस्ट) ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, जिसे वाकायामा प्रीफेक्चर के अरिदा सिटी में मात्र छह घंटे से भी कम समय में स्थापित किया गया। इस स्टेशन का नाम हात्सुशिमा स्टेशन है और यह 1948 से सेवा दे रहे एक पुराने लकड़ी के स्टेशन की जगह लेता है। यह परियोजना सार्वजनिक अवसंरचना में 3D प्रिंटिंग की क्रांतिकारी संभावनाओं को दर्शाती है।
- भारत ने सिएरा लियोन में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक परियोजना हेतु 9.90 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस पहल का नाम है "सिएरा लियोन में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सक्षम करना", जिसे भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के तहत समर्थन प्राप्त है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से लागू किया जा रहा है। यह परियोजना सिएरा लियोन की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है और समावेशी विकास, सततता तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- मॉरीशस ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस (ISA) के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश और विश्व स्तर पर चौथा देश बन गया है। इस रणनीतिक समझौते का उद्देश्य ISA और मॉरीशस के बीच स्वच्छ ऊर्जा पहलों पर, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है, जो राष्ट्र के सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के अनुरूप है। CPF दीर्घकालिक सौर ऊर्जा सहयोग के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा, जिसमें नवोन्मेषी और पैमाने योग्य तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- न्यूयॉर्क सिटी में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मेयर एरिक एडम्स ने 14 अप्रैल 2025 को आधिकारिक रूप से "डॉ. भीमराव अंबेडकर दिवस" घोषित किया। यह घोषणा भारत के संविधान निर्माता और महान समाज सुधारक डॉ. अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर की गई, जो उनके मानवाधिकार, न्याय और समानता के लिए किए गए योगदान को वैश्विक मान्यता प्रदान करती है।
- वन्यजीव संरक्षण में भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका को सशक्त करते हुए, भारत सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत IBCA का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। यह समझौता दुनिया की सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों — बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा — के संरक्षण के प्रति भारत की गहन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया IBCA, इन संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण, अनुसंधान और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करेगा।

- चीन ने सात दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (Rare Earth Elements – REEs) के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे पहले से ही अस्थिर वैश्विक व्यापार माहौल में तनाव और बढ़ गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब अमेरिका ने अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर नए शुल्क लगाए हैं।चीन लंबे समय से दुर्लभ पृथ्वी खनन और परिशोधन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी रहा है, और ये तत्व इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों और सैन्य तकनीकों के निर्माण में बेहद आवश्यक हैं। इन प्रतिबंधों के चलते वैश्विक उद्योगों पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दुनिया के विभिन्न देशों को अब अपने आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और चीनी निर्यात पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है।
- जनरल ब्राइस ओलिगी नगुएमा ने गैबॉन के राष्ट्रपति चुनाव में 90% से अधिक मतों के साथ जीत दर्ज की है, जिससे मध्य अफ्रीकी देश पर उनकी पकड़ और मजबूत हुई है। यह विजय 2023 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद आई है, जिसमें नगुएमा ने दशकों से सत्ता में रही बोंगो वंश को सत्ता से हटा दिया था। तख्तापलट के समय उन्होंने सत्ता छोड़ने का वादा किया था, लेकिन नए चुनावी नियमों के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा, जो सैन्य अधिकारियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। गैबॉन, जो तेल और खनिज संसाधनों से समृद्ध है, अब भी असमानता और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, जिन्हें नगुएमा को अपने सात साल के कार्यकाल में सुलझाना होगा।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने महामारी संधि (Pandemic Treaty) के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है, जो वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक समझौता है। यह प्रस्ताव अंतर-सरकारी वार्ताकार निकाय (Intergovernmental Negotiating Body – INB) द्वारा तैयार किया गया है और इसे 19 मई 2025 को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) में प्रस्तुत किया जाएगा। यह समझौता व्यापक बातचीत के बाद सामने आया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए भविष्य के स्वास्थ्य संकटों के प्रति समान और त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करना है।
- इक्वाडोर के दक्षिणपंथी मौजूदा राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने दूसरे दौर के राष्ट्रपति रन-ऑफ चुनाव में जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ उन्हें पूर्ण चार वर्षीय कार्यकाल मिला है। नोबोआ ने अपनी वामपंथी प्रतिद्वंद्वी लुइसा गोंजालेज़ को बड़े अंतर से हराया, जो देश में बढ़ती नशीली तस्करी से जुड़ी हिंसा और आर्थिक अस्थिरता के बीच जनता की चिंताओं को दर्शाता है। राष्ट्रीय चुनाव परिषद ने परिणामों की घोषणा की, हालांकि लुइसा गोंजालेज़ ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए पुनर्मतगणना की मांग की है।
- अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच, बीजिंग ने अपने प्रमुख एयरलाइनों को बोइंग विमान की खरीद और डिलीवरी रोकने का निर्देश दिया है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर 145% शुल्क लगाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। यह निर्णय न केवल व्यापारिक टकराव को और गहराता है, बल्कि वैश्विक विमानन उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक संरचना को भी बदलता है। इससे एयरबस और चीन की अपनी विमान निर्माता कंपनी COMAC जैसे बोइंग के प्रतिद्वंद्वियों के लिए नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।.
- ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल 2025 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय को मिलने वाली लगभग 2.3 अरब डॉलर की संघीय निधि को रोक दिया, क्योंकि संस्थान ने उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया जो उसकी आंतरिक नीतियों में बड़े बदलाव लाने के लिए रखी गई थीं। इन मांगों में विविधता, समानता और समावेशन (DEI) कार्यक्रमों को बंद करना और योग्यता आधारित सुधारों को लागू करना शामिल था। इस टकराव ने देशभर में अकादमिक स्वतंत्रता, सरकारी हस्तक्षेप, यहूदी विरोध (Antisemitism), और निजी संस्थानों पर कार्यकारी अधिकार की कानूनी सीमाओं को लेकर एक व्यापक बहस छेड़ दी है। हार्वर्ड सहित अन्य आइवी लीग विश्वविद्यालयों ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और इन मांगों को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है।
- चीन ने हाल ही में एक क्रांतिकारी प्रकार के हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है, जो पारंपरिक विखंडनीय पदार्थों जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम के बिना कार्य करता है। इसके बजाय, यह मैग्नीशियम हाइड्राइड-आधारित फ्यूजन जैसी उन्नत संलयन तकनीकों का उपयोग करता है। इस विकास ने हथियार नियंत्रण, अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। यह प्रगति आधुनिक युद्ध में परमाणु हथियारों की धारणा और उनके नियमन को पूरी तरह से पुनर्परिभाषित कर सकती है।
- यूनेस्को ने 17 अप्रैल 2025 को 16 नए वैश्विक जियोपार्क्स (Global Geoparks) को मान्यता दी, जिससे अब विश्वभर में ऐसे जियोपार्क्स की कुल संख्या 50 देशों में 229 हो गई है। यह नेटवर्क अब लगभग 8,55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो नामीबिया देश के आकार के बराबर है। नए घोषित जियोपार्क्स एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फैले हैं और इन्हें उनकी अद्वितीय भूवैज्ञानिक धरोहर के लिए मान्यता दी गई है, जिसमें ज्वालामुखीय श्रृंखलाएं, प्राचीन चट्टानी संरचनाएं, पर्वतीय क्षेत्र, जीवाश्म स्थल और रेगिस्तानी परिदृश्य शामिल हैं। ये स्थल न केवल भूवैज्ञानिक चमत्कारों के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, बल्कि पर्यावरणीय शिक्षा, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने 21 अप्रैल 2025 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की शुरुआत की। नई दिल्ली स्थित पालम एयरपोर्ट पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके साथ सेकंड लेडी उषा वांस और उनके बच्चे भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चार दिवसीय इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, रक्षा और आर्थिक साझेदारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को गहराना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक भी निर्धारित है, जो भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती गति को दर्शाती है।
- सतत शहरी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, आंध्र प्रदेश की नियोजित राजधानी अमरावती दुनिया का पहला ऐसा शहर बनने की ओर अग्रसर है, जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा परिकल्पित यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण-संवेदनशील शहरीकरण की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच स्थित अमरावती को एक आधुनिक, पर्यावरण-मित्र "जनता की राजधानी" के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो सतत शहर नियोजन में वैश्विक मानक स्थापित करने की दिशा में एक प्रेरणास्रोत बनेगा।

बैंकिंग और फाइनेंस

क्रम संख्या	बैंक का नाम	उद्देश्य / पहल का विवरण
1.	एक्सिस बैंक	जे.पी. मॉर्गन और उसकी ब्लॉकचेन यूनिट किनेक्सिस के साथ साझेदारी में, GIFT सिटी से भारत की पहली 24x7 यूएस डॉलर भुगतान सेवा वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए शुरू की। यह रीयल-टाइम डॉलर क्लियरिंग सुविधा तरलता प्रबंधन को बेहतर बनाती है, लागत कम करती है, और मध्य पूर्व देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देती है।
2.	बंधन बैंक	अप्रैल 2025 में "एलीट प्लस सेविंग्स अकाउंट" शुरू किया गया, जो उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (HNIs) के लिए है। इसमें असीमित नकद जमा और विस्तारित बीमा कवरेज जैसी सुविधाएँ हैं।
3.	एसबीआई कार्ड	टाटा डिजिटल के साथ साझेदारी में "टाटा न्यू एसबीआई कार्ड" लॉन्च किया – दो संस्करण: टाटा न्यू प्लस और टाटा न्यू इनफिनिटी। दोनों कार्ड पर टाटा न्यू और सहयोगी ब्रांडों पर खर्च पर 10% तक इनाम (न्यूकॉइन्स), लाउंज एक्सेस, सालाना शुल्क में छूट और बिल भुगतान पर कैशबैक जैसी सुविधाएँ हैं।
4.	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	15 अप्रैल 2025 से "अमृत वृष्टि एफडी योजना" फिर से शुरू की गई। वरिष्ठ नागरिकों को 7.55%, अति-वरिष्ठ नागरिकों को 7.65% और आम नागरिकों को 7.05% ब्याज दर मिलती है (444 दिनों की अवधि के लिए)। यह योजना बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और उच्च-रिटर्न निवेश विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से है।
5.	पंजाब नेशनल बैंक (PNB)	12 अप्रैल 2025 को 131वें स्थापना दिवस पर 34 नए उत्पाद/सेवाएं लॉन्च की गईं। इनमें महिलाओं, किसानों, एनआरआई और पेंशनरों के लिए 12 जमा योजनाएँ, 10 डिजिटल टूल (जैसे AI सहायक "पिहू", QR आधारित फीडबैक सिस्टम) और "साइबर रन" हाफ मैराथन जैसी पहलें शामिल हैं।
6.	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	शाखाओं पर प्रशिक्षित 'ग्राहक मित्रों' की नियुक्ति की गई, जो डिजिटल बैंकिंग और सेल्फ-सर्विस प्लेटफार्मों में ग्राहकों की सहायता करते हैं। उद्देश्य शाखाओं की भीड़ कम करना और वैकल्पिक बैंकिंग चैनलों को बढ़ावा देना है।

आरबीआई समाचार

विनियामक प्राधिकरणों से संबंधित करेंट अफेयर्स		
क्रम संख्या	**संस्था का नाम**	**उद्देश्य / पहल का विवरण**
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• वर्ष 2025 में RBI ने अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। प्रमुख मील के पत्थर: 1991 में आर्थिक उदारीकरण, और हाल की डिजिटल भुगतान व वित्तीय समावेशन में प्रगति।
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• 2 अप्रैल 2025 को RBI ने बताया कि ₹2000 के 98.21% नोट बैंकिंग प्रणाली में लौटाए जा चुके हैं। यह नोट 2016 में विमुद्रीकरण के बाद जारी हुए थे, और 2023 में RBI ने इन्हें चलन से हटाने की घोषणा की थी।
3.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• 1 अप्रैल 2025 से, 500 शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को SAF से PCA फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। यह कदम समय पर हस्तक्षेप और वित्तीय स्थिरता की बहाली के उद्देश्य से है।
4.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• RBI ने सरकारी गारंटीशुदा सिक्योरिटी रिसीट्स (SRs) के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे खराब ऋणों के समाधान और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। इसमें पूंजी उपचार और वैल्यूएशन पद्धति में बदलाव शामिल हैं।
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• 1 मई 2025 से एटीएम से मुफ्त सीमा से अधिक निकासी पर शुल्क ₹21 से बढ़ाकर ₹23 किया गया है। यह नियम नकद पुनर्चक्रण मशीनों पर भी लागू होगा (नकद जमा को छोड़कर)। उद्देश्य: एटीएम रखरखाव लागत की भरपाई।
6.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) की सीमाएँ यथावत रहेंगी: केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के लिए 6%, राज्य विकास ऋणों के लिए 2% और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए 15%। उद्देश्य: स्थिर निवेश वातावरण बनाए रखना।
7.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• NPCI को UPI P2M लेनदेन की सीमा बढ़ाने की अनुमति दी गई है (शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसे क्षेत्रों में ₹2–5 लाख तक)। P2P सीमा ₹1 लाख यथावत है। यह कदम डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
8.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• 'RBI कहता है' अभियान के तहत RBI ने अपना ऑफिशियल WhatsApp चैनल लॉन्च किया है, जिससे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकथाम को बढ़ावा मिलेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
9.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• अजन्ता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, औरंगाबाद का लाइसेंस 22 अप्रैल 2025 से रद्द किया गया, पूंजी की कमी और जमा धन की सुरक्षा में विफलता के कारण। 91.55% जमाकर्ताओं को DICGC योजना के तहत ₹5 लाख तक का बीमा मिलेगा।

विनियामक प्राधिकरणों से संबंधित करेंट अफेयर्स		
क्रम संख्या	**संस्था का नाम**	**उद्देश्य / पहल का विवरण**
10.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• सभी बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी वेबसाइट का डोमेन '.bank.in' पर स्थानांतरित करना अनिवार्य किया गया है। उद्देश्य: साइबर सुरक्षा बढ़ाना और धोखाधड़ी को रोकना। IDRBT को एकमात्र रजिस्ट्रार बनाया गया है।
11.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• अब 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चे स्वतंत्र रूप से बचत खाता और सावधि जमा खाता खोल सकते हैं। यह वित्तीय साक्षरता को प्रारंभिक स्तर से प्रोत्साहित करने के लिए है। बैंकों को जोखिम नीति के आधार पर अनुमति देनी होगी।

सेबी समाचार

क्रम संख्या	घोषणा	मुख्य विवरण
1.	सेबी (SEBI)	• ओवरनाइट और लिक्विड म्यूचुअल फंड योजनाओं में रिडेम्प्शन की कट-ऑफ टाइमिंग संशोधित की गई है, जो 1 जून 2025 से लागू होगी। यह Upstreaming Framework (दिसंबर 2023) के तहत लागू किया गया है ताकि निवेशकों के फंड की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऑफलाइन मोड के लिए कट-ऑफ समय दोपहर 3:00 बजे है, जबकि ऑनलाइन मोड (केवल ओवरनाइट फंड्स) के लिए इसे शाम 7:00 बजे तक बढ़ाया गया है ताकि उसी दिन का NAV प्राप्त किया जा सके। यह कदम AMFI और सेबी की म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति के समर्थन से उठाया गया है। इसका उद्देश्य कोलेटरल के बेहतर उपयोग और निवेशकों के फंड की सुरक्षा को मजबूत करना है।

अर्थव्यवस्था और व्यापार

अप्रैल 2024 के अनुसार जीडीपी और विकास दर

- भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) की सीमा में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। अपरिवर्तित सीमा – केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 6%, राज्य ऋणों के लिए 2% और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए 15% हैं।
- भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह मार्च 2025 में साल-दर-साल (YoY) 9.9% की मजबूत वृद्धि के साथ ₹1.96 लाख करोड़ तक पहुँच गया। यह वृद्धि मजबूत आर्थिक गतिविधियों और कर अनुपालन में सुधार को दर्शाती है।
- भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि फरवरी 2025 में घटकर 2.9% रह गई, जो पिछले पांच महीनों में सबसे धीमी दर है। यह गिरावट फरवरी 2024 में दर्ज 7.1% की वृद्धि की तुलना में काफी कम है। आठ प्रमुख उद्योगों में से केवल तीन उद्योगों में मासिक उत्पादन में वृद्धि हुई, जबकि सिर्फ सीमेंट और उर्वरक ऐसे क्षेत्र थे, जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उत्पादन दर्ज किया। कोर सेक्टर में यह मंदी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है, जिसने जनवरी 2025 में 5% की वृद्धि दर्ज की थी।
- भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद लचीलेपन के साथ वृद्धि दर्ज कर रही है। एशियाई विकास आउटलुक (ADO) अप्रैल 2025 के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण घरेलू मांग में वृद्धि, ग्रामीण आय में सुधार, और मुद्रास्फीति में नरमी है। एशियाई विकास बैंक (ADB) का मानना है कि यह वृद्धि की गति वित्त वर्ष 2026 में भी बनी रहेगी, और GDP वृद्धि दर 6.8% रहने की संभावना है। इसका समर्थन अनुकूल राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों से होगा। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों और नीतिगत अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए अपना अनुमान थोड़ा घटाकर 6.5% कर दिया है।
- भारत की औद्योगिक गतिविधि फरवरी 2025 में स्पष्ट रूप से धीमी पड़ी, जहाँ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) केवल 2.9% की वृद्धि दर्ज कर पाया — जो कि पिछले छह महीनों में सबसे कम है। यह गिरावट मुख्यतः खनन, निर्माण और बिजली क्षेत्रों में सुस्त वृद्धि और पिछले वर्ष के उच्च आधार प्रभाव के कारण देखी गई। हालांकि अधिकांश उपयोग-आधारित वर्गों में उत्पादन कम हुआ, लेकिन पूंजीगत वस्तुएं एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहीं जहाँ उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नए वित्तीय वर्ष की पहली नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों में कटौती की घोषणा की है। 7 से 9 अप्रैल 2025 के बीच हुई 54वीं बैठक में समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6% करने का निर्णय लिया, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी (SDF) दर को 5.75% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) व बैंक दर को 6.25% कर दिया गया है।
- भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति मार्च 2025 में घटकर 2.05% रह गई, जो फरवरी 2025 में 2.38% थी। यह जानकारी 15 अप्रैल 2025 को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में दी गई। मुद्रास्फीति में यह गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों की कीमतों में तीव्र गिरावट के कारण हुई, जिससे सब्जियों में 15.88% की ऋणात्मक मुद्रास्फीति (deflation) दर्ज की गई। हालांकि खाद्य वस्तुओं में कुल मिलाकर मुद्रास्फीति में कमी आई, लेकिन निर्मित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि देखी गई। मार्च में निर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति 3.07% रही, जो फरवरी में 2.86% थी। आंकड़ों से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति मिश्रित रही—एक ओर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई, वहीं ईंधन, बिजली और निर्मित वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में दाम बढ़े।

- भारत के बैंकिंग क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में 12-13% की ऋण वृद्धि (क्रेडिट ग्रोथ) होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए अनुमानित 11-11.5% वृद्धि से थोड़ा अधिक है। क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा साझा की गई इस सकारात्मक भविष्यवाणी के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि अनुकूल विनियामक उपाय, कर कटौती के कारण उपभोग में वृद्धि, और ब्याज दरों में नरमी।
- भारत की फार्मास्युटिकल उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जहां दवा और फार्मा निर्यात पहली बार $30 अरब के पार पहुंच गया है। मार्च 2025 में 31% की वार्षिक वृद्धि ने इस लक्ष्य को पार करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे $29.38 अरब के वार्षिक लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया गया। यह उल्लेखनीय वृद्धि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और संभावित अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों के बीच भी संभव हो पाई, जो सौभाग्यवश फार्मा निर्यात को प्रभावित नहीं कर सकीं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहा, जबकि यूके, ब्राज़ील और फ्रांस जैसे अन्य प्रमुख बाजारों ने भी सीमित लेकिन स्थिर योगदान दिया।
- मार्च 2025 में भारत के कोर सेक्टर (मूलभूत क्षेत्र) के उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका प्रमुख कारण बढ़ते तापमान और समय से पहले शुरू हुई गर्मी की लहरों के कारण बिजली उत्पादन में इज़ाफा रहा। यह प्रदर्शन फरवरी 2025 की 3.4% वृद्धि की तुलना में थोड़ा बेहतर है, लेकिन मार्च 2024 में दर्ज की गई 6.3% की वृद्धि से कम है। देश की आठ प्रमुख आधारभूत उद्योगें — कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली — औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 40.27% का योगदान करती हैं।
- घरेलू इस्पात उद्योग को संरक्षण देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने चुनिंदा श्रेणियों की इस्पात आयात पर 12% की अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय 21 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है और इसका उद्देश्य विशेष रूप से चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों से हो रहे कम लागत वाले इस्पात आयात में आई तेज़ बढ़ोतरी को रोकना है। इस कदम को उद्योग जगत की उन बढ़ती चिंताओं के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिनमें अनुचित प्रतिस्पर्धा और बाज़ार के असंतुलन की बात उठाई जा रही थी। सरकार का यह फैसला घरेलू निर्माताओं को राहत देने और इस्पात क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है।

अर्थव्यवस्था समाचार

- भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि फरवरी 2025 में घटकर 2.9% रह गई, जो पिछले पांच महीनों में सबसे धीमी दर है। यह गिरावट फरवरी 2024 में दर्ज 7.1% की वृद्धि की तुलना में काफी कम है। आठ प्रमुख उद्योगों में से केवल तीन उद्योगों में मासिक उत्पादन में वृद्धि हुई, जबकि सिर्फ सीमेंट और उर्वरक ऐसे क्षेत्र थे, जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उत्पादन दर्ज किया। कोर सेक्टर में यह मंदी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है, जिसने जनवरी 2025 में 5% की वृद्धि दर्ज की थी।
- भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद लचीलेपन के साथ वृद्धि दर्ज कर रही है। एशियाई विकास आउटलुक (ADO) अप्रैल 2025 के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण घरेलू मांग में वृद्धि, ग्रामीण आय में सुधार, और मुद्रास्फीति में नरमी है। एशियाई विकास बैंक (ADB) का मानना है कि यह वृद्धि की गति वित्त वर्ष 2026 में भी बनी रहेगी, और GDP वृद्धि दर 6.8% रहने की संभावना है। इसका समर्थन अनुकूल राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों से होगा। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों और नीतिगत अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए अपना अनुमान थोड़ा घटाकर 6.5% कर दिया है।

व्यापार समाचार

- टैरिफ एक ऐसा कर है जो सरकार दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाती है। जब ये उत्पाद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं, तो उन्हें आयात करने वाले व्यवसाय को आयात करने वाले देश की सरकार को यह कर चुकाना पड़ता है।
- 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना ने हाशिए पर पड़े उद्यमियों को सशक्त बनाने के सात साल पूरे कर लिए हैं , जिसके तहत 61,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं । आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित इस पहल को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- बेंगलुरु स्थित पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी Juspay ने 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया है। कंपनी ने सीरीज़ D फंडिंग राउंड में $60 मिलियन (लगभग ₹500 करोड़) जुटाए हैं। इस निवेश दौर का नेतृत्व Kedaara Capital ने किया, जिसमें मौजूदा निवेशकों SoftBank और Accel ने भी भाग लिया।
- दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर कंपनी ब्लैकरॉक (BlackRock) ने भारत के अडानी ग्रुप (Adani Group) द्वारा जारी किए गए 750 मिलियन डॉलर के प्राइवेट बॉन्ड को सब्सक्राइब किया है। इस डील में कई प्रमुख अमेरिकी और यूरोपीय निवेशकों ने भी भाग लिया है, जो अडानी समूह में निवेशकों के विश्वास की सतर्क लेकिन उल्लेखनीय वापसी को दर्शाता है। यह पूंजी अडानी की सहायक कंपनी रिन्यू एक्सिम (Renew Exim) को प्रदान की जाएगी, जो आईटीडी सिमेंटेशन (ITD Cementation) के अधिग्रहण में उपयोग की जाएगी।
- फिनटेक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Razorpay ने अपने Turbo UPI प्लगइन का अनावरण किया है, जिसे NPCI BHIM Services Limited (NBSL) और Axis Bank के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। इस समाधान में BHIM Vega प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है, जिससे लेन-देन के दौरान बाहरी रीडायरेक्शन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उपयोगकर्ता सीधे ऐप के भीतर ही भुगतान पूरा कर सकते हैं। यह उन्नत UPI समाधान भुगतान विफलताओं को कम करने, लेन-देन की गति बढ़ाने, विश्वसनीयता में सुधार करने तथा एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जो भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित कर रहा है।

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक महत्वपूर्ण नियामकीय कार्रवाई के तहत Gensol Engineering Ltd (GEL) और इसके प्रवर्तकों, अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को प्रतिभूति बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई कंपनी में गंभीर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चूक और फंड डायवर्जन (धन के ग़लत इस्तेमाल) के कारण की गई है। SEBI को जून 2024 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शेयर की कीमतों में हेरफेर और कंपनी के धन का दुरुपयोग उजागर किया गया था। यह मामला नियामक संस्थाओं द्वारा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के एक अहम उदाहरण के रूप में सामने आया है।
- एक रणनीतिक ब्रांडिंग पहल के तहत, मिल्कफेड पंजाब, जो भारत की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय दुग्ध सहकारी संस्थाओं में से एक है, ने अपनी प्रमुख डेयरी ब्रांड वेरका (Verka) के लिए एक नया मास्कट 'वीरा' लॉन्च किया है। यह पहल वेरका की पहचान को देश और विदेशों में और अधिक मजबूत करने तथा बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, जैसा कि वर्षों से अमूल गर्ल के माध्यम से अमूल ने किया है। वीरा, एक मुस्कुराता हुआ, हाथ जोड़े खड़ा नन्हा सिख बालक, पंजाब की गर्मजोशी, परंपरा और मेहमाननवाज़ी का प्रतीक है। यह शुभारंभ अमृतसर में ₹135 करोड़ की डेयरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखने के साथ हुआ, जो वेरका के संचालन के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- Zepto, जो भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्विक-कॉमर्स स्टार्टअप्स में से एक है, ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने हाल ही में अपनी मूल कंपनी का नाम आधिकारिक रूप से बदल लिया है। अब इसे किरणाकार्ट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के बजाय Zepto प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। यह बदलाव कंपनी की उपभोक्ता ब्रांड पहचान के अनुरूप किया गया है। यह नाम परिवर्तन हाल ही में मुंबई स्थित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (RoC) द्वारा स्वीकृत किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी अब अपने ब्रांड की पहचान और हितधारकों की रणनीति को IPO से पहले और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर है।
- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) भारत के खनन क्षेत्र में इतिहास रच रहा है, क्योंकि यह देश का पहला कोयला सार्वजनिक उपक्रम (PSU) बन गया है जो भूमिगत कोयला खनन के लिए पेस्ट फिल तकनीक को लागू कर रहा है। यह अत्याधुनिक पहल भारत के कोयला उद्योग में सतत और पर्यावरण-सम्मत खनन प्रथाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। इस नवाचारी तकनीक को अपनाने से सतही बाधाओं वाले क्षेत्रों में भी कोयले का सुरक्षित और कुशल दोहन संभव होगा, साथ ही इससे पर्यावरणीय प्रभाव को भी न्यूनतम किया जा सकेगा।
- भारत ने अपने आंतरिक जल परिवहन (IWT) क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान देश ने 145.5 मिलियन टन (MMT) कार्गो परिवहन दर्ज किया, जो वित्तीय वर्ष 2013–14 में मात्र 18.1 MMT था। इस उल्लेखनीय वृद्धि के पीछे व्यापक बुनियादी ढांचा विकास, नीति सुधारों और तकनीकी नवाचारों का योगदान है। भारत ने अपने राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर 111 कर दी है और परिचालन लंबाई लगभग 4,900 किलोमीटर तक बढ़ा दी है, जो बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स और सतत विकास के प्रति देश की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समझौता ज्ञापन एवं समझौते

देश के साथ समझौता ज्ञापन

देश	समझौता किसके साथ	क्षेत्र / उद्देश्य
भारत	रूस	• भारत-रूस प्राथमिक निवेश परियोजनाओं पर कार्य समूह (IRWG-PIP) के 8वें सत्र में दोनों देशों ने 6 नई रणनीतिक परियोजनाओं पर सहमति जताई। यह बैठक नई दिल्ली में अमरदीप सिंह भाटिया (भारत) और व्लादिमीर इलिचेव (रूस) की सह-अध्यक्षता में हुई। सत्र का मुख्य फोकस व्यापार, प्रौद्योगिकीय सहयोग और आर्थिक विकास पर था। साथ ही, भारत-रूस निवेश मंच के दूसरे संस्करण में 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिससे संयुक्त परियोजनाओं में बढ़ती रुचि सामने आई।

राज्य के साथ समझौता ज्ञापन

राज्य	समझौता किसके साथ	क्षेत्र / उद्देश्य
केरल	आईआईटी बॉम्बे	• केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) और आईआईटी बॉम्बे मिलकर व्हीकल-टू-ग्रिड (V2G) तकनीक को लागू करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू कर रहे हैं। यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बैटरियों को न केवल चार्ज करने बल्कि जरूरत पड़ने पर ग्रिड में बिजली वापस भेजने की सुविधा देती है। इस पहल का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, ग्रिड की स्थिरता बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। परियोजना के तहत ईवी मालिकों को प्रीमियम टैरिफ जैसे वित्तीय प्रोत्साहन भी मिलेंगे, विशेष रूप से जब वे पीक आवर्स के दौरान ऊर्जा ग्रिड को उपलब्ध कराते हैं।

संगठन के बीच समझौता ज्ञापन

संगठन	समझौता किसके साथ	क्षेत्र / उद्देश्य
इंडिया पोस्ट	निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड	• म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए डोर-टू-डोर KYC सत्यापन सेवा प्रदान करने के लिए समझौता किया गया है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, वृद्ध नागरिकों, और चलने-फिरने में असमर्थ लोगों के लिए म्यूचुअल फंड निवेश को और अधिक सुलभ बनाना है। इंडिया पोस्ट का देशव्यापी नेटवर्क पहले ही UTI और SUUTI के लिए 5 लाख से अधिक KYC सत्यापन कर चुका है। यह भागीदारी जन निवेश पहल को भी समर्थन देती है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	स्विगी	• नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल के माध्यम से गिग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया गया। इसका उद्देश्य अगले 2–3 वर्षों में 12 लाख नौकरी के अवसर पैदा करना है। इसमें रीयल-टाइम जॉब पोस्टिंग, समावेशी नियुक्ति (युवाओं, महिलाओं और फ्लेक्सिबल वर्क चाहने वालों के लिए) को बढ़ावा देना शामिल है। स्विगी गिग जॉब्स, डिलीवरी रोल्स, और सपोर्ट रोल्स पोस्ट करेगा, जो डिजिटल सशक्तिकरण और कर्मचारी कल्याण योजनाओं को भी सहयोग देगा।

नियुक्तियाँ और इस्तीफे

नियुक्तियाँ राष्ट्रीय

व्यक्ति का नाम	पद	संस्था / स्थान	मुख्य बिंदु
डॉ. जय भट्टाचार्य	राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (NIH) के निदेशक	अमेरिका	• अमेरिकी सीनेट ने 25 मार्च 2025 को पुष्टि की; ट्रम्प द्वारा नामांकन। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर, MD और अर्थशास्त्र में PhD। सार्वजनिक स्वास्थ्य और नीति में विशेषज्ञ।
निधि तिवारी	प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव	भारत सरकार	• आईएफएस अधिकारी, पहले पीएमओ में उप सचिव, विदेश मंत्रालय में भी सेवाएं दीं।
अंबुज चंदना	प्रबंध निदेशक और हेड, कंज़्यूमर बैंकिंग	डीबीएस बैंक इंडिया	• कोटक महिंद्रा बैंक में 16+ वर्षों का अनुभव; खुदरा बैंकिंग और ऋण क्षेत्र में विशेषज्ञता।
सलीला पांडे	एमडी और सीईओ	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज	• एसबीआई में 30 वर्षों का अनुभव; क्रेडिट सेवाओं और खुदरा बैंकिंग की विशेषज्ञ।
एन. चंद्रशेखरन	आईएमएफ सलाहकार परिषद सदस्य	टाटा संस	• उद्यमिता और विकास से संबंधित IMF सलाहकार परिषद में नियुक्त; वैश्विक व्यापार रणनीति में प्रमुख भूमिका।
स्वामीनाथन एस. अय्यर	पूर्णकालिक सदस्य (जीवन बीमा)	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)	• 5 साल के लिए नियुक्त; बीमा क्षेत्र की नीति और निगरानी में विशेषज्ञता।
पूनम गुप्ता	डिप्टी गवर्नर	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• IMF, विश्व बैंक, NCAER में अनुभव; मौद्रिक नीति निर्माण में भूमिका।
एच. शंकर	प्रबंध निदेशक	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL)	• जुलाई 2024 से अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे; परिष्करण परियोजनाओं में नेतृत्व किया।
सिवासुब्रमण्यम रामण	अध्यक्ष	पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)	• 5 वर्षों की नियुक्ति; राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना की निगरानी।
कमल हासन	अध्यक्ष	FICCI मीडिया और मनोरंजन समिति (दक्षिण)	• भारत के मीडिया क्षेत्र को $100 बिलियन उद्योग में बदलने की दृष्टि।
सोहिनी राजोला	कार्यकारी निदेशक	NPCI	• भुगतान समाधान को बढ़ावा देने हेतु NPCI में नियुक्त।
मोहसिन नक़वी	अध्यक्ष	एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC)	• पीसीबी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री; क्रिकेट कूटनीति में योगदान।

व्यक्ति का नाम	पद	संस्था / स्थान	मुख्य बिंदु
सीमा अग्रवाल	महानिदेशक, अग्निशमन एवं बचाव सेवाएं	भारत सरकार	• पूर्व में नागरिक आपूर्ति की डीजी रही हैं; आठ अन्य आईपीएस अधिकारियों का तबादला भी हुआ।
बालाजी नुथलापाडी	कार्यकारी निदेशक – प्रौद्योगिकी एवं संचालन	इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक	• सिटी बैंक में वरिष्ठ पदों पर कार्यानुभव; आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त।
न्यायमूर्ति अरुण पाली	मुख्य न्यायाधीश	जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय	• सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर नियुक्ति; पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से स्थानांतरण।
सतीश चव्वा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)	ओमान इंडिया संयुक्त निवेश कोष (OIJIF)	• 20 वर्षों से अधिक का निजी इक्विटी और वित्तीय अनुभव।
विरल दावड़ा	उप मुख्य सूचना अधिकारी	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)	• IT अवसंरचना को सशक्त बनाने हेतु नियुक्त; पूर्व CTO, NCDEX।
डॉ. मोहन राजन	अध्यक्ष और चिकित्सा निदेशक	राजन आई केयर हॉस्पिटल	• AIOS के उपाध्यक्ष नियुक्त; तमिलनाडु के पांचवें विशेषज्ञ ophthalmologist इस पद पर।
मीराबाई चानू	अध्यक्ष	IWLF एथलीट्स कमीशन	• अनुभवी खिलाड़ी नेतृत्व को बढ़ावा देने हेतु नियुक्त।
संतोष कुमार	उप मुख्य वित्तीय अधिकारी (Deputy CFO)	इंडसइंड बैंक	• माइक्रोफाइनेंस में बढ़ते NPA के मद्देनज़र नियुक्ति।
टी. रबी शंकर	उप गवर्नर	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• एक वर्ष का पुनर्नियुक्ति कार्यकाल; आर्थिक स्थिरता और मौद्रिक नीति में भूमिका।
जज कावेरी बवेजा	रजिस्ट्रार (विजिलेंस)	दिल्ली उच्च न्यायालय	• प्रशासनिक फेरबदल के तहत नियुक्ति।
अजय भूषण प्रसाद पांडे	उपाध्यक्ष	एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक	• निवेश समाधान, सततता, और पोर्टफोलियो प्रबंधन विभाग की निगरानी।
जितेंद्र मिश्रा	अध्यक्ष	CIFEJ (बाल और युवा फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय केंद्र)	• SIFFCY के निदेशक; 2025–2027 कार्यकाल के लिए निर्वाचित।
डॉ. मांगीलाल जाट	सचिव और महानिदेशक	DARE और ICAR	• 25 वर्षों का कृषि और जलवायु अनुकूल खेती में अनुभव।
स्टेसी सायर	उपाध्यक्ष और एमडी	बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी केंद्र	• 28 वर्षों का अनुभव; विमान कार्यक्रमों में नेतृत्व किया।
अनंत अंबानी	कार्यकारी निदेशक	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	• 1 मई 2025 से 5 वर्षों का कार्यकाल; हरित ऊर्जा परियोजनाओं में नेतृत्व।
डॉ. नीलम ढुंगाना तिम्सिना	कार्यवाहक गवर्नर	नेपाल राष्ट्र बैंक	• 6 अप्रैल 2025 से कार्यभार ग्रहण; नेपाल के वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्ति।

ब्रांड और अभियान राजदूत

व्यक्ति का नाम	ब्रांड / अभियान	प्रमुख बिंदु
अनन्या पांडे	शनेल (Chanel)	• बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे को शनेल का पहली बार भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो उनके और भारतीय फैशन उद्योग दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह उपलब्धि पेरिस में हुए शनेल स्प्रिंग/समर 2025 शो में उनकी उपस्थिति के बाद आई है।
कृति सेनन	ड्रीम टेक्नोलॉजी (Dreame Technology)	• ड्रीम टेक्नोलॉजी, एक प्रमुख चीनी स्मार्ट होम उपकरण ब्रांड, ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 2017 में स्थापित यह ब्रांड रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, कॉर्डलेस वैक्यूम और हेयर स्टाइलिंग टूल्स जैसे एआई-आधारित स्मार्ट उत्पादों के लिए जाना जाता है।

पुरस्कार

अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार

पुरस्कार का नाम	पुरस्कार विजेता	क्षेत्र	प्रमुख बिंदु
प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार	पुरातत्वविद माईना स्वामी	इतिहास और समाज सेवा	• आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद माईना स्वामी को ऐतिहासिक शोध और सामाजिक सेवा में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा तुम्मलापल्ली कलाक्षेत्रम, विजयवाड़ा में प्रदान किया गया। इसमें 'कलारत्न' उपाधि, 'हंसा' पदक, प्रशंसा प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार शामिल हैं।
गोल्ड मरकरी पुरस्कार (शांति और स्थायित्व के लिए)	दलाई लामा	शांति और पर्यावरण	• गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल द्वारा 1 अप्रैल 2025 को दलाई लामा को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान उनके अहिंसा, मानव गरिमा, धार्मिक संवाद और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जीवनभर के समर्पण को मान्यता देता है।
उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार	निखिल सिंघल	जनसंपर्क और रणनीतिक संचार	• विगर मीडिया वर्ल्डवाइड के संस्थापक और नोएडा हाईराइज फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल सिंघल को यह पुरस्कार 31 मार्च 2025 को लखनऊ के ताज होटल में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह में दिया गया। उन्होंने अपनी टीम को समर्पण और उत्कृष्टता के लिए धन्यवाद दिया।
राष्ट्रीय युवा पुरस्कार	अकार्श श्रॉफ	सामाजिक सेवा और शिक्षा	• युवास्पार्क के संस्थापक अकार्श श्रॉफ को आंगनवाड़ी डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा नवाचार में उनके प्रभावशाली कार्य के लिए 3 अप्रैल 2025 को यह पुरस्कार संसद भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को राष्ट्रीय विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। इस वर्ष 22 युवाओं को सम्मानित किया गया।
फ्रेड डैरिंगटन पुरस्कार (कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए)	सुदर्शन पटनायक	रेत शिल्प और कला	• सुदर्शन पटनायक ने अपनी भगवान गणेश की रेत कला के लिए यह पहला फ्रेड डैरिंगटन पुरस्कार जीता, जो "विश्व शांति" का संदेश देती है। 10 फीट ऊंची यह मूर्ति नवंबर 2025 तक वेमाउथ, डॉर्सेट के सैंडवर्ल्ड में प्रदर्शित की जा रही है। पुरस्कार में डैरिंगटन की कार्टून छवि वाला स्वर्ण पदक और पटनायक की मूर्ति की रेत से बना कांच का तरंग शामिल है।
'मास्टर ह्यूमर अवॉर्ड'	आमिर खान	हास्य और सिनेमा	• चीन के मकाऊ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कॉमेडी महोत्सव 2025 में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को यह पुरस्कार 9-13 अप्रैल को प्रदान किया गया। चीन में उन्हें 'अंकल मी' के नाम से जाना जाता है। '3 इडियट्स', 'पीके', और 'दंगल' जैसी फिल्मों से उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक रही है, विशेष रूप से 'दंगल' ने ₹1000 करोड़ से अधिक की कमाई की।
वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार	पी. शिवकामी	साहित्य और सामाजिक चेतना	• प्रसिद्ध लेखिका, पूर्व IAS अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता पी. शिवकामी को चेन्नई में नीलम सांस्कृतिक केंद्र द्वारा ₹1 लाख के पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने भाषण में दलित पहचान, प्रतिरोध की शक्ति, अंग्रेजी में लेखन के महत्व और साहित्य में दलित आवाजों की वृद्धि को रेखांकित किया।
'लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी' पुरस्कार	डॉ. डी. नागेश्वर रेड्डी	चिकित्सा (गैस्ट्रोएंटरोलॉजी)	• हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल्स के अध्यक्ष डॉ. डी. नागेश्वर रेड्डी को जापानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी समुदाय द्वारा टोक्यो में SHOWA मेडिकल यूनिवर्सिटी में आयोजित 'टोक्यो लाइव ग्लोबल एंडोस्कोपी 2025' कार्यक्रम में यह सम्मान मिला।

पुरस्कार का नाम	पुरस्कार विजेता	क्षेत्र	प्रमुख बिंदु
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य (आधार बायोमेट्रिक अपडेट और सत्यापन)	मेघालय	शासन और पहचान प्रबंधन	• भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार सत्यापन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेघालय को दो श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया। पुरस्कार नई दिल्ली में प्रस्तुत किए गए।
मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल	D. पांडा, राहुल कुमार पांडे (2023), राम रतन जाट, झूमर राम पूनिया, रणवीर सिंह जमवाल (2024)	सैन्य सेवा और साहसिक कार्य	• यूनाइटेड सर्विस इंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) द्वारा आयोजित समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यह मेडल उन सैन्य कर्मियों को प्रदान किया जिन्होंने सैन्य खोजबीन, अन्वेषण और साहसिक अभियानों में उत्कृष्ट योगदान दिया।
गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025	अच्युत सामंत	शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण	• KIIT और KISS के संस्थापक अच्युत सामंत को यह पुरस्कार कोकराझार, असम में उनके शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न और ₹1 लाख की राशि शामिल है, जिसे उन्होंने ट्रस्ट को वापस दान कर दिया।
ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर	प्रियंका चोपड़ा	सिनेमा (बॉलीवुड-हॉलीवुड सेतु)	• 10 मई 2025 को लॉस एंजेलिस के म्यूजिक सेंटर में आयोजित गोल्ड हाउस गोल्ड गाला में प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच 25 वर्षों के प्रभावशाली करियर के लिए पहला 'ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर' दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (सार्वजनिक प्रशासन) 2024	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	नवाचार और पोषण प्रबंधन	• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन को 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के तहत टेक-आधारित पोषण प्रशासन में नवाचार के लिए यह पुरस्कार 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय सचिव श्री अनिल मलिक द्वारा प्राप्त किया गया।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024	कुमार मंगलम बिड़ला	उद्योग और नेतृत्व	• आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष और पद्म भूषण सम्मानित कुमार मंगलम बिड़ला को भारत की आर्थिक प्रगति में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार 24 अप्रैल को मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिया गया।
'ऑर्ड्रे देज़ आर्ट ए लेत्र' (फ्रेंच कला और साहित्य सम्मान)	पायल कपाड़िया	सिनेमा	• मुंबई स्थित फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को फ्रांस की सरकार द्वारा 'ऑफिसियर डान लोर्ड्रे देज़ आर्ट ए लेत्र' से सम्मानित किया गया। उनका फिल्म 'All We Imagine As Light' ने 77वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीता और गोल्डन ग्लोब में नामांकित हुई।
राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार	राजेश उन्नी	समुद्री क्षेत्र	• सीनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को भारत के सर्वोच्च समुद्री सम्मान 'राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार' से 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस (मुंबई) पर सम्मानित किया गया।

शिखर सम्मेलन, कार्यक्रम और सम्मेलन

श्रेणी	कार्यक्रम	स्थल	मुख्य बिंदु
सम्मेलन	9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट (GTS) 2025	नई दिल्ली	• विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में होगा। थीम है – "संभावना"। यह उभरती तकनीकों के माध्यम से समावेशी विकास, डिजिटल शासन और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों की खोज करेगा। इसमें 40+ देशों से 150+ वक्ता शामिल होंगे।
सम्मेलन	IDF वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस	बैंकॉक	• WHO और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) द्वारा आयोजित यह हाइब्रिड साइड इवेंट "पुल बनाना: टीबी और मधुमेह को संबोधित करने की एकीकृत रणनीतियाँ" विषय पर आधारित था। इसमें 2023 में 1.25 मिलियन मौतों वाले 10.8 मिलियन टीबी मामलों और 2024 में 828 मिलियन वयस्कों में मधुमेह की स्थिति पर चर्चा हुई। टीबी और डायबिटीज की 15% सह-बीमारी दर उजागर की गई। WHO ने प्रारंभिक निदान, द्विदिश स्क्रीनिंग और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ीकरण हेतु नई गाइडलाइन लॉन्च की।

श्रेणी	कार्यक्रम	स्थल	मुख्य बिंदु
कार्यक्रम	11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक	ब्रासीलिया, ब्राज़ील	• 3 अप्रैल 2025 को आयोजित इस बैठक में भारत ने "बाकू से बेलेम रोडमैप" के अंतर्गत USD 1.3 ट्रिलियन जुटाने पर बल दिया। MoEFCC के अमनदीप गर्ग ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा, तथा न्यायपूर्ण संक्रमण (Just Transition) पर ज़ोर दिया। बैठक में जलवायु वित्त, ऊर्जा विविधीकरण, ग्रीन ग्रिड पहल, संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था की बात की गई।
कार्यक्रम	ISAR - संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी विशेषज्ञ कार्य समूह	—	• भारत को 2025–2027 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों पर संयुक्त राष्ट्र के ISAR कार्य समूह का सदस्य नियुक्त किया गया। यह भारत की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कॉर्पोरेट प्रशासन में वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। भारत वित्तीय व गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग, CSR, पर्यावरण और शासन जैसे क्षेत्रों में योगदान देगा।
कार्यक्रम	वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद (Global Climate Action Council)	प्रस्तावित (COP30 से पहले)	• ब्राज़ील ने COP30 (नवंबर 2025, बेलेम) से पहले UNFCCC के अंतर्गत एक "वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद" के गठन का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य जलवायु वार्ताओं को सरल बनाना और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। यह प्रस्ताव मिश्रित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के बावजूद ब्राज़ील की अग्रणी भूमिका को दर्शाता है।
कार्यक्रम	बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति	नामसाई, अरुणाचल प्रदेश	• संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) द्वारा 21–22 अप्रैल 2025 को आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में बुद्ध धर्म के पूर्वोत्तर भारत की कला, संस्कृति और इतिहास पर प्रभाव की चर्चा होगी। इसमें विशेष रूप से ताई खामती जनजाति द्वारा प्रचलित थेरवाद बौद्ध धर्म पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
सम्मेलन	राष्ट्रीय सम्मेलन 'पर्यावरण – 2025'	नई दिल्ली	• 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। पर्यावरण संरक्षण को दैनिक जिम्मेदारी बताया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा आयोजित सम्मेलन में पर्यावरणीय चुनौतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और नीति सहयोग पर चर्चा हुई।
सम्मेलन	सेना कमांडरों का सम्मेलन (ACC) 2025	नई दिल्ली	• 1–4 अप्रैल 2025 को आयोजित। राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य तैयारियों, तकनीकी समावेशन और सैनिक कल्याण पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS और नीति आयोग प्रमुख ने रक्षा रणनीति पर दृष्टिकोण साझा किया।
सम्मेलन	बड़े NBFCs के लिए सम्मेलन	चेन्नई	• 28 मार्च 2025 को RBI द्वारा आयोजित। विषय: "साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी: NBFCs को सुदृढ़ बनाना"। 200+ प्रतिभागी शामिल हुए। नियामकीय पर्यवेक्षण, जोखिम प्रबंधन, पारदर्शिता और निष्पक्ष उधारी पर चर्चा हुई।
सम्मेलन	6वां बिम्सटेक शिखर सम्मेलन	थाईलैंड	• 3 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। उद्देश्य: व्यापार, संपर्क और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय रणनीति और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर। बैठक के बाद श्रीलंका दौरा।
सम्मेलन	जिटेक्स अफ्रीका 2025	माराकेच, मोरक्को	• डिजिटल अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास पर वैश्विक संवाद का मंच। भारत के राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने आधार, UPI, ONDC और स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया।

इंडेक्स

रैंकिंग

- भारत ने वर्ष 2023 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में निजी निवेश के रूप में ₹11,943 करोड़ (अमेरिकी डॉलर 1.4 बिलियन) के साथ वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया है, जो वैश्विक AI परिदृश्य में उसकी उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी 'फ्रंटियर तकनीकों के लिए तत्परता सूचकांक' में भारत ने 2022 में 48वें स्थान से सुधार करते हुए 2024 में 36वां स्थान प्राप्त किया। हालांकि, भारत को पवन ऊर्जा में जर्मनी, इलेक्ट्रिक वाहनों में जापान और 5जी तकनीक में दक्षिण कोरिया जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत के पास 1.3 करोड़ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मजबूत कार्यबल है और वह AI अनुसंधान और नैनो तकनीक में अग्रणी देशों में शामिल है। लेकिन इस नेतृत्व को बनाए रखने के लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निरंतर निवेश और कार्यबल कौशल विकास आवश्यक है। अनुमान है कि AI का आर्थिक प्रभाव वर्ष 2033 तक ₹4,09,48,800 करोड़ (अमेरिकी डॉलर 4.8 ट्रिलियन) तक पहुंच सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 7 अप्रैल 2025 को CERT-In, CSIRT-Fin और SISA के सहयोग से BFSI (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा) क्षेत्र के लिए "डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024" जारी की। इस रिपोर्ट का शुभारंभ DFS, MeitY और SISA के

शीर्ष अधिकारियों द्वारा किया गया। यह रिपोर्ट साइबर खतरों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है और साइबर सुरक्षा के लिए एक मजबूत रणनीति का खाका प्रदान करती है। रिपोर्ट में AI-आधारित साइबर हमलों, बढ़ते डिजिटल हमले के क्षेत्रों और अनुपालन से जुड़ी चुनौतियों को प्रमुख जोखिम के रूप में उजागर किया गया है। इसमें "लोग, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी" के स्तर पर समन्वित साइबर सुरक्षा रणनीति की सिफारिश की गई है, जिसका उद्देश्य संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाना, सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना और साझा खुफिया जानकारी के माध्यम से एक सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।

- Ookla के स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स (फरवरी 2025) के अनुसार, मुंबई ने भारतीय शहरों में सबसे धीमी फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड दर्ज की, जो वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर रही, जहां डाउनलोड स्पीड 58.24 Mbps रही। वहीं, दिल्ली ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो 89वें स्थान पर रही और डाउनलोड स्पीड 91.11 Mbps रही। इस असमानता के कारण भारत की वैश्विक ब्रॉडबैंड रैंकिंग 94 से गिरकर 95 हो गई। देश की औसत डाउनलोड स्पीड 61.66 Mbps, अपलोड स्पीड 57.89 Mbps और लेटेंसी 7 ms रही। मुंबई के खराब प्रदर्शन के पीछे घनी आबादी और भौगोलिक चुनौतियां प्रमुख कारण मानी गईं।
- दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डा एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) वर्ल्ड द्वारा 2024 में विश्व का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया, जहां 7.7 करोड़ यात्रियों की आवाजाही हुई। यह 2019 में 17वें स्थान से 2023 में 10वें और अब 2024 में 9वें स्थान तक पहुंचकर भारत की बढ़ती विमानन क्षमता, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और वैश्विक कनेक्टिविटी को दर्शाता है। GMR समूह के तहत दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) द्वारा संचालित IGI, शीर्ष 10 वैश्विक हवाई अड्डों में शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। इस सूची में शीर्ष पर अटलांटा और दुबई जैसे हवाई अड्डे हैं, जबकि 2024 में कुल 9.5 अरब यात्रियों ने हवाई यात्रा की।
- नीति आयोग की रिपोर्ट 'Unlocking $25+ Billion Export Potential - India's Hand & Power Tools Sector' में भारत के हाथ और पावर टूल्स उद्योग के वैश्विक बाजार में अवसरों का विश्लेषण किया गया है, जिसका वर्तमान मूल्य $100 अरब है और जो 2035 तक $190 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास इस क्षेत्र में $25 अरब के निर्यात और अगले दशक में 35 लाख नौकरियों के सृजन की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि, उच्च कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स लागत के कारण भारत को लागत संबंधी प्रतिस्पर्धा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- 2025 की TIME 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस जैसे वैश्विक हस्तियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने राजनीति, नवाचार और सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। गौरतलब है कि इस वर्ष सूची में कोई भी भारतीय व्यक्तित्व शामिल नहीं है, जबकि 2024 में आलिया भट्ट और साक्षी मलिक को इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला था।

रिपोर्ट

रिपोर्ट का नाम	प्रस्तुतकर्ता	मुख्य बिंदु
यूनेस्को रिपोर्ट	यूनेस्को	'न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ' कार्यक्रम (27-28 मार्च 2025, फ्रांस) में स्कूल भोजन की गुणवत्ता पर चिंता जताई गई। ► 2024 में 47% प्राथमिक छात्र भोजन प्राप्त कर रहे थे। ► 27% भोजन में पोषण विशेषज्ञ की भूमिका नहीं थी। ► 187 में से केवल 93 देशों में स्कूल फूड कानून हैं। ► 65% देशों ने खाद्य मानक तय किए हैं।
2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट	यूएनसीटीएडी	भारत ने फ्रंटियर तकनीकों को अपनाने में प्रगति की है, 2022 में 48वें स्थान से बढ़कर 2025 में 36वें स्थान पर पहुंचा। ► आईसीटी, अनुसंधान, औद्योगिक क्षमता और वित्त में सुधार। ► एआई और नैनो टेक्नोलॉजी में अग्रणी। ► विकासशील देशों के बीच भारत उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

रक्षा

अभ्यास

अभ्यास का नाम	स्थान / भागीदार देश	मुख्य बिंदु
INIOCHOS-25	ग्रीस / 15 देश	भारतीय वायुसेना ने 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक एंड्रावीडा एयर बेस, ग्रीस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास INIOCHOS-25 में हिस्सा लिया। ► IAF ने Su-30 MKI, IL-78, और C-17 विमान तैनात किए। ► युद्ध कौशल, संयुक्त वायु अभियानों और सामरिक विशेषज्ञता को बढ़ाने पर जोर।

अभ्यास का नाम	स्थान / भागीदार देश	मुख्य बिंदु
टाइगर ट्रायम्फ 2025	भारत (पूर्वी तट), अमेरिका	भारत-अमेरिका त्रि-सेवा HADR अभ्यास का चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 तक। ► SOPs और संयुक्त समन्वय केंद्र (CCC) विकसित करना। ► विशाखापत्तनम में हार्बर चरण (1-7 अप्रैल) और काकीनाडा में समुद्री चरण (8-13 अप्रैल)।
इंद्रा 2025	भारत / रूस	भारतीय और रूसी नौसेनाओं के बीच 14वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक। ► समुद्री सुरक्षा खतरों का मुकाबला, संयुक्त संचालन की तैयारी और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का आदान-प्रदान।
दस्तलिक-VI (DUSTLIK-VI)	पुणे, भारत / उज्बेकिस्तान	भारत-उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण 16 से 28 अप्रैल 2025 तक। ► सामरिक समन्वय और सैन्य सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित।
आक्रामण (Aakraman)	भारत	भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित प्रमुख सैन्य अभ्यास, जिसमें राफेल और Su-30MKI लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। ► पर्वतीय और स्थलीय लक्ष्यों पर हमलों का अभ्यास, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और लाइव फायरिंग शामिल। ► स-400, मेटियोर और रैम्पेज मिसाइलों का उपयोग।

सौदा और समझौता ज्ञापन

- वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपये (2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.04% की वृद्धि दर्शाता है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) और निजी उद्योग द्वारा संचालित यह उछाल रक्षा विनिर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। डीपीएसयू ने 42.85% की वृद्धि दर्ज की, जिसका योगदान 8,389 करोड़ रुपये रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 15,233 करोड़ रुपये रहा।
- भारत और फ्रांस 28 अप्रैल, 2025 को 26 राफेल-मरीन (राफेल-एम) जेट विमानों के लिए ₹63,000 करोड़ के जी-टू-जी सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तैयार हैं - 22 सिंगल-सीटर और 4 ट्विन-सीटर ट्रेनर - भारत के नौसैनिक विमानन को बढ़ाने के लिए। इन जेट विमानों को INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा, जो स्वदेशी ट्विन इंजन डेक-बेस्ड फाइटर (TEDBF) तैयार होने तक क्षमता अंतर को पाटेंगे। डिलीवरी 3.5 साल में शुरू होगी, 6.5 साल में पूरी डिलीवरी होगी, जिससे भारत-फ्रांस के रणनीतिक रक्षा संबंध मजबूत होंगे।

सेना, नौसेना और वायु सेना समाचार

- भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारियों द्वारा संचालित नाविका सागर परिक्रमा-II (NSP-II) अभियान ने अपने वैश्विक परिक्रमा यात्रा के चौथे चरण को पूरा करते हुए केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश किया। INSV तारिणी को भारतीय वाणिज्य दूत रूबी जसप्रीत, दक्षिण अफ्रीकी नौसेना की रियर एडमिरल (JG) लिसा हेंड्रिक्स, और भारतीय रक्षा सलाहकार कैप्टन अतुल सपाहिया द्वारा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीकी नौसेना बैंड ने विशेष प्रस्तुति दी।
- भारतीय सेना ने DRDO और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित MRSAM (मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल) के सफल परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मिसाइल प्रणाली ने चार उड़ान परीक्षणों के दौरान उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक रोका और नष्ट कर दिया।
- भारत ने अपनी नौसैनिक विमानन शक्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्रांस के साथ ₹63,000 करोड़ (7 अरब डॉलर से अधिक) के अंतर-सरकारी समझौते को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद की जाएगी। इस बहुप्रतीक्षित सौदे को कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति (CCS) द्वारा औपचारिक रूप से मंज़ूरी दी गई है। यह सौदा विशेष रूप से भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत से संचालन के लिए किया गया है और इससे नौसेना की वायु शक्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिलेगा।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच भारतीय वायु सेना के सुखोई-30 MKI विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम 'गौरव' (Long-Range Glide Bomb – LRGB) के सफल परीक्षण किए। इन परीक्षणों में 'गौरव' बम ने लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को अत्यंत सटीकता के साथ भेदा, जो भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और वायु से प्रक्षेपित हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्शाता है।
- भारतीय नौसेना ने 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में अपने प्रतिष्ठित मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संगोष्ठी – 'मेघायन-25' के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। यह कार्यक्रम विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देना था। संगोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने किया। इस आयोजन में प्रमुख वैज्ञानिक एवं रक्षा संस्थानों की सक्रिय भागीदारी रही।
- भारत ने हाइपरसोनिक हथियारों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अंतर्गत कार्यरत रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL) ने 25 अप्रैल 2025 को सक्रिय शीतलित स्क्रामजेट सबस्केल कम्बस्टर (Active Cooled Scramjet Subscale Combustor) का एक लंबी अवधि का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। यह परीक्षण हैदराबाद में हाल ही में स्थापित स्क्रामजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी में आयोजित किया गया और यह 1,000 सेकंड से अधिक समय तक चला।

- भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सुनयना गुरुवार, 17 अप्रैल 2025 को मोज़ाम्बिक के नाकाला बंदरगाह पर पहुँचा, जो इंडियन ओशन शिप (IOS) SAGAR मिशन के तहत उसकी चल रही तैनाती का हिस्सा है। यह पोर्ट कॉल भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में साझेदारी और स्थायित्व को बढ़ावा देने की भारत की रणनीतिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आईएनएस सुनयना की यह यात्रा हाल ही में तंज़ानिया के डार-एस-सलाम में आयोजित भारत-अफ्रीका समुद्री साझेदारी अभ्यास "AIKEYME 25" के उद्घाटन सत्र में भाग लेने के बाद हो रही है, जो क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को एक नई दिशा देने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
- भारतीय वायुसेना (IAF) ने संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा एयर बेस पर 'एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग-10' में भाग लेने के लिए अपना एक दल तैनात किया है। यह प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास 21 अप्रैल से 8 मई, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह रणनीतिक सहभागिता भारत की वैश्विक साझेदारों के साथ सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपनी संचालन क्षमताओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

विज्ञान प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय

- बहुप्रतीक्षित NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) उपग्रह मिशन, जो भारत की इसरो और अमेरिका की नासा के बीच एक अनोखी सहयोगात्मक परियोजना है, अब जून 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह उपलब्धि कई बार की देरी के बाद सामने आई है, विशेष रूप से असेंबली और परीक्षण चरणों के दौरान। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को आगामी अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी दी, जिसमें NISAR और मई महीने में प्रस्तावित अन्य प्रमुख मिशन शामिल हैं।
- सी-डॉट ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एसटीएल) के साथ मिलकर 4-कोर मल्टी-कोर फाइबर (एमसीएफ) पर भारत के पहले क्यूकेडी ट्रांसमिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह क्वांटम-सुरक्षित संचार नेटवर्क की दिशा में देश की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मल्टी-कोर फाइबर (एमसीएफ) तकनीक एक ही फाइबर के भीतर कई कोर में डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम करके शक्तिशाली समाधान प्रदान करती है। इससे भौतिक स्थान और बुनियादी ढांचे की लागत में काफी बचत होती है। क्यूकेडी के लिए आमतौर पर क्वांटम चैनल के लिए एक समर्पित डार्क फाइबर की आवश्यकता होती है।
- आंध्र प्रदेश के अमरावती में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव शुरू करके भारत अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग लगा रहा है। रीयल-टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (RTGS) की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में IBM, TCS और L&T जैसी अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इस प्रगतिशील परियोजना के रोडमैप को आकार देने के लिए भाग लिया। यह प्रस्तावित सुविधा क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान, नवाचार और पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए एक विश्वस्तरीय केंद्र बनने का लक्ष्य रखती है, जो उन्नत संगणन तकनीकों में भारत की वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
- बढ़ते साइबर अपराधों के खतरे के बीच, आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन ने 1 अप्रैल 2025 को साइबर कमांडोज़ के पहले बैच का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इस विशेष पहल का उद्देश्य पूरे भारत में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को उन्नत साइबर सुरक्षा तकनीकों से लैस करना है, ताकि वे तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल खतरों से प्रभावी रूप से निपट सकें।
- मेटा (Meta), जिसके सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग हैं, ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए एलएलएएमए-4 (Llama-4) नामक अगली पीढ़ी के बड़े भाषा मॉडल सूट को लॉन्च किया है। यह घोषणा 6 अप्रैल 2025 को की गई। इस सूट में तीन शक्तिशाली एआई मॉडल शामिल हैं – स्काउट (Scout), मैवरिक (Maverick), और बेहेमोथ (Behemoth) – जिन्हें मल्टीमॉडल क्षमताओं और तार्किक सोच के विभिन्न स्तरों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।
- भारत का पहला "एजेंटिक एआई हैकाथॉन", जिसे Techvantage.ai ने CrewAI के सहयोग से आयोजित किया, देश के एआई क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह आयोजन "एजेंटिक एआई वीक" के दौरान हुआ और इसमें देशभर से 1,500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो स्वायत्त एआई प्रणालियों के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। ये एआई एजेंट जटिल व्यावसायिक चुनौतियों को हल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और यह हैकाथॉन इस तेजी से उभरते क्षेत्र में नवाचार का एक मंच बना। यह एक महीने तक चलने वाली पहल थी, जिसमें कई शहरों में गतिविधियाँ हुईं और इसका भव्य समापन केरल के टेक्नोपार्क में हुआ।
- भारत ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह "आर्यभट" की स्वर्ण जयंती मनाई, जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट के नाम पर रखे गए इस उपग्रह ने भारत की वैज्ञानिक यात्रा में ऐतिहासिक छलांग का प्रतीक बनते हुए, इसरो (ISRO) को एक वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में उभरने की राह दिखाई। शीत युद्ध काल के दौरान तकनीकी संसाधनों और अवसंरचनात्मक सीमाओं के बावजूद, आर्यभट की सफलता ने भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की नींव रखी और आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है।

अंतरराष्ट्रीय

- बांग्लादेश ने 8 अप्रैल 2025 को आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी प्रतिबद्धता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकट किया। इस ऐतिहासिक कदम के साथ बांग्लादेश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया। यह कार्यक्रम ढाका में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा सचिव अशरफ उद्दीन ने बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया। वहीं, NASA की कार्यवाहक प्रशासक जेनेट पेट्रो ने बांग्लादेश के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे अंतरिक्ष सहयोग के नए युग की शुरुआत बताया।

- डालस स्थित बायोटेक कंपनी कोलॉसल बायोसाइंसेज़ ने पहली बार एक विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता प्राप्त की है — डायर वुल्फ (Dire Wolf), जो लगभग 12,500 साल पहले विलुप्त हो गई थी। आधुनिक डीएनए तकनीक और CRISPR जैसी जीन-संपादन तकनीकों का उपयोग करते हुए, कंपनी ने तीन डायर वुल्फ पिल्लों को जन्म दिया है। यह उपलब्धि "डी-एक्सटिंक्शन" (विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने) के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। कोलॉसल बायोसाइंसेज़ का उद्देश्य केवल विलुप्त जीवों को लौटाना नहीं है, बल्कि जैव-विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करने में भी योगदान देना है।
- सी-डॉट ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एसटीएल) के साथ मिलकर 4-कोर मल्टी-कोर फाइबर (एमसीएफ) पर भारत के पहले क्यूकेडी ट्रांसमिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह क्वांटम-सुरक्षित संचार नेटवर्क की दिशा में देश की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मल्टी-कोर फाइबर (एमसीएफ) तकनीक एक ही फाइबर के भीतर कई कोर में डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम करके शक्तिशाली समाधान प्रदान करती है। इससे भौतिक स्थान और बुनियादी ढांचे की लागत में काफी बचत होती है। क्यूकेडी के लिए आमतौर पर क्वांटम चैनल के लिए एक समर्पित डार्क फाइबर की आवश्यकता होती है।
- ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने 14 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक सबऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें केवल महिलाएं सवार थीं — यह 1963 के बाद पहली बार हुआ जब वलेन्टीना तेरेश्कोवा ने पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में उड़ान भरी थी। यह प्रक्षेपण टेक्सास के वैन हॉर्न से हुआ और इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी छह प्रमुख महिलाओं ने हिस्सा लिया। लगभग 10 मिनट की यह उड़ान व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा, एयरोस्पेस में लैंगिक प्रतिनिधित्व और पॉप कल्चर के माध्यम से वैज्ञानिक जागरूकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।
- बहुप्रतीक्षित NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) उपग्रह मिशन, जो भारत की इसरो और अमेरिका की नासा के बीच एक अनोखी सहयोगात्मक परियोजना है, अब जून 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह उपलब्धि कई बार की देरी के बाद सामने आई है, विशेष रूप से असेंबली और परीक्षण चरणों के दौरान। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को आगामी अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी दी, जिसमें NISAR और मई महीने में प्रस्तावित अन्य प्रमुख मिशन शामिल हैं।
- नासा (NASA) क्वांटम ग्रैविटी ग्रैडियोमीटर पाथफाइंडर (Quantum Gravity Gradiometer Pathfinder – QGGPf) के विकास का नेतृत्व कर रहा है। यह एक कॉम्पैक्ट और अत्यधिक संवेदनशील क्वांटम सेंसर है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को अभूतपूर्व सटीकता के साथ मानचित्रित करने का वादा करता है। यह नई तकनीक पृथ्वी की सतह और उपसतह को समझने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, जिससे जलवायु विज्ञान, संसाधन खोज, नेविगेशन और ग्रहों के अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में नए आयाम खुलेंगे।

खेल

क्रिकेट

- अनुभवी भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी शानदार प्रतिभा का परिचय देते हुए टी20 क्रिकेट में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2025 के मुकाबले में हासिल की गई यह उपलब्धि कोहली को दुनिया भर में शीर्ष पांच टी20 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल करती है।
- क्रिकेट आधिकारिक तौर पर लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक वापसी कर रहा है, जैसा कि 9 अप्रैल, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा पुष्टि की गई है। इस खेल में पुरुषों और महिलाओं के T20 टूर्नामेंट के लिए छह-छह टीमें होंगी, जिसमें प्रत्येक लिंग के लिए कुल 90 एथलीट कोटा होगा। यह 128 वर्षों के बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी को दर्शाता है, इससे पहले यह केवल 1900 पेरिस खेलों में ही शामिल हुआ था।
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली ने आईपीएल 2025 सीज़न में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। कोहली आईपीएल इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मिलाकर 1000 बाउंड्रीज़ (चौके + छक्के) का आंकड़ा पार किया। यह कीर्तिमान बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB बनाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) मुकाबले के दौरान दर्ज किया गया।
- भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर को मार्च 2025 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यह सम्मान उन्हें ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। अय्यर ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 243 रन बनाए। उन्होंने इस खिताब की दौड़ में न्यूज़ीलैंड के जैकब डफी और राचिन रविंद्र को पीछे छोड़ा। इस तरह भारत के लिए यह लगातार दूसरा महीना रहा जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने यह सम्मान जीता—फरवरी 2025 में यह पुरस्कार शुभमन गिल को मिला था। श्रेयस अय्यर के दबाव भरे मुकाबलों में लगातार अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में एक मजबूत और विश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों के अधिकारों और आकांक्षाओं की रक्षा करने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कार्यबल का गठन करने की घोषणा की है। यह पहल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB), और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के साथ साझेदारी में की गई है। इसका उद्देश्य इन खिलाड़ियों को आर्थिक और विकासात्मक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे विस्थापन और राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद अपने क्रिकेट सफर को जारी रख सकें।

- विराट कोहली, जो आधुनिक क्रिकेट के दिग्गजों में गिने जाते हैं, ने IPL 2025 के दौरान टी20 क्रिकेट में अपना 100वां अर्धशतक बनाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह यादगार पारी मैच 28 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में खेली गई, जहां कोहली ने 45 गेंदों पर नाबाद 62 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। यह पारी IPL में उनका 66वां 50+ स्कोर भी था, जिससे वह डेविड वॉर्नर के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक 50+ स्कोर वाले खिलाड़ी बन गए। यह उपलब्धि कोहली की लगातार प्रदर्शन करने की क्षमता और टी20 फॉर्मेट में उनकी लंबी उम्र और क्लास को दर्शाती है।
- मुंबई इंडियंस (MI) के ओपनिंग बल्लेबाज़ रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए हैं। वह यह मुकाम हासिल करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने हैं। यह उपलब्धि रोहित ने आईपीएल 2025 के मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेले गए मैच के दौरान हासिल की। रोहित अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 12,000 से अधिक रन बनाए हैं — वह ऐसा करने वाले दुनिया के आठवें बल्लेबाज़ हैं। रोहित की निरंतरता और नेतृत्व ने उन्हें MI के लिए एक अहम खिलाड़ी बना दिया है, और उनके योगदान ने वर्षों से टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में एक और शानदार कीर्तिमान स्थापित करते हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ सबसे ज़्यादा फिफ्टी-प्लस स्कोर (50 से अधिक रन की पारियाँ) बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मुल्लांपुर में खेले गए रोमांचक मुकाबले में हासिल की। कोहली ने 54 गेंदों में नाबाद 73 रन की ज़िम्मेदार पारी खेली, जिससे RCB ने 158 रनों का लक्ष्य 7 विकेट से हासिल कर लिया। यह विराट कोहली का आईपीएल में 67वां फिफ्टी-प्लस स्कोर है, जो उनकी निरंतरता और टी20 क्रिकेट में अद्वितीय कौशल का प्रमाण है। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने कोहली को लीग के सबसे प्रभावशाली और भरोसेमंद खिलाड़ियों में और भी मजबूत स्थान दिलाया है।

बैडमिंटन और टेनिस

- बॉम्बे जिमखाना, मुंबई (24-28 मार्च, 2025) में आयोजित इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर इवेंट में अनाहत सिंह ने अपना 11वां पीएसए खिताब जीता, जिससे भारत की शीर्ष रैंक वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी के रूप में उनकी स्थिति फिर से पुख्ता हुई, जबकि करीम एल टॉर्की (मिस्र, विश्व नंबर 64) ने पुरुष एकल फाइनल में अभय सिंह (भारत) के खिलाफ जीत हासिल की। 53,500 डॉलर की पुरस्कार राशि के साथ, यह 2018 के बाद से भारत का सबसे अधिक रेटिंग वाला पीएसए इवेंट था और देश में आयोजित पहला पीएसए कॉपर इवेंट था।
- विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने फाइनल में जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर मियामी ओपन का अपना पहला खिताब जीता, इस तरह उन्होंने टूर्नामेंट में कोई भी सेट गंवाए बिना खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही उन्होंने 19वां WTA खिताब अपने नाम कर लिया, जिसमें 8 WTA 1000 खिताब और 3 ग्रैंड स्लैम खिताब शामिल हैं। सबालेंका का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने पहले सेट में पेगुला की सर्विस को लव के लिए तोड़ा और दूसरे सेट में आक्रामक शॉट-मेकिंग का प्रदर्शन किया।

हॉकी

- भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 15 साल के शानदार करियर के बाद 2 अप्रैल, 2024 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। 32 वर्षीय स्ट्राइकर, जिन्होंने 320 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 158 गोल किए हैं, भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। कटारिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी भावनात्मक विदाई साझा की, जिसमें उन्होंने अपने करियर के "चरम" पर कदम पीछे खींचने के अपने फ़ैसले पर ज़ोर दिया, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खेल को छोड़ने का फ़ैसला किया।

रेसिंग

- फ्रांसेस्को बैगनिया ने अमेरिका के ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की, जब मार्क मार्केज़ सर्किट ऑफ़ द अमेरिकाज़ (COTA) में नौवें लैप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। डुकाटी ने पोडियम पर अपना दबदबा बनाया, एलेक्स मार्केज़ दूसरे और फैबियो डि जियानान्टोनियो तीसरे स्थान पर रहे, जिससे डुकाटी की लगातार 20वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत दर्ज हुई, जो होंडा के रिकॉर्ड (22) से सिर्फ़ दो जीत पीछे है।
- मैक्स वर्स्टैपेन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स में 2025 फॉर्मूला 1 सीज़न की अपनी पहली रेस जीती, जिससे उनकी लगातार चौथी जीत सुनिश्चित हुई। मैकलारेन के लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्त्री के साथ एक करीबी मुकाबले के बाद, वर्स्टैपेन ने रणनीतिक पिट स्टॉप और टायर विकल्पों की मदद से बढ़त बनाए रखी। पोल पोजिशन के लिए क्वालीफाइंग में उन्होंने नॉरिस को सिर्फ़ 0.012 सेकंड से पीछे छोड़ा। यह रेस रेड बुल के लिए भी महत्वपूर्ण थी, जो होंडा पावर के साथ उनकी आखिरी रेस थी। वर्स्टैपेन ने स्टैंडिंग में अपनी बढ़त को बढ़ाया, अब नॉरिस से सिर्फ़ एक अंक आगे हैं। अन्य उल्लेखनीय फिनिश में चार्ल्स लेक्लर (फेरारी) चौथे और जॉर्ज रसेल (मर्सिडीज) पांचवें स्थान पर रहे।

एथलेटिक और फुटबॉल

- भारत ने ब्राजील के फोज डू इगुआकु में 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में ऐतिहासिक शुरुआत की, हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए। उनकी जीत तब हुई जब उनके प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के ओडेल कामारा चोट के कारण प्रतियोगिता से हट गए। अभिनाश जामवाल ने 65 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि जदुमणि सिंह मंडेंगबाम, मनीष राठौर, सचिन और विशाल ने कांस्य पदक जीते। भारत ने कुल छह पदक जीते, जो विश्व मुक्केबाजी कप में अपनी पहली भागीदारी में एक मजबूत प्रदर्शन था, जिसने 2028 ओलंपिक से पहले एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया।
- भारत ने अम्मान में 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्रीस्टाइल और ग्रीको-रोमन कुश्ती में दमदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते। मनीषा भानवाला (62 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि दीपक पुनिया (92 किग्रा), उदित (61 किग्रा) और रीतिका हुड्डा (76 किग्रा) ने रजत पदक जीता। अंतिम पंगल (53 किग्रा) और दिनेश (125 किग्रा) सहित छह पहलवानों ने कांस्य पदक जीता। 30 सदस्यीय दल में मानसी लाठेर और मुकुल दहिया जैसी शीर्ष प्रतिभाएँ शामिल थीं, जिन्होंने महाद्वीपीय कुश्ती में भारत के प्रभुत्व को मजबूत किया।

OTHER SPORTS NEWS

- मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, ने आधिकारिक तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। वे श्रीलंका के शम्मी सिल्वा का स्थान लेंगे और महाद्वीप की क्रिकेट संस्था का नेतृत्व करने पर गर्व व्यक्त किया।
- कारगिल विजय दिवस 2025 समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय सेना द्वारा जुबर स्टेडियम में बटालिक क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना, खेलों को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को जोड़ना था। यह स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देने का भी एक प्रयास था।
- नई दिल्ली में आयोजित अदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 का समापन एक रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ हुआ, जिसमें राजनिगंधा अचीवर्स ने जिंदल पैंथर को हराकर खिताब अपने नाम किया। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट स्वर्गीय श्री अदित्य विक्रम बिड़ला के पोलो खेल के प्रति प्रेम को समर्पित है और इसमें दुनिया के कुछ बेहतरीन पोलो खिलाड़ियों ने भाग लिया।
- भारत की मुक्केबाज़ी टीम ने ब्राज़ील के फॉज़ डू इगुआसू में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अपने पहले ही प्रयास में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में हितेश गुलिया ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और अब तक के एकमात्र भारतीय मुक्केबाज़ बने। उनका यह ऐतिहासिक जीत तब और खास बन गई जब फाइनल में उनके प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के ओडेल कैमारा चोट के चलते मुकाबले में नहीं उतर पाए। हितेश की इस उपलब्धि के अलावा, अभिनाश जम्वाल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया, जबकि चार अन्य भारतीय मुक्केबाज़ों ने विभिन्न भार वर्गों में कांस्य पदक अपने नाम किए।
- मैक्स वेरस्टैपेन ने 2025 जापानी ग्रैंड प्रिक्स में मैकलारेन के ड्राइवर लैंडो नोरिस और ऑस्कर पियास्ट्री को पछाड़कर लगातार चौथी जीत दर्ज की। वेरस्टैपेन की पोल पोजीशन और रेस में लगातार बेहतर प्रदर्शन ने उन्हें स्टैंडिंग में अपनी बढ़त को और मजबूत करने में मदद की, अब वे नोरिस से सिर्फ़ एक अंक पीछे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड किंगडम) 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए एकमात्र "वैध" बोलीदाता बनकर उभरा है। इस बात की पुष्टि फीफा अध्यक्ष जियानी इनफैंटिनो ने की है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से यह बोली प्रस्तुत की गई है, जिससे यह तय माना जा रहा है कि यह टूर्नामेंट एक बार फिर यूरोप में लौटेगा—2023 संस्करण के बाद पहली बार। यह ऐतिहासिक अवसर 2022 में आयोजित UEFA महिला यूरो जैसे सफल आयोजनों की सफलता के बाद आया है और यह क्षेत्र में महिला फुटबॉल के बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता को भी दर्शाता है।
- उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय निशानेबाज़ सौरभ चौधरी ने पेरू के लीमा में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप (अप्रैल 2025) में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारतीय निशानेबाज़ी टीम में शानदार वापसी की। ओलंपिक चैंपियनों से सजी इस फाइनल में उन्होंने कड़ी टक्कर और कम स्कोर वाले मुकाबले में धैर्य और साहस का परिचय दिया। यह उनका दो वर्षों में पहला व्यक्तिगत वर्ल्ड कप पदक है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी जबरदस्त वापसी को दर्शाता है।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) 2025 पहली बार बिहार में आयोजित होने जा रहे हैं, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक होगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना में किया जाएगा। यह कार्यक्रम न केवल राज्य में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि बिहार के खेल बुनियादी ढांचे को भी मज़बूती प्रदान करेगा और उभरते हुए खिलाड़ियों को एक राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराएगा।
- कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में 13 अप्रैल 2025 को मोहन बागान सुपर जायंट ने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराकर इंडियन सुपर लीग (ISL) 2024-25 का खिताब अपने नाम किया। यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक रही – पहली बार किसी टीम ने घरेलू मैदान पर ISL फाइनल जीता, और मोहन बागान पहली टीम बनी जिसने लीग शील्ड और ISL ट्रॉफी दोनों एक ही सीज़न में अपने नाम की।
- भारत ने अंतरराष्ट्रीय शूटिंग सत्र की शानदार शुरुआत करते हुए 2025 के पहले ISSF विश्व कप (राइफल, पिस्टल और शॉटगन वर्गों के लिए) में कुल दूसरा स्थान हासिल किया। यह टूर्नामेंट आगामी पेरिस ओलंपिक से पहले आयोजित किया गया, जिसमें भारत की युवा और अनुभवी प्रतिभा का बेहतरीन संगम देखने को मिला। हालांकि अंतिम स्पर्धा में भारत मामूली अंतर से पदक से चूक गया, फिर भी भारतीय दल ने कुल 8 पदक जीतकर अपनी क्षमता, निरंतरता और उज्ज्वल भविष्य की मजबूत झलक पेश की। यह प्रदर्शन आने वाले ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों और उम्मीदों को और मजबूत करता है।

- मैकलारेन के ऑस्कर पियास्त्री ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 2025 फॉर्मूला 1 सीजन की अपनी दूसरी जीत हासिल की। पियास्त्री, जिन्होंने पोल पोजीशन से शुरुआत की, ने रेस में सेफ्टी कार के हस्तक्षेप के बावजूद दबदबा बनाए रखा, जो उनके और टीममेट लैंडो नॉरिस के साथ खिताबी संघर्ष को मजबूत करता है। इस जीत के साथ, वह 2025 सीजन के पहले रिपीट विजेता बने और मैकलारेन के लिए उनके बहरेनी मालिकों के होम ट्रैक पर पहली जीत दर्ज की।
- भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम, जिसमें धीरज बोम्मादेवर, अतानु दास, और तरुणदीप राय शामिल थे, ने अपनी 2025 सीजन की शुरुआत ऑबर्नडेल, फ्लोरिडा में आयोजित विश्व कप स्टेज 1 में रजत पदक के साथ की। हालांकि, वे दुनिया की नंबर दो टीम थे, भारतीय त्रयी फाइनल में चीन से 1-5 से हार गई, जो इस टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पर थी। भारतीय टीम ने इससे पहले सेमीफाइनल में स्पेन (8वीं सीड) को हराया था।
- दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जो 3 से 5 मई तक रांची, झारखंड में आयोजित होने वाली थी, को सात महीनों में दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है। पहले यह प्रतियोगिता अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित थी, लेकिन इस बार की देरी का कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वीज़ा क्लीयरेंस से जुड़ी समस्याएं बताई जा रही हैं। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दक्षिण एशिया के शीर्ष एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद थी, जिनमें पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम और श्रीलंका के प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। अब इस आयोजन के लिए नई संभावित तारीख जून 2025 के दूसरे या तीसरे सप्ताह की तय की गई है, जो वीज़ा मुद्दों के समाधान पर निर्भर करेगी।

पुस्तक एवं लेखक

पुस्तक का नाम	लेखक / प्रकाशक	मुख्य बिंदु
द ग्रेट कन्सिलिएटर: लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया	संजीव चोपड़ा	• यह पुस्तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और योगदान पर प्रकाश डालती है। इसमें BSF की स्थापना और "जय जवान, जय किसान" नारे की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित किया गया है।
द इंडिया आई सॉ	एस. अम्बुजम्मल	• एस. अम्बुजम्मल की आत्मकथा 'नान कांडा भारतम' (अनुवाद: The India I Saw) में उनके संघर्षों और सामाजिक सुधार कार्यों का वर्णन है। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गांधीवादी थीं, जिन्होंने महिला कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
केयरलेस पीपल	सारा विन-विलियम्स	• फेसबुक (अब मेटा) की पूर्व नीति निदेशक सारा द्वारा लिखित इस पुस्तक में कंपनी के अंदर चल रहे नैतिक पतन, नेतृत्व विफलताओं, और विवादास्पद वैश्विक हस्तक्षेप (जैसे 2016 अमेरिकी चुनाव, म्यांमार संकट) का खुलासा किया गया है।
आई एम सर्कुलर	MeitY व इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी (ICCE)	• यह कॉफी टेबल बुक भारत में परिपत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 30 नवाचारों को प्रदर्शित करती है। इसमें ई-कचरा रीसाइक्लिंग, IoT-आधारित समाधान, और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग जैसी पहल शामिल हैं। इसे 23 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया।
संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय	(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन)	• यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संग्रह है जो भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और परंपरागत धरोहर पर केंद्रित है। 18 अप्रैल 2025 को IGNCA नई दिल्ली में इसका विमोचन हुआ, जिसमें कई प्रमुख संत और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

निधन

राष्ट्रीय

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	मुख्य तथ्य
1	मनोज कुमार	बॉलीवुड अभिनेता	पाकिस्तान (जन्म: हरिकृष्ण गिरि गोस्वामी)	• 87 वर्ष की आयु में निधन। "हरियाली और रास्ता", "वो कौन थी?", "पत्थर के सनम" जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि। देशभक्ति फिल्मों के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते हैं। विभाजन के बाद दिल्ली में बसे।
2	रविकुमार	मलयालम व तमिल फिल्म अभिनेता	चेन्नई	• 71 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को निधन। "उल्लास यात्रा" (1975), "अवरगल" (1977) जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध। फिल्मी परिवार से संबंध—माता भारती, पिता के.एम.के. मेनन।
3	पद्मश्री राम सहाय पांडे	राय लोकनृत्य के कलाकार	सागर, मध्य प्रदेश	• 92 वर्ष की आयु में निधन। गरीबी और सामाजिक प्रतिबंधों के बावजूद राय नृत्य को लोकप्रिय सांस्कृतिक पहचान में बदलने का कार्य किया। इस लोकनृत्य को नवजीवन देने के लिए सराहे गए।

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	मुख्य तथ्य
4	दादी रतन मोहिनी	आध्यात्मिक नेत्री (ब्रह्मा कुमारी)	हैदराबाद, सिंध (अब पाकिस्तान)	• 100 वर्ष की आयु में 8 अप्रैल 2025 को निधन। ब्रह्मा कुमारीज़ की प्रमुख प्रशासक (2021 से)। विश्व शांति सम्मेलन 1954 में प्रतिनिधित्व किया। विश्वभर में शांति और मूल्यों का प्रचार-प्रसार किया।
5	कुमुदिनी लाखिया	कथक नृत्यांगना	भारत	• (1930–2024) में निधन। कथक को कथा और साहित्य पर निर्भरता से बाहर निकालकर आधुनिक विषयों और समूह-नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया। राम गोपाल के साथ यूरोप दौरे से वैश्विक दृष्टिकोण मिला।
6	डॉ. के. कस्तूरीरंगन	वैज्ञानिक, पूर्व ISRO अध्यक्ष	भारत	• 84 वर्ष की आयु में 25 अप्रैल 2025 को निधन। PSLV, GSLV, IRS-1A और भास्कर-I व II मिशनों में अग्रणी भूमिका। 1994–2003 तक ISRO प्रमुख रहे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में चार दशकों तक अमूल्य योगदान।
7	एम. जी. एस. नारायणन	इतिहासकार	पोननी, केरल	• 92 वर्ष की आयु में निधन। केरल और दक्षिण भारत के प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास के विशेषज्ञ। ICHR के सदस्य सचिव और अध्यक्ष रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए सराहे गए।

अंतरराष्ट्रीय

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	मुख्य तथ्य
1	रिचर्ड चेम्बरलिन	अमेरिकी अभिनेता	बेवर्ली हिल्स, कैलिफ़ोर्निया	• "मिनीसिरीज़ के राजा" के रूप में प्रसिद्ध। 90 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2024 को हवाई के वाइमनालो में निधन। 'Dr. Kildare' (1961–66) में डॉ. जेम्स की भूमिका से लोकप्रियता। युद्ध सेवा के बाद अभिनय को अपनाया। 1963–65 तक 'Most Popular Male Star' का खिताब जीता।
2	वेल किल्मर	अमेरिकी अभिनेता	लॉस एंजेलेस, कैलिफ़ोर्निया	• 65 वर्ष की आयु में न्यूमोनिया से निधन। 'Top Gun', 'Batman Forever', 'The Doors' जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं। जूलियार्ड ड्रामा डिवीजन में सबसे कम उम्र में प्रवेश। 'Top Secret!' (1984) से हॉलीवुड में शुरुआत की। वर्षों तक गले के कैंसर से जूझे।
3	जीन मार्श	ब्रिटिश अभिनेत्री व पटकथाकार	लंदन, यूनाइटेड किंगडम	• 90 वर्ष की आयु में 13 अप्रैल 2025 को डिमेंशिया से निधन। 'Upstairs, Downstairs' की सह-निर्माता व अभिनेत्री। Emmy पुरस्कार विजेता भूमिका 'Mrs. Rose Buck' से प्रसिद्ध। ब्रिटिश टेलीविजन में गहरी छाप छोड़ी।
4	पोप फ्रांसिस	कैथोलिक धर्मगुरु (पोप)	ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना	• 88 वर्ष की आयु में डबल न्यूमोनिया से निधन। 2013 में पहले लैटिन अमेरिकी, जेसुइट व गैर-यूरोपीय पोप बने। समलैंगिक अधिकारों, जलवायु संरक्षण, प्रवासियों और सामाजिक न्याय पर प्रगतिशील विचार। वेटिकन सुधारों और अंतर-धार्मिक संवाद के पक्षधर।
5	मारियो वर्गास योसा	पेरूवियन लेखक व पत्रकार	अरेक्विपा, पेरू	• 89 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 2025 को निधन। 2010 में साहित्य के नोबेल विजेता। 'The Time of the Hero', 'The Green House' सहित 30+ पुस्तकों के लेखक। सत्ता और व्यक्ति के संघर्ष की विषयवस्तु पर केंद्रित लेखन। राजनीति और साहित्य दोनों में वैश्विक प्रभावशाली व्यक्तित्व।

महत्वपूर्ण दिवस

दिनांक	दिवस/अवसर	विषय/विवरण
1 अप्रैल	उत्कल दिवस (ओडिशा दिवस)	• 1936 में ओडिशा का गठन, भारत का पहला भाषाई राज्य; कालिंग युद्ध और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान।
2 अप्रैल	विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस	• विषय: "न्यूरोडायवर्सिटी और सतत विकास लक्ष्य (SDGs) को बढ़ावा देना"।
4 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस	• विषय: "सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है" — युद्ध क्षेत्रों में बारूदी सुरंगों से निपटने पर ध्यान।
5 अप्रैल	समता दिवस	• बाबू जगजीवन राम की जयंती; सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित।
5 अप्रैल	राष्ट्रीय समुद्री दिवस	• 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की पहली समुद्री यात्रा की स्मृति में।

दिनांक	दिवस/अवसर	विषय/विवरण
6 अप्रैल	स्वामीनारायण जयंती	• भगवान स्वामीनारायण की जयंती; चैत शुक्ल नवमी को राम नवमी के साथ मनाई जाती है।
6 अप्रैल	खेल के माध्यम से विकास व शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	• विषय: "खेल से सामाजिक समावेश की ओर"।
7 अप्रैल	विश्व स्वास्थ्य दिवस	• विषय: "स्वस्थ प्रारंभ, आशापूर्ण भविष्य" — मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर केंद्रित।
7 अप्रैल	**1994** तुत्सी नरसंहार की अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस	• रवांडा में हुए नरसंहार की स्मृति में; शांति व शिक्षा के महत्व पर बल।
10 अप्रैल	महावीर जयंती	• भगवान महावीर की 2623वीं जयंती; अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का संदेश।
10 अप्रैल	विश्व होम्योपैथी दिवस	• डॉ. हैनिमन की जयंती; "समान समान को ठीक करता है" सिद्धांत को बढ़ावा।
13 अप्रैल	सियाचिन दिवस	• ऑपरेशन मेघदूत (1984) की स्मृति में; दुनिया के सबसे ऊँचे युद्धक्षेत्र की सुरक्षा।
14 अप्रैल	अंबेडकर जयंती	• डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती; संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रणेता।
14 अप्रैल	विश्व शगास रोग दिवस	• लैटिन अमेरिका में प्रचलित एक मौन परजीवी रोग के प्रति जागरूकता।
15 अप्रैल	हिमाचल दिवस	• 1948 में प्रांत के रूप में गठन; 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा।
15 अप्रैल	विश्व कला दिवस	• लिओनार्डो दा विंची की जयंती पर; विषय: "एकता और उपचार हेतु कला"।
18 अप्रैल	विश्व धरोहर दिवस	• विषय: "आपदाओं और संघर्षों से विरासत को खतरा" — संरक्षण पर जागरूकता।
19 अप्रैल	विश्व यकृत दिवस	• विषय: "भोजन ही दवा है" — यकृत स्वास्थ्य में पोषण की भूमिका।
21 अप्रैल	राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस	• सरदार पटेल द्वारा 1947 में 'भारत की स्टील फ्रेम' कहे गए IAS अधिकारियों की स्मृति में।
21 अप्रैल	विश्व रचनात्मकता व नवाचार दिवस	• नवाचार और समस्या समाधान की वैश्विक भूमिका को उजागर करता है।
22 अप्रैल	पृथ्वी दिवस	• विषय: "हमारी शक्ति, हमारा ग्रह" — पर्यावरणीय जिम्मेदारी और नवीकरणीय ऊर्जा पर बल।
23 अप्रैल	विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस	• विषय: "एसडीजी प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका" — साहित्य व लेखकों का सम्मान।
24 अप्रैल	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस	• 73वें संविधान संशोधन की वर्षगांठ; ग्राम स्वराज व डिजिटल पंचायतों का उत्सव।
24–30 अप्रैल	विश्व टीकाकरण सप्ताह	• विषय: "सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है" — जीवन रक्षक टीकों के प्रति जागरूकता।
25 अप्रैल	विश्व मलेरिया दिवस	• विषय: "मलेरिया समाप्त करें: पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनःजागरण"।
25 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस	• 1945 में UN चार्टर ड्राफ्ट करने वाले प्रतिनिधियों की भूमिका को सम्मान।

विविध

- बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर की एक महत्वपूर्ण कंपनी HIL लिमिटेड और सीके बिरला ग्रुप का हिस्सा, ने रीब्रांडिंग की है और अब इसे BirlaNu लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। यह बदलाव निर्माण उद्योग के लिए गुणवत्ता, नवाचार और स्थायी उत्पाद बनाने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- कुंभकोणम पान पत्ता (थंजावुर) और थोवलई फूलों की माला (कन्याकुमारी) को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है। इस मान्यता के साथ, तमिलनाडु के कुल जीआई उत्पादों की संख्या 62 हो गई है। चार महीने की समीक्षा प्रक्रिया के बाद, 30 नवंबर 2024 को सरकारी गजट में इन उत्पादों की आधिकारिक जीआई स्थिति प्रकाशित की गई।
- अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र में कारीगरों द्वारा सदियों से संजोई गई पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है। यह अनूठी हस्तनिर्मित वस्त्र कला गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया गया है।
- मिस्र के रेड सी में 27 मार्च 2025 को हर्गदा तट के पास पर्यटकों के लिए उपयोग की जाने वाली सिनाबाद पनडुब्बी डूब गई। इस दुर्घटना में छह विदेशी पर्यटकों की मृत्यु हो गई, जिनमें सभी रूसी नागरिक थे। यह पनडुब्बी 45 विदेशी पर्यटकों और पांच मिस्री क्रू सदस्यों के साथ नियमित यात्रा पर थी जब यह हादसा हुआ।
- पश्चिम बंगाल ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राज्य के सात पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हुआ है, जिनमें प्रसिद्ध नोलें गुड़र संदेश और बारुईपुर अमरूद शामिल हैं। इस मान्यता से इन पारंपरिक वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी, जिससे राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और इसकी सांस्कृतिक पहचान और सशक्त होगी।
- यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी शाहरुख खान और काजोल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। डीडीएलजे अब लीसेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन जाएगी, जिससे जुड़ा स्टैच्यू यहां लगेगा। शाहरुख और काजोल का फिल्म के एक सीन का स्टैच्यू 'सीन्स इन द स्क्वायर' में लगेगा। इसकी घोषणा हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस ने की। लीसेस्टर स्क्वायर में 'सीन्स इन द स्क्वायर' मूवी ट्रेल में अब डीडीएलजे के रूप में एक नई प्रतिमा लगेगी। यह हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म के 30 साल पूरे होने के जश्न की शुरूआत होगी।
- केंद्र सरकार ने मेघालय के दो पारंपरिक वस्त्र उत्पादों – रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किए हैं। यह मान्यता न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देती है बल्कि इसके स्वदेशी शिल्प को कानूनी संरक्षण और बेहतर बाज़ारीकरण भी प्रदान करती है।
- हाल ही में बनारस शहनाई को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया जाना भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को एक ऐतिहासिक मान्यता है। पूरी दुनिया में उस्ताद बिस्मिल्ला खान के माध्यम से प्रसिद्ध हुई शहनाई केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक संगीत का प्रतीक है। वाराणसी (काशी) के पारंपरिक कारीगरों के लिए यह GI टैग केवल एक आधिकारिक प्रमाणपत्र नहीं है, बल्कि उनकी पीढ़ियों से चली आ रही विरासत, निष्ठा और शिल्प कौशल को मिला एक भावनात्मक और सांस्कृतिक सम्मान है।

स्थैतिक टेकअवे

क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
संगठन		
1	एशियाई विकास बैंक	राष्ट्रपति - मासातो कांडा मुख्यालय - मांडलुयॉन्ग, मनीला, फिलीपींस
2	आरबीआई	राज्यपाल - संजय मल्होत्रा मुख्यालय - मुंबई
3	एसबीआई	अध्यक्ष - चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी मुख्यालय - मुंबई
4	एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाएँ	एमडी और सीईओ - सलिला पांडे
5	डीबीएस बैंक इंडिया	एमडी और सीईओ - रजत वर्मा
6	टाटा संस	अध्यक्ष - नटराजन चन्द्रशेखरन
7	एक्सिस बैंक	एमडी और सीईओ - अमिताभ चौधरी
8	फिक्की	अध्यक्ष - हर्ष वर्धन अग्रवाल
9	आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड	सीईओ - विशाखा मुले
10	रेनॉल्ट ग्रुप	सीईओ - वेंकटराम मामिलापल्ले
11	निसान इंडिया	सीईओ-सौरभ वत्स

क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
12	स्पेस एक्स	सीईओ - एलोन मस्क
13	माइक्रोसॉफ्ट	सीईओ - सत्या नडेला
14	एशियाई क्रिकेट परिषद	अध्यक्ष - मोहसिन नकवी मुख्यालय - दुबई
देश		
15	यूएसए	राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प मुद्रा - अमेरिकी डॉलर राजधानी - वाशिंगटन डी.सी.
16	ब्राजील	राष्ट्रपति - लूला दा सिल्वा मुद्रा - ब्राज़ीलियन रियल राजधानी - ब्राज़ीलिया
17	म्यांमार	राष्ट्रपति - मिन आंग ह्लाइंग (कार्यवाहक) मुद्रा - क्यात राजधानी - नेपीडॉ
18	सिंगापुर	प्रधानमंत्री - लॉरेंस वोंग मुद्रा - सिंगापुर डॉलर राजधानी - सिंगापुर
19	थाईलैंड	राष्ट्रपति - पैटोंगटार्न शिनावात्रा मुद्रा - थाई बात राजधानी - बैंकॉक
20	जापान	पीएम - इशिबा शिगेरु मुद्रा - यान राजधानी-टोक्यो
21	रूस	राष्ट्रपति - व्लादिमीर पुतिन मुद्रा - रूसी रूबल राजधानी - मास्को
राज्य		
22	असम	राज्यपाल- लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सीएम-हेमंत बिस्वा सरमा राजधानी - दिसपुर
23	पंजाब	राज्यपाल- गुलाब चंद सीएम - भगवंत मान राजधानी - चंडीगढ़
24	छत्तीसगढ़	राज्यपाल- रामेन डेका सीएम-विष्णुदेव साय राजधानी - रायपुर
25	पश्चिम बंगाल	राज्यपाल- सी. वी. आनंद बोस मुख्यमंत्री - ममता बनर्जी राजधानी - कोलकाता
26	महाराष्ट्र	राज्यपाल- सी. पी. राधाकृष्णन मुख्यमंत्री - देवेंद्र फडणवीस राजधानी - मुंबई
27	तेलंगाना	राज्यपाल- जिष्णु देव वर्मा सीएम - रेवंत रेड्डी राजधानी - हैदराबाद
28	आंध्र प्रदेश	राज्यपाल- एस. अब्दुल नज़ीर सीएम - चंद्रबाबू नायडू राजधानी - अमरावती

क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
29	ओडिशा	राज्यपाल- हरि बाबू कंभमपति सीएम - मोहन चरण माझी राजधानी-भुवनेश्वर

क्रमांक	नाम	विवरण
		संगठन
1	यूनेस्को	मुख्यालय - पेरिस, फ्रांस
2	सेबी	अध्यक्ष - तुहिन कांता पांडे प्रधान कार्यालय - मुंबई
3	स्विगी	संस्थापक - श्रीहर्ष मेजेस्टी, नंदन रेड्डी, राहुल जैमिनी
4	ब्लू ओरिजिन	सीईओ - डेव लिम्प
5	अडानी लिमिटेड	अध्यक्ष - गौतम अडानी
6	डब्ल्यूएचओ	महानिदेशक - टेड्रोस एडनोम घेब्रेयसस
7	भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार	अजय कुमार सूद
8	इंडसइंड बैंक	एमडी - सुमंत कथपालिया मुख्य कार्यालय - मुंबई
		देश
9	संयुक्त राज्य अमेरिका	राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी - वाशिंगटन डी.सी. मुद्रा - **USD**
10	चीन	राष्ट्रपति - शी जिनपिंग राजधानी - बीजिंग मुद्रा - युआन
11	गैबॉन	राष्ट्रपति - ब्राइस ओलिगुई नगोमा राजधानी - लिब्रेविल मुद्रा - सीएफए फ्रैंक
12	इक्वाडोर	राष्ट्रपति - डेनियल नोबोआ राजधानी - क्विटो मुद्रा: अमरीकी डॉलर
13	तंजानिया	राष्ट्रपति - सामिया सुलुहू राजधानी - डोडोमा
14	यूएई	राष्ट्रपति - शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान राजधानी - अबू धाबी मुद्रा - यूएई दिरहम
		भारतीय राज्य
15	केरल	गवर्नर - आर्लेकर सीएम- पिनाराई विजयन राजधानी - तिरुवनंतपुरम
16	तमिलनाडु	राज्यपाल - आर. एन. रवि मुख्यमंत्री - एम. के. स्टालिन राजधानी - चेन्नई
17	मेघालय	राज्यपाल - सी. विजयशंकर मुख्यमंत्री - कॉनराड संगमा राजधानी - शिलांग
18	अरुणाचल प्रदेश	राज्यपाल - कैवल्य परनायक सीएम- पेमा खांडू राजधानी - ईटानगर

क्रमांक	नाम	विवरण
19	तेलंगाना	राज्यपाल - जिष्णु देव वर्मा सीएम - रेवंत रेड्डी राजधानी - हैदराबाद
20	गुजरात	राज्यपाल - आचार्य देवव्रत सीएम-भूपेंद्र पटेल राजधानी - गांधीनगर
21	मध्य प्रदेश	राज्यपाल - मंगुभाई पटेल सीएम - मोहन यादव राजधानी - भोपाल
22	पश्चिम बंगाल	राज्यपाल - सी. वी. आनंद बोस मुख्यमंत्री - ममता बनर्जी राजधानी - कोलकाता

क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
संगठन		
1	इसरो	अध्यक्ष - वी नारायणन
2	आरबीआई	राज्यपाल - संजय मल्होत्रा
3	सेबी	अध्यक्ष - तुहिन कांता पांडे
4	एसबीआई	अध्यक्ष - चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी
5	पीएनबी (पंजाब नेशनल बैंक)	एमडी/सीईओ - अशोक चंद्रा
6	यूनेस्को	मुख्यालय - पेरिस
7	आईएमएफ	राष्ट्रपति - क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
8	विश्व बैंक	अध्यक्ष - अजय बंगा
9	बोइंग	सीईओ - केली ऑर्टबर्ग
10	एयर इंडिया	सीईओ - कैम्पबेल विल्सन
11	रिलायंस इंडस्ट्रीज	अध्यक्ष - मुकेश अंबानी
देश		
12	यूएसए	राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी - वाशिंगटन डी.सी. मुद्रा - **USD**
13	चीन	राष्ट्रपति - शी जिनपिंग राजधानी - बीजिंग मुद्रा - युआन
14	कजाकिस्तान	राष्ट्रपति - कसम टोकयेव राजधानी - तेंगे मुद्रा-अस्ताना
15	सऊदी अरब	राष्ट्रपति - मोहम्मद बिन सलमान राजधानी - रियाद मुद्रा - सऊदी रियाल
16	दक्षिण अफ्रीका	राष्ट्रपति - सिरिल रामफोसा
17	केन्या	राष्ट्रपति - विलियम रुटो राजधानी - नैरोबी मुद्रा - शिलिंग
18	रूस	राष्ट्रपति - व्लादिमीर पुतिन राजधानी - मास्को मुद्रा - रूबल

क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
19	फ्रांस	राष्ट्रपति - इमैनुएल मैक्रों राजधानी - पेरिस मुद्रा - यूरो
भारतीय राज्य		
20	आंध्र प्रदेश	राज्यपाल - एस अब्दुल नज़ीर सीएम - चंद्रबाबू नायडू राजधानी - अमरावती
21	तेलंगाना	राज्यपाल - जिष्णु देव वर्मा सीएम - रेवंत रेड्डी राजधानी - हैदराबाद
22	बिहार	राज्यपाल - आरिफ खान मुख्यमंत्री - नीतीश कुमार राजधानी - पटना
23	महाराष्ट्र	राज्यपाल - सी. पी. राधाकृष्णन मुख्यमंत्री - देवेंद्र फडणवीस राजधानी - मुंबई
24	ओडिशा	राज्यपाल - हरि बाबू कंभमपति सीएम - मोहन चरण माझी राजधानी-भुवनेश्वर
25	कर्नाटक	राज्यपाल - थावर चंद गेहलोत सीएम - सिद्धारमैया राजधानी - बेंगलुरु